The House reassembled at two minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

SHORT DURATION DISCUSSION

Farmers' distress leading to rise in incidents of their suicide in country

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Short Duration Discussion on the farmers' distress leading to rise in the incidents of their suicide in the country. Shri Digvijaya Singh to initiate.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, यह देश इस वर्ष को चम्पारण के आन्दोलन का 'शताब्दी वर्ष' मना रहा है। उस समय महात्मा गांधी जी ने नील की खेती करने वाले चम्पारण के किसानों के पक्ष में तथा ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी एवं आन्दोलन किया था। 100 साल के बाद, आज देश में जो परिस्थितियां हैं और आज भी किस प्रकार से सरकार अपनी मौजूदा सरकारी नीतियों के माध्यम से किसानों का शोषण कर रही है, वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी सज्जन व्यक्ति हैं। ये बार-बार यही कहते हैं कि पहली बार इस सरकार ने यह किया है, लकिन चम्पारण के 100वें वर्ष के आयोजन में हमें उनसे उम्मीद थी कि वे किसानों की बात करेंगे, परन्तु हमें पता लगा कि वहां वे योगासन के कैम्प में भाग लेने गए थे।

महोदय, मंत्री जी द्वारा जिस समय योगासन में भाग लिया जा रहा था, उसी समय मध्य प्रदेश की पिपलिया मंडी में, मध्य प्रदेश की सरकार बर्बरता से किसानों के खिलाफ गोलीबारी कर रही थी और यह भी अजीब बात है कि मध्य प्रदेश सरकार यह पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार गोली किसने चलाई और गोली किस के आदेश से चली? गोली चलाने के लिए जो operating procedures हैं, वे भी नहीं अपनाए गए कि किस प्रकार से पहले crowd control के कुछ जो निश्चित तरीके हैं, उन्हें भी नहीं अपनाया गया। मध्य प्रदेश की पिपलिया मंडी मे जब गोली चल रही थी, तब चम्पारण में एक योगासान कैम्प चल रहा था। माननीय, आज के समय में सही पूछिए तो खेती-बाड़ी, किसानी घाटे का सौदा है। एक समय जहाँ हमारे देश के जीडीपी में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान कृषि क्षेत्र से आता था, अब वह घट कर 16-17 प्रतिशत रह गया है, लेकिन जितने लोग कृषि पर निर्भर थे, वह संख्या आज भी लगभग वही है। तो स्वाभाविक है कि इस देश में खेती-किसानी का जो धंधा है, वह viable नहीं है और उसी के कारण आमतौर पर किसान अपने बच्चों को खेती-किसानी से हटकर दूसरे कामों में लगाते हैं। देश के किसान जो आज अपनी फसल बेचते हैं, जो consumer pay करता है, वह लगभग 40 से 50 प्रतिशत होता है, जबकि developed countries में यह लगभग 80 से 82 प्रतिशत होता है।

[श्री दिग्विजय सिंह]

सर, इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े वादे किए गए। भाजपा कहती है कि सन् 2022 तक -- 2019 तक इनका टर्म है। इनको उम्मीद है कि 2019 से 2024 में इनको एक सरकार बनाने का मौका फिर मिल जाएगा। इसलिए बड़ी चतुराई से उन्होंने 2022 तक अपना एक टारगेट रखा है कि वे किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। कैसे करेंगे? जिस प्रकार की नीतियां बनायी हैं, वे तो किसान विरोधी हैं, यह मैं आपको बताऊँगा। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के बारे में इन्होंने कहा था, चुनावी सभा में प्रधान मंत्री जी के भाषण हैं कि हम उसे लागू करेंगे, लागत की डेढ़ गुनी कीमत हम किसानों को देंगे। आपने अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए Minimum Support Price के बारे में रमेश चन्द्र जी की अध्यक्षता में 2015 में एक कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है। डेढ़ साल से यह रिपोर्ट आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।

आज हालात क्या हैं? यह National Crime Records Bureau की report है, जिसके अनुसार 2014-2015 में आत्महत्या के मामलों में 42 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय में असंवेदनशील है। यदि आप देखें कि किस प्रकार से, कौन-सी नीतियों के कारण आज यह स्थिति बनी है, तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जान-बूझ कर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी में जो राज्य सरकारें बोनस दिया करती थीं, उस पर कहा कि अगर कोई राज्य सरकार बोनस देगी, वहाँ पर हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहाँ पर हम लोगों ने अपने समय में एक बोनस देना प्रारम्भ किया था, इन्होंने कहा - नहीं, जो राज्य सरकार बोनस देगी, हम वहाँ प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए 2015-2016 का प्रोक्योरमेंट, जहाँ कि बम्पर क्रॉप थी, उसका आप देखें, तो प्रोक्योरमेंट घट कर 23 मिलियन टन हो गया, जबकि सामान्य तौर पर 28 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट किया जाता था। उस बहाने उन्होंने कहा कि scarcity हो सकती है और scarcity होने पर हमें import करना पड़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे बड़ा स्कैम यदि आज हमें कृषि क्षेत्र में नज़र आता है, बाबू साहब आपकी गलती नहीं है, वह तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इस बात को देखती है। जब प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है, आपके assessment हैं, मानसून अच्छा है, उस समय आप गेहूँ की इम्पोर्ट ड्यूटी 25 परसेंट से घटा कर 10 परसेंट करते हैं और 10 परसेंट से फिर ज़ीरो परसेंट कर देते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर गेहूँ, जिसको हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसको इम्पोर्ट करने की क्या जरूरत थी? दिसम्बर में आपने ज़ीरो परसेंट किया और उसके बाद फिर मार्च में जब इम्पोर्ट हो गया, जब फसल आने लगी, तब आपने वापस 10% कर दिया। इम्पोर्टेड गेहूँ की आज कीमत 1,300-1,350 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि आपकी Minimum Support Price 1,625 रुपए प्रति क्विंटल है। उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि import and export policy of agricultural produce is a very relevant subject to the interest of the farmers. हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि food grains में हमारा इम्पोर्ट 2014-15 में जो केवल 134 करोड़ रुपए का था, वह 2016-17 में बढ़ कर 9,009 करोड़ रुपए का हो गया, an increase of 6623 per cent, जबकि food

grains की availability में कहीं shortage नहीं थी। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे, तो भारत सरकार का इम्पोर्ट का बजट जो 2010-2011 में 56 हजार करोड़ रुपए का हुआ करता था, वह अब 2015-16 में बढ़ कर 1,40,268 करोड़ रुपए का हो गया है। इसका मतलब यह है कि आप विदेशों से सस्ता अनाज मंगाइए, सस्ती कृषि उपज मंगाइए और यह स्वाभाविक है कि जब विदेशों से सस्ते में इम्पोर्ट होगा, तो इससे सबसे पहले नुकसान हमारे किसानों को होगा। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में ठीक कहा है, 'Importing agriculture produce from outside is like outsourcing the interest of the farmers to the foreign countries.' उन्होंने यह भी कहा है, 'Import of agriculture crops leads to unemployment in the country.' सर, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का वे वादा करते थे, कम से कम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के मसले पर तो वे ध्यान दें। इसी प्रकार उन्होंने एक्सपोर्ट की नीति को नियंत्रित कर दिया, जिसकी वजह से 2014-15 में एक्सपोर्ट 1.31 लाख करोड़ रुपए का था, वह 2015-16 में घट कर 1.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब आप देख लीजिए कि foodgrains का जो import volume था, वह 2014 और 2017 के बीच में 110 गुना हो गया।

इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि imported fruits, जो 2014-15 में 5,400 करोड़ रुपए का था, वह बढ़ कर 5,897 करोड़ रुपए का हो गया। इस देश में किसानों की आत्महत्या और किसानों में असंतोष का जो एक बहुत बड़ा कारण है, वह आपकी इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी है। सर, मैं आपके माध्यम से कॉमर्स मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने अभी जो रमेश चन्द कमेटी बनाई है, उसने आपको सिफारिश की है कि जो कमिशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करता है, उसका स्कोप बढ़ाया जाए। उस कमिशन के स्कोप को बढ़ाते हुए उसको यह जवाबदेही सौंपनी चाहिए कि जब कभी भी केन्द्र सरकार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की पॉलिसी बनाती है, तो कम से कम उस कमिशन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं तो यह अनुरोध करूँगा कि आपकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी के अंदर आपको कम से कम मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी उसमें रखना चाहिए और विशेषकर उनको, जो कृषि से जुड़े हुए हैं।

सर, इस साल दलहन की पैदावार लगभग दुगुनी हो गई है। चूंकि पिछली बार दलहन के भाव अच्छे थे, किसान तो इस मामले में होशियार होता ही है, इसलिए उसने जैसे ही देखा कि दलहन के भाव अच्छे मिल रहे हैं, उसने अपना एरिया बढ़ा दिया। जिसकी वजह से pulses की लगभग दुगुनी फसल आई है। Pulses की दुगुनी फसल आई है, लेकिन आपने उसमें जीरो परसेंट इम्पोर्ट-ड्यूटी कर दी है। इसकी वजह से मोज़ाम्बिक, म्यांमार तथा अन्य देशों से सस्ती दाल आने लगी। आपने अभी अरहर दाल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, उसको बढ़ा कर आपने 5,400 रुपए प्रति क्विंटल किया है, लेकिन बाजार में तुअर दाल 3,400 से 3,600 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा में नहीं खरीदी जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन किसी का सही तरीके से होता है, तो वह गेहूं और धान का होता है। उसमें भी जितनी पैदावार है, उसका केवल 25 से 30 प्रतिशत ही आप खरीद पाते हैं, बाकी आप नहीं खरीद पाते हैं। बाकी के लिए किसान व्यापारियों पर निर्भर रहता है। दलहन की खरीद FCI नहीं करती है, NAFED करती है। दूसरी तरफ, लगभग 8 से 10 प्रतिशत दलहन भी NAFED नहीं खरीदती और उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। व्यापारी

[श्री दिग्विजय सिंह]

आपके अधिकारियों से मिलकर, जो किसान का अनाज आता है, दलहन आता है, तिलहन आता है, उसे reject करा देते हैं और शाम को वही अनाज किसान के नाम से खरीदकर, व्यापारी दूसरे दिन मुनाफा कमा लेता है। अनाज की खरीद में FCI and NAFED भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है।

एक ज़माना वह था, जब पूरे देश में कहा जाता था कि जिस तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, यहां के किसान उतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी के समय Green Revolution आया, उसके कारण 1964 में जो हमारे foodgrains का production केवल 10 मिलियन टन था, 1970 में वही बढ़कर 20 मिलियन टन हो गया, जो अब 95 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो इसका पहला बिन्दु था - export and import duty - अगर कभी भी आपका निर्णय होता है, तो इस मामले में Commerce Ministry का कृषि मंत्रालय से पूछना आवश्यक है। खाद्य मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि सुनियोजित ढंग से काम हो सके।

उपसभापति महोदय, जैसे कहा जाता है - 'कंगाली में आटा गीला' - जहां किसानों को भाव नहीं मिल रहा था, उसी समय देश में नोटबंदी हुई। नोटबंदी कब हुई, जब 2016 की खरीफ फसल की पैदावार मार्केट में आ रही थी। वही समय शादी वगैरह का होता है। आप जानते हैं कि किसानों की 95 प्रतिशत खरीद-फरोख्त कैश में होती है। जब बाजार से कैश गायब हो गया, तब आप समझ सकते हैं कि किसानों को किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा। व्यापारी उनसे कहते थे कि अगर नकद दाम चाहिए तो 200-300 रुपए कम भाव पर पैसा ले जा और अगर पूरी रकम चाहता है तो चैक ले जा। अब चैक लेकर किसान कहां-कहां घूमेगा? जन-धन योजना का आपने ढिंढोरा पीटा था। अगर 6 महीने account operate नहीं हुआ तो चैक को revive करने में समय लग जाता है। इसलिए इसके पीछे दूसरा बहुत बड़ा कारण नोटबंदी का रहा है, जिससे किसान परेशान हुआ है।

तीसरे, माननीय उपसभापति महोदय, अभी तक पूरे देश में गौपालकों के जो पशु unviable हो जाते थे, उन्हें वे बाजार में जाकर बेच देते हैं। हम सब गौमाता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, हमारी कांग्रेस पार्टी पहले से इसकी समर्थक रही है, लेकिन यह राज्य का निर्णय है। इस मामले को राज्यों पर विचार के लिए छोड़ा जाना चाहिए। आपने यहां से तुगलकी आदेश निकालकर नियम इतने कठोर बना दिए, जिससे किसानों को बेहद परेशानी हो गई। अब वे अपने unviable पशुओं को बाजार में भी नहीं बेच सकते हैं। वीर सावरकर जी, जिनका आप हमेशा ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं गौ-हत्या पर प्रतिबंध के विरोध में हूं। गौ-हत्या पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे किसान की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, उसे दिक्कत आएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि crop insurance या फसल बीमा योजना के बारे में मंत्री जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगर इससे लाभ हुआ है तो insurance companies को हुआ है, किसानों को लाभ नहीं हुआ है। आप यदि 2016 की gross premium collected figures देखें, तो वह 15,981 करोड़ रुपए थी, और claim approved 5,962

करोड़ रुपए था। इससे पता चलता है कि लगभग 10 हजार करोड़ रुपए केवल 2016 में बीमा कम्पनियों को लाभ हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, इनका समझौता भी बड़ा अजीब है। यदि कंपनी को नुकसान होगा, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, लेकिन अगर मुनाफा होगा, तो उसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा। उसमें भी claim decided in favour of farmers is 5,962 crores, but claim paid is only Rs.1,934 crore. It means that only 32 per cent claim approved by the companies have been paid by the insurance companies. आपने यह जो एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला लिया है, शुद्ध रूप से बाबू साहब, आप जो कहते रहे हैं कि हमने फसल बीमा में यह कह दिया, प्रधान मंत्री ने यह कर दिया, यह केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए है। आपने कह दिया, हमने किसान का दो परसेंट ही प्रीमियम रखा है, लेकिन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का प्रीमियम आपने काफी बढ़ा दिया है। उसमें भी आपने जो टर्म्स तय की हैं, उनमें आपने indemnity level low रखा है और साथ ही, आपने उसमें threshold limit भी इतनी कम रखी है कि सामान्य तौर पर किसान को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपने फसल बीमा योजना का जो ढिंढोरा पीटा है, उसमें भी आप बहुत सफल नहीं हुए हैं।

इसके साथ-साथ, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आपने उसके अंदर कोई Grievance Redressal Mechanism भी नहीं बनाया है। इसके अलावा, आप जो scale of finance तय करते हैं, वह भी इतना low है कि उसकी फसल को जितना लाभ मिलना चाहिए, वह उसकी वजह से नहीं मिल पाता है। इसी के साथ-साथ, कई बार इस बात की शिकायतें आती हैं कि आपकी जो notified crops हैं, उनमें आप बीमा देते हैं, लेकिन जो प्रीमियम है, वह आप - किसान ने लोन लिया, आपने प्रीमियम काट लिया। जो नोटिफाइड क्रॉप्स नहीं हैं, उनका प्रीमियम भी आप काट लेते हैं। जो किसान cooperative banks और commercial banks, दोनों से लोन होता है, उसकी एक क्रॉप का दोनों जगह से प्रीमियम कट जाता है। इस तरह की कई शिकायतें सामने आ रही हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि रमेश चन्द्र कमिटी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आप crop insurance की बजाय उसका price insurance कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अभी केवल 6 क्रॉप्स के लिए आप Minimum Support Price तय करते हैं और उन्होंने रिकमंड किया है कि ऐसी कम से कम 22 क्रॉप्स हैं, जिनके लिए आपको Minimum Support Price तय करना चाहिए। उन्होंने आपको methodology में भी सुझाव दिए हैं। जब आप किसी भी agricultual crop का Minimum Support Price तय करते हैं, तो वह आपको उसकी sowing के कम से कम तीन महीने पहले अनाउंस करना चाहिए, ताकि किसान को मालूम रहे कि मैं जो फसल बो रहा हूँ और जब मेरी पैदावार आएगी, तो उसका न्यूनतम मूल्य इतना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रमेश चन्द्र कमिटी आप ही ने बनाई है। आप स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन Minimum Support Price के लिए आपकी जो रमेश चन्द्र कमिटी बनी है, उसकी सिफारिशों को आप कम से कम लागू कर दीजिए। उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि यदि आपने Minimum Supprot Price 1,000 रुपए तय कर दी, उसमें अगर आप खरीद नहीं कर पा रहे हैं और एक Average Minimum Price, यानी किसान ने जिस मूल्य पर उसे बेचा, वह 800 रुपए है, तो उसमें सरकार को

[श्री दिग्विजय सिंह]

200 रुपये की सब्सिडी देनी चाहिए, जिसको वे Deficiency Price Payment, यानी Price insurance कहते हैं। मैं समझता हूँ कि क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा किसानों को तब मिलेगा, जब उसकी फसल खराब होगी। जब फसल बम्पर आई हुई है, बम्पर क्रॉप है, तो उस समय आप यदि उसके Minimum Support Price operation को सख्ती से लागू करें और लागू करने के बाद, उसको जो घाटा हो रहा है, उसको आप incentivize करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि किसानों को निश्चित तौर पर लाभ होगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि the Commission for Agricultural Costs and Prices को the Commission for Agricultural Costs, Prices and Policies कर देना चाहिए।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ समस्याएँ हैं, वहीं दूसरी तरफ उन समस्याओं का सॉल्यूशन भी हम लोगों को देखना चाहिए। आखिर, इस देश के किसानों की जो समस्या है, वह अपने आप में सबके सामने है, लेकिन समस्याओं का निदान भी हमें इस सदन के माध्यम से बताना आवश्यक है। जैसा मैंने आपसे कहा है, क्रॉप इंश्योरेंस के बजाय प्राइस इश्योरेंस को महत्व देना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन पूरे देश में सख्ती से अब लागू होना चाहिए और आज जो हमारी पर-कैपिटा होल्डिंग्स हैं, वे धीरे-धीरे कम होती चली जा रही हैं। कैसे हम छोटी होल्डिंग को और अधिक उत्पादक बनाएं, इस पर अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। Encourage integrated farming; Give price insurance. जैसा मैंने आपसे कहा है, जो सबसे जरूरी आज मांग किसानों की है कर्जा माफी की ...**(समय की घंटी)**... I will take five minutes more.

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): कर्जा माफ हो गया।

श्री दिग्विजय सिंह: आपने कर दिया होगा। आपके महाराष्ट्र में ...**(व्यवधान)**... राउत साहब, आप शायद उद्धव ठाकरे जी से चर्चा आजकल नहीं कर रहे हैं।

श्री नरेश गुजराल (पंजाब): पंजाब में भी हो गया।

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, मेरा आपसे कहना यह है कि कर्जा माफी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कर्जा न पटाऊं। लेकिन इस देश की व्यवस्था को हम लोगों ने इसमें कॉमर्शियल बैंक की एन्ट्री से बिगाड़ दिया। इस देश मे कोऑपरेटिव बैंक का एक बड़ा मजबूत नेटवर्क था, जहां गांव-गांव में उनके गोडाउन थे, समय पर उनको फर्टिलाइजर और बीज भी समय पर मिल जाता था और उसका पेमेंट हो जाता था। लेकिन हमने कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम को पूरा बिगाड़ दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कर्जा माफ करें, दोनों का करें, लेकिन कॉमर्शियल बैंक का नहीं कर सकते तो कम से कम आप कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे पूरे माफ करिए और एक बार फिर से कोऑपरेटिव मूवमेंट को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। Sir, I must also put on record and mention about the farmers' agitation in Tamil Nadu. Two days earlier, I had made a point that the promises

made by the Chief Minister of Tamil Nadu should be fulfilled. So, I came to know that the Tamil Nadu Government has written off all the cooperative loans and now, they are again demanding loan write-off from the Government of India. Sir, I would urge upon the hon. Minister to speak out in favour of the farmers of this country so that the loan write-off can take place.

Sir, at the same time, सबसे ज्यादा आज जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उसके दो-तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो कर्ज़ा है और कर्ज़ा भी इसलिए है क्योंकि agricultural credit system choke हो चुका है और अब वह व्यापारियों के चंगुल में आ चुका है। साहूकार से कर्जा ले रहा है। 18 से 24 प्रतिशत ब्याज पर कर्जा ले रहा है और जब नहीं पटा पा रहा है तो फिर उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकांश किसानों को अब cash credit limit मिल जाती है, जिससे वह खाद, बीज खरीदने के बजाय कहीं मोटर साइकिल, गाड़ी खरीद रहा है और इसीलिए आज किसान जो खाद और बीज खरीद रहा है, वह खाद, बीज व्यापारियों के माध्यम से खरीद रहा है और व्यापारी उसको काइंड में दे रहा है और 18 से 24 और 30-30, 32-32 परसेंट ब्याज ले रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको cleanup करने की आवश्यकता है और loan write-off की आवश्यकता है।

मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरा कारण है कि गिरता हुआ जल स्तर, Over-exploitation of groundwater is one of the major reasons of farmers' distress in this country. और इसलिए बड़े दिनों से इसकी बात होती थी। बड़ी आसानी से ground water recharge किया जा सकता है। जो known aquifers हैं, identified aquifers हैं, उसमें surface runoff डालिए, अपने आप रिचार्ज होगा और बिना रीचार्ज किए आपका ग्राउंड वाटर आगे काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हमारा जो स्टोरेज में वेस्ट हो रहा है, अधिकांश स्टोरेज की जो हमारी व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। Eight to ten per cent of our total crop is wasted in poor storage. हम लोगों ने cold chain बनाने का तय किया था, FDI in retail में हमने कहा था, लेकिन उस समय हमने विरोध किया, शायद अब आप उसको सही रास्ते पर आकर, कोल्ड चेन की आवश्यकता है। Perishable fruits and vegetables के लिए कोल्ड चेन की आवश्यकता है। ...**(व्यवधान)**... जी, एजेंडा तो पूरा हमारा ही चल रहा है, केवल उसकी marketing हो रही है, packaging कर रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं तो organic farming का पक्षधर हूं। Sustainable agriculture तो organic farming के माध्यम से ही हो सकता है, हालांकि थोड़ा-बहुत production कम होगा, लेकिन मेरा यह अनुभव है, मध्य प्रदेश के कई गांवों में हमने organic farming की, जिसमें वे बैंक से एक पैसा कर्ज़ा नहीं लेते थे और आसानी से अपना परिवार चलाते थे। इसलिए I strongly advocate the practice of sustainable agriculture, which is only organic agriculture.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय उपसभापति महोदय, इस सरकार ने हमें... माननीय बाबू साहब हमारी बात सुन तो रहे हैं, मंत्री जी सुन तो रहे हैं, लेकिन बाबू साहब, आपसे हमें इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल अधिकारविहीन है। Minimum Government is PMO. उसके बाद न आगे

[श्री दिग्विजय सिंह]

कोई है, न पीछे कोई है और माननीय प्रधान मंत्री का तो नज़रिया है, "मेरी मर्ज़ी", मैं जब चाहूंगा, demonetisation कर दूंगा, जब मन में आएगा, मैं यह कर दूंगा - "मेरी मर्ज़ी"। यह सरकार केवल चल रही है - "मेरी मर्ज़ी" से। इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, हमें आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन किसानों की लड़ाई, जो हम लोग इस मोहल्ले में बैठे हुए हैं, हमें यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर किसानों का भला हो सकता है, धन्यवाद।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से आज़ादी के बाद जितने भी किसानों की किसी भी घटना में, किसी भी regime में हत्या हुई हो या आत्महत्या हुई हो, उन सारे परिवारों को, जिनकी संख्या लाखों में है, मैं जब यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो एक किसान के बेटे के नाते मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी असीम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय दिग्विजय सिंह जी दस साल तक हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। उन्होंने यहां पर बहुत सारी बातें गिनायी हैं और उन्होंने सीधे-सीधे कहा है कि "मेरी मर्ज़ी"। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी, मर्ज़ी तो अब उन्हीं की चलेगी, जिन्हें जनादेश मिला है और आपकी हठधर्मिता यह है कि आप अपनी मर्ज़ी थोपना चाहते हैं और जनादेश नहीं मान रहे हैं - आपके दिल में उथल-पुथल चल रही है कि यह क्या हो रहा है? आज भी जब शपथ समारोह हो रहा था * देश के जनादेश का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है - न मुझे है न आपको है। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: और न मोदी जी को है।

श्री प्रभात झा: मेरी सरकार, इस देश की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, मैं नरेन्द्र मोदी जी के वाक्य से ही शुरू करता हूं। किसानों और गांवों की स्थिति में बदलाव लाना भारत सरकार की प्राथमिकता है। परम्परागत कृषि के साथ आधुनिक तकनीक का ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**... एक मिनट।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): यह जो आपने Central Hall का जिक्र किया, जब नए राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे, * सब प्रसन्न थे। यह चीज़ आप यहां से मत कहिए।

श्री नरेश अग्रवाल: उसे निकलवा दीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: लोगों को यह ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा: अच्छी बात है। मैं अपनी बात का समर्थन करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): वे पार्टी के राष्ट्रपति नहीं हैं, देश के राष्ट्रपति हैं। उनका सम्मान करना चाहिए।

श्री प्रभात झा: मैं समझ गया

*Expunged as ordered by the Chair.

प्रो. राम गोपाल यादवः सबको प्रसन्नता है, वे यहां हमारे साथी रहे हैं, दस-बारह साल यहां रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश (कर्णाटक): पं. जवाहरलाल नेहरू को भूल ही गए।

श्री प्रभात झाः मुझे खुशी है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवालः वह लाइन निकलवा दीजिए। ...**(व्यवधान)**... वह लाइन निकलवा दीजिए।

श्री उपसभापतिः Yes. निकलेगी। That is expunged. *...(Interruptions)...* That is expunged.

श्री प्रभात झाः मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि वे देश के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर बनायी जाएगी। Digital India का फायदा किसानों को दिलवाने के लिए अनेक कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहला काम प्रधान मंत्री ने किया है कि उन्होंने सबसे पहले कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान मंत्रालय कर दिया। हमारी सरकार की मंशा इसी से जाहिर होती है। ...**(व्यवधान)**... मैं उम्मीद भी यही करता हूं। सच सुनने की ताकत होनी चाहिए, ज़रा सच को सुनिये। जब आपने मंदसौर गोली कांड की बात कही, तो आप सब को सुनकर आश्चर्य होगा कि जब हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री स्वयं दिग्विजय सिंह जी थे, 12 जनवरी, 1998 को 24 किसानों को गोली से मारने का काम किसके मुख्य मंत्री काल में हुआ था, हम यह जानना चाहते हैं? आप थे मुख्य मंत्री। आपने उनको कोई जानबूझ कर नहीं मारा था या शिवराज सिंह जी ने कोई जान-बूझ कर नहीं मारा था। ऐसी घटनाओं को राजनीति रंग देना, कोई मुख्य मंत्री इतना क्रूर या प्रधान मंत्री नहीं हो सकता, जो किसानों की हत्या करे और इसलिए मैं दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा.. उस समय हम लोग थे, विपक्ष में थे, आप मुख्य मंत्री थे, तो हमने कभी नहीं कहा कि आपने मारा। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने जान-बूझ कर मारा है। जबकि भारत में यदि कोई पहला राज्य है, आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही - सबसे पहला राज्य है जिसने स्वामीनाथन रिपोर्ट से दो कदम आगे, मैं एक-एक चीज़ पर आऊंगा, अपने निर्णय लिए हैं। हम खाली रिपोर्ट का हवाला देकर बात नहीं करते, मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा की एक-एक लाइन पढ़ूंगा और हमारी सरकार द्वारा किए गए तुलनात्मक कार्यों को बताऊंगा। सोइल हैल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना, ई-नाम, जैविक खेती, नीम कोटिंग इत्यादि हमने कभी नहीं सुने थे। इन तीन सालों में यूरिया को लेकर कहीं दंगा-फसाद नहीं हुआ है। कुछ तो अच्छा कहिए कि इस सरकार ने किया है, मैं कभी-कभी सोचता हूं कि तीन साल हो गए, क्या हमने एक भी काम अच्छा नहीं किया। जनता के बीच में कहिए, तो जनता जवाब देती है और फिर आपको जनता जवाब देगी, लेकिन जवाब के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं हैं।

प्रधान मंत्री सिंचाई योजना और पशुधन योजना कृषि को किसानों के लिए एक लाभप्रद व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए अहम योजनाएं हैं। पिछले तीन साल में फसलों का record उत्पादन हुआ है। वर्ष 2016-17 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस साल बम्पर फसल हुई है, record 241.98 मिलियन टन अनाज के उत्पादन का अनुमान है, जिसमें चावल का 108.86 मिलियन टन और गेहूं का 96.64 मिलियन टन उत्पादन है, यह record उत्पादन हुआ है। मोटे अनाजों का भी ज्यादा उत्पादन

[श्री प्रभात झा]

हुआ है। मुझे अच्छा लगा, जब आपने कहा - माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि दलहन की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। जरा सी दाल की कीमत बढ़ गई थी, तो नाक में दम हो गया। अब किसान ने दलहन पैदा की है और आपने देखा होगा कि उसके समर्थन मूल्य में भी भारत सरकार किसानों कि हित के लिए सबसे आगे आई है। पिछले सालों में दालों के उत्पादन में कमी हुई थी, जिससे दालों का आयात करना पड़ा था, लेकिन इस साल record उत्पादन 22.14 मिलियन टन उत्पादन हुआ है और तिलहनों का भी record उत्पादन 33.60 मिलियन टन हुआ है। माननीय दिग्विजय सिंह जी आपने समर्थन मूल्य के बारे में कहा है। मैं बताना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य में भी वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में किसानों की आय को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी कीगईहै,जोपहलेकभीनहींकीगईथी।वर्ष2016-17कीखरीदफसलकीदालमेंअरहरकेसमर्थन
मूल्य को 4,625 रुपये से बढ़ाकर 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। उड़द के मूल्य को 4,625 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग के मूल्य को 4,850 रुपए से बढ़ाकर 5,250 रुपए कर दिया गया है। यह क्या किसानों के हित में लिए गए निर्णय नहीं हैं? इतना ही नहीं, आप जरा "किसान चैनल" को देखिए, जो मोदी के विज़न से निकला, "किसान चैनल" आज किसानों की जानकारी के लिए नई-नई चीज़ें दे रहा है। आप नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूं। देश की आत्मा को समझने की शुरुआत भारत के गांव, देहात से होती है। आपने 70 साल तक खाली "'कृषि प्रधान देश" कहा, लाल किले की प्राचीर से अगर "कृषि प्रधान देश" में कृषि की यह हालत है, तो मैं जानना चाहता हूं, निवेदन से, विनम्रता से कि इस देश में शासन किसने सर्वाधिक किया? कौन है इसका जिम्मेदार? हमसे आप तीन साल में सवाल पूछ रहे हैं और अटल जी के छह साल में फसल बीमा योजना आई थी और क्रेडिट कार्ड योजना को कौन लाया था? आपने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। अगर इस देश के किसानोंकीदयनीयहालतकेलिएसबसेबड़ाकोईजिम्मेदारहै,तोइसदेशमेंसर्वाधिकवर्षोंतकजो
सत्ता में रहे हैं, वे जिम्मेदार हैं। इसी आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मंत्र दिया था कि हर खेत को पानी। हमारी सरकार इस मूल मंत्र पर चल रही है, 'हर खेत को पानी, हर हाथ को काम'। और इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हल के पीछे चल रहे आदमी की सुध ली, जो माटी पुत्र है, जो हमें अन्न देता है, उसकी सुध ली। हम उन्हें "अन्नदाता" कहते हैं, लेकिनउनकीतकदीरबदलनेकेजितनेफैसलेइन3सालोंमेंहुएहैं,आपके60सालकेराज्यमेंकभी
नहीं हुए। 26 मई, 2015 को शुरू किया गया 24 घंटे का किसान चैनल, किसानों में नई जाग्रति पैदा कर रहा है। महोदय, इतना ही नहीं, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसानों की भलाई के लिए नई फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। आपने भी "फसल बीमा योजना" लागू की थी, हमने उसमें एक शब्द जोड़ा, "नई फसल बीमा योजना" और जो किसान इस "नई फसल बीमा योजना" से जुड़ गए हैं, उन्हें कोई भी प्राकृतिक आपदा डरा नहीं सकती। महोदय, आज तक किसान को निर्भीक नहीं बनाया गया। पहली बार खलिहान में खराब होने वाली फसल के लिए "फसल बीमा" की बात अगर किसी ने की, तो वह भारत सरकार के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कृषि मंत्रालय ने की। आप फसल बीमा देते वक्त उसमें से कर्जा काट लेते थे, अब फसल बीमा का पैसा किसान के कर्जे से नहीं काटा जाता है।

महोदय, हम किसानों के हितैषी कैसे हैं, इस बारे में कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। भारत में आपने भी अनेक राज्यों में राज किया है, लेकिन मैं उस राज्य का नाम जानना चाहता हूं, जो जीरो परसेंट ब्याज पर किसानों को पैसा देता हो। वे राज्य हैं, भा.ज.पा. शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दूसरे, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप 1 लाख रुपए कर्ज देते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश सरकार को सिर्फ 90 हजार रुपए वापस करने हैं। उसे 10 हजार तत्काल वापस दिए जाएंगे। यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। महोदय, किसान ने बम्पर प्याज पैदा किया, लेकिन वह सड़ रहा था। वह उसे फेंकने जा रहा था, तब किसान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने फैसला किया और मध्य प्रदेश में प्याज को 8 रुपए किलो में खरीदा। अब हम किसान हितैषी हैं या आप, यह आपको तय करना है। प्याज भंडारण के लिए जगह नहीं थी, मुख्य मंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि प्याज़ सड़ेगा, लेकिन किसान को मरने नहीं देंगे। अगर किसान जिंदा रहेगा तो फिर से प्याज व अलग फसल उगाएगा, लेकिन उसे मरने नहीं देंगे। महोदय, मूंग 5,225 रुपए प्रति क्विंटल एवं उड़द 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमारी सरकार ने वहां खरीदी है। किसानों को 50 फीसदी नगद एवं शेष RTGS/NEFT के द्वारा प्रति दिन भुगतान किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा 1,000 करोड़ की लागत से भारत के किसी राज्य ने नहीं किया है, लेकिन भा.ज.पा. शासित राज्य ने निर्णय लिया है कि मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जाएगा। आपने कहा कि किसान की लागत कितनी होगी? महोदय, अगर किसान को घाटा होता है, तो इस मूल्य स्थिरीकरण कोष से उसकी भरपायी करेंगे। हमने यह भी फैसला किया है कि वह जो फसल पैदा करेगा, उस पर उसका कितना खर्च हुआ, यह अध्ययन भी वहां पर किया जायेगा और यह घोषणा की गयी है कि किसानों को घाटा नहीं, किसान को फायदे में खरीद कर देंगे, चाहे हमारी सरकार को अपनी ओर से कुछ भी करना पड़े। ...**(व्यवधान)**...

आपने कर्ज़ माफी की बात की। हमारे महाराष्ट्र में यह हुआ, यू.पी. में हुआ, मध्य प्रदेश में ...**(व्यवधान)**... आप मेरे बाद अपनी बात कह दीजिए। मध्य प्रदेश भारत का भा.ज.पा. शासित राष्ट्र है, वहां के किसान कितने दमदार हुए हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां कि किसानों ने कहा है कि हम 78 फीसदी किसान कर्ज़ चुकाते हैं, हम कर्ज़ माफी नहीं चाहते। वहां किसानों से मुख्य मंत्री ने पूछा कि आप फसल की लागत चाहते हैं या कर्ज माफी? तो सारे किसानों ने शाजापुर में हाथ उठाकर कहा कि हमें उचित दाम चाहिए, कर्ज माफी नहीं। हम किसी की दया पर जिंदा नहीं रहना चाहते। आप सुनकर आश्चर्य करोगे कि कितना कर्ज होगा, 11 हजार करोड़, 12 हजार करोड़! आपको मालूम है कि भाजपा सरकार ने मुआवजे के नाम पर एक वर्ष में किसानों को कितनी राशि दी है, मध्य प्रदेश की सरकार ने 18,840 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं। आज कर्जा माफी की बात कर रहे हैं और यह जानना चाहते हो। हमे कृषि कर्मण पुरस्कार किसने दिया? जब माननीय डा. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे और कृषिं मत्री भी थे, उस समय दो बार पुरस्कार मिला। आप थोड़ी शाबासी भी तो दीजिए। आप छः दिन थप्पड़ मारते हो, एक दिन तो प्यार कर लो, झूठा ही प्यार कर लो, लेकिन कुछ तो कर लो। आप लोग कहते हैं कि हम गांधी जी के शिष्य हैं, वैसे शिष्य तो हम लोग भी उनके शिष्य हैं। गांधी जी कहते थे कि "कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे, तो दूसरा आगे कर दो", लेकिन यहां तो मारने ही नहीं देते और यदि मारते हैं, तो दोनों गाल ही तोड़ देते हैं। आप यह मत करिए। मेरा सदन से एक ही निवेदन है कि अगर अच्छी बात होती है, तो उसे कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए।

[श्री प्रभात झा]

आपने स्वामीनाथन की बात की, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्वामी से लेकर भूस्वामित्व तक किसानों का होना चाहिए। हमारी सरकार ने कहा है कि विकास योजनाओं या औद्योगिक विकास क्षेत्र या किसानों की भूमि जो नगरीय है, उसे जबर्दस्ती अधिकृत नहीं किया जाएगा। यह कैबिनेट का फैसला है। आप मुझे बताइए कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानी या नहीं मानी? किसानों के आबादी पट्टे दिए जाने थे, यह स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया, तो हमने वन के पट्टे दिए और हमने अन्यान्य पट्टे बांट दिए। आप बताइए कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानी या नहीं मानी? आप वनवासियों से जाकर पूछिए। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप मुख्य मंत्री थे और उस समय मैं भाजपाका काम करता था, उस समय आपने घोषणाएं की थी। आपके जमाने के पट्टे हम बांट रहे हैं और ईमानदारी से बांट रहे हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। यदि यहां किसानों की कोई हमदर्द पार्टी है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है। स्वामीनाथन आयोग द्वारा नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस बनाने की बात की गई थी, मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने इस पर अमल किया है। स्वामीनाथन आयोग द्वारा किसानों को जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा की गई थी, मध्य प्रदेश की पहली सरकार है, जिसने इन अनुशंसा के अनुसार काम किया है। इतना ही नहीं, स्वामीनाथन आयोग द्वारा किसानों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु जो भी अनुशंसा की गई थी, उसे बड़े दिल से यदि किसी ने स्वीकार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने किया है। मैं बहुत नाम गिना सकता हूं, लेकिन मैं यहां कुछ मोटी-मोटीबातें कहना चाह रहा था। आपने कहा कि क्या किया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि दूध उत्पादन में आज विश्व में पहले स्थान पर कौन है? आज दूध उत्पादन के मामले में विश्व में भारत पहले स्थान पर है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है। विश्व में 2015-16 में अगर 155 मिलियन टन दूध का उत्पादन यदि किसी ने किया है, तो वह हमारे देश भारत ने किया है। आप ऐसा मत कहिए कि कुछ नहीं हो रहा है।

फल और सब्जियों में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो उसका नाम भी भारत ही है। 254 मिलियन टन फल-सब्जियों का उत्पादन आज भारत में होता है। चावल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। मैं आपको लगातार गिनवा रहा हूं। मत्स्य उत्पादन में भी विश्व में भारत दूसरे नम्बर पर आता है। अंडों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पांचवां है, इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले सालों में नए-नऐ नीति निर्णय लिए और उनके परिणाम आशा के अनुरूप आ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट दी गई है। देश में खाद्य उत्पादों के उत्पादन और खुदरा बिक्री में भी 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट दी गई है तथा कई प्रकार के करों में भी छूट दी गई है। इन नीतियों के परिणाम हैं। जनवरी, 2017 तक देश में 42 मेगा फूड पार्कों पर विभिन्न स्तरों पर काम किया गया है, जनवरी, 2017 तक 200 से अधिक कोल्ड चेन विकसित की जा रही हैं। किसानों को हर स्तर पर सहयोग देकर मोदी सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया है।

अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि 2019 में क्या होगा? दिग्विजय सिंह जी आप तो इतने पढ़े-लिखे इंजीनियर, मुख्य मंत्री, सांसद इत्यादि क्या-क्या नहीं हैं, यदि आप गाँव के गरीब गँवार

से पूछेंगे कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी, तो वह ताली बजाते हुए, आह्लादित होकर, नाचते हुए कहेगा नरेन्द्र मोदी की सरकार। आप राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन भारत का आम नागरिक राष्ट्र नीति से जुड़ा होता है। वह देखता है, उसकी पैनी निगाह होती है। आपकी, हमारी राजनीतिक निगाह हो सकती है, लेकिन आम नागरिक की राजनीतिक निगाह पैनी नहीं होती। यह मैंने नहीं कहा, यह जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि, "अरे विरोधियों एक हो जाओ, नहीं तो क्या होगा? 2019 तो गया, 2024 भी जाएगा।" यह मैंने नहीं कहा ...**(समय की घंटी)**... इसलिए जनवरी, 2017 तक किसानों को हर स्तर पर सहयोग देकर मोदी ...**(व्यवधान)**... ...**(समय की घंटी)**... अब कितने एक हैं, वह तो अभी पता लग गया ...**(समय की घंटी)**... उपसभापति जी, दो मिनट दीजिए।

महोदय, जैविक उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत सरकार जैविक खेती के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। 2015-2018 तक 1 लाख समूहों के अंतर्गत 5 लाख एकड़ क्षेत्र को जैविक खेती के दायरे में लाने का काम चल रहा है। राज्य सरकारें अब तक 7,186 समूहों के माध्यम से 3.59 लाख एकड़ भूमि को जैविक खेती के दायरे में ला चुकी हैं। देश के उत्तरी-पूर्वी राज्यों की भौगोलिक दशा को देखते हुए जैविक खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए 2015 से 2018 तक 400 करोड़ रुपए की एक परियोजना चल रही है। 2015 से 2017 तक 143.13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जिनमें 2016-17 तक 1975 समूहों के माध्यम से 39,969 किसानों की जैविक खेती का विकास होगा। अब आप बार-बार कह रहे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अगर मैं गिनाने लगूँ तो तीन सालों में जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं, अगर हर कैबिनेट में सबसे ज्यादा इस सरकार ने फैसला लिए हैं, तो आप कैबिनेट के डिसिजन्स उठाकर देख लीजिए, वे भारत के सिर्फ 67 फीसदी किसानों के हित में लिए गए फैसले हैं। दूसरी तरफ, आप अपने दस साल के फैसले उठाकर देख लीजिए।

महोदय, मैं एक छोटी-सी बात कहूंगा, यह मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखनी है, आप देश के सर्वे को देख लीजिए, अगर वे इतने अच्छे प्रधान मंत्री नहीं हैं, तो विश्व की सर्वे रिपोर्ट में यह बात क्यों आ रही है कि यदि इस विश्व का कोई सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, तो उसका नाम है नरेन्द्र मोदी? भारत के 73 फीसदी लोगों में से 54 फीसदी किसान कहते हैं कि अगर नरेन्द्र मोदी बने रहे तो 2022 में हमारी आमदनी दुगनी कौन करेगा? नरेन्द्र मोदी। आप चिंता मत कीजिए। हमें इस देश ने जनादेश दिया है। हम उस जनादेश को फलीभूत करने के लिए एक-एक निर्णय लेंगे। पहले हमारे बारे में कहा जाता था.. बस, एक आखिरी लाइन है। हमारे बारे में कहा जाता था कि ये सरकार में आते नहीं हैं, आते हैं तो सरकार चलाते नहीं हैं, बीच में ही भाग जाते हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी, अब हम सरकार में आते भी हैं, सरकार चलाते भी हैं, दुबारा भी आते हैं ...**(व्यवधान)**... और अब आते रहेंगे ...**(व्यवधान)**... और आप वहाँ बैठते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।

प्रो. राम गोपाल यादवः उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया है। मैं अभी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और आदरणीय प्रभात झा जी को सुन रहा था। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जब प्रभात जी बोल रहे थे, तब कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मध्य प्रदेश की विधान सभा में बहस

[प्रो. राम गोपाल यादव]

चल रही है। अन्य बातों की चर्चा के बाद मैं करूंगा, लेकिन दो बातें, जिनकी चर्चा अभी-अभी प्रभात जी ने की, उन पर बोलूंगा। एक तो फसल बीमा योजना, पहले उसमें सरकारी कंपनियां थीं, जो बीमा का मुआवजा दिया करती थीं, वे 85 परसेंट तक दे दिया करती थीं, अब आपने इसे निजी कंपनियों को दे दिया और वे 15 परसेंट देती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रीमियम का कितना पैसा कंपनियों को जाता है और कितना पैसा किसानों को मिलता है, अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है? दूसरा, फूड प्रोसेसिंग का, दूध से लेकर अन्य चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया, यह सही है कि इन मामलों में भारत की स्थिति कपेरेटिवली बहुत अच्छी है, बल्कि दूध के मामले पर तो हम नंबर एक पर हैं, लेकिन जो अन्य पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनके लिए जो फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं है। यह विभाग दस-बारह साल पहले आपनके इसी मंत्रालय में था, जो बाद में अलग हो गया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग हमारे यहां दो, तीन, चार परसेंट से ज्यादा नहीं हो पाई। नतीजा इसका यह होता है कि हर साल इस देश में 50 हजार करोड़ से लेकर 60 हजार करोड़ रुपए के फल, सब्जियां, मीट सड़ जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं। कोई व्यवस्था, कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है कि हम अपने फलों को, अपने अन्य उत्पादों को बचा सकें। क्या कारण है कि जो विदेशों से आया हुआ सेब है, ज्यादा रसीला है? हम अभी खान मार्केट के सामने रहते हैं, वहां से विदेश का सेब लाएं तो बिल्कुल रसीला है और हमारे यहां का इतना बढ़िया जो सेब होता है, चाहे वह हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड में भी अच्छा सेब होने लगा है, लेकिन उसमें दो-तीन दिन बाद ही पेट्रोल और ग्लुकोज़ जैसी स्थिति हो जाती है, फिसफिसा हो जाता है। हम अभी इसमें कुछ नहीं कर पाए हैं। ये ऐसी चीजें रहेंगी, जब तक हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा फार्म आउटपुट अमेरिका के बाद हिंदुस्तान का ही है, इसके बावजूद किसान गरीब क्यों है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है?

महोदय, हम कर्ज माफी की बात करते हैं। कर्ज माफी से किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने इशारा किया था, कई बार कर्ज माफी का जो तरीका है, जो अधिकारी फार्मूला निकालते हैं, वे ऐसा बनाते हैं कि जिसने कभी कर्ज repay न किया हो, सिर्फ उसी का कर्ज माफ हो पाता है और यदि किसी ने एक किस्त भी दे दी, तो उसका कर्ज माफ नहीं होता है। इसलिए अब किसान जो कर्ज लेता है, वह यह मानने लगा है कि किसी ने किसी दिन कोई सरकार कर्जा माफ करेगी ही, इसलिए पैसा वापिस देने से कोई फायदा नहीं है, कर्ज चुकाने से कोई फायदा नहीं है। तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तभी हो सकता है, जब किसान को आप इस तरह की सहूलियतें दें, जिनकी उनको जरूरत है, जैसे नई टेक्नोलॉजी। आजादी के तत्काल बाद पंडित नेहरू जी ने कहा था - Everything can wait, but, not agriculture, लेकिन हमारे देश में अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है।

1970 में GDP में agriculture का जो हिस्सा था, वह 43 परसेंट था और अब वह 11 परसेंट के आसपास रह गया है, 12 परसेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं। हालाँकि उसका कारण यह भी है कि दूसरे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा तरक्की हुई, लेकिन GDP में इसका हिस्सा गिरा। खेती पर निर्भर रहने वाले लोग लगभग उतने ही हैं, जितने पहले थी, एक-दो परसेंट कम हो गए होंगे। इसका सीधा अर्थ हुआ कि

किसान गरीब हुआ, किसान की आर्थिक स्थिति खराब हुई। आप नई टेक्नोलॉजी भी लाए, आपने कुछ नए seeds वगैरह देने की कोशिश भी की, जैसे बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन से शुरू में तो किसानों की हालत खराब हुई, क्योंकि बीज इतना महँगा था कि लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए, लेकिन बाद में वह काम कर गया। उसका बीज कितना महँगा है! यह कम से कम चार गुणा महँगा है। जैसा मैंने कहा कि खेती पर अब भी लगभग 58 से 60 परसेंट लोग निर्भर करते हैं। आप अभी भारत सरकार की बात कर रहे थे। जब तक आप agriculture को बजट नहीं देंगे, तब तक आप कितनी ही घोषणाएँ करते रहिए, कितनी ही बातें करते रहिए, कितना ही यह कहते रहिए कि जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं, उन सबमें किसानों के लिए फैसले हुए हैं, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो पिछला बजट था, उसमें agriculture के लिए total allocation यूनियन बजट का केवल 2.3 परसेंट था। जो सेक्टर देश के 58-60 परसेंट लोगों को रोजगार देता हो, जिस पर लोग इतने बड़े पैमाने पर निर्भर हों, उसके लिए बजट दो फीसदी है और जो एक परसेंट रोजगार नहीं दे सकते हैं, उनके लिए 16 परसेंट, 17 परसेंट, 18 परसेंट, 20 परसेंट बजट है। स्थिति इतनी खराब है, कोई कितना ही कहे, हालाँकि इसके लिए केवल आप जिम्मेदार नहीं हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। कुछ दिन हम लोग भी सत्ता में रहे, कुछ ये लोग सत्ता में रहे, जो भी रहे, खेती की उपेक्षा, किसानों की उपेक्षा निरंतर हुई है। खेती और किसान कल्याण मंत्रालय नाम रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेती मायने किसान, किसान मायने खेती। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने import liberalization के बारे में कहा। प्रभात जी ने बार-बार स्वामीनाथन साहब का नाम लिया। स्वामीनाथन साहब ने ही लिखा है कि जो import liberalization हुआ है, उससे हिन्दुस्तान में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप उनको quote तो करते हैं, लेकिन उनके सुझावों पर अमल करने का प्रयास नहीं किया जाता है। मेरी उनसे हमेशा बातचीत होती थी। संयोग से जब मैं उस सदन में था और लगभग चार साल तक Agriculture Committee का चेयरमैन रहा, तो स्वामीनाथन साहब भी उस कमिटी के मेम्बर थे। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी पूरी कमिटी को उनसे सीखने को मिला, वे देश के इतने बड़े agriculture scientist थे। उन्होंने खुद कहा कि import liberalization की वजह से किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। जब हमारे यहां जरूरत पड़ती है, तो बजाय इसके कि हम अपने उत्पादकों को ज्यादा पैसा दें, बाहर से मंगाना शुरू कर देते हैं। जब हमारे यहां पैदा होता है, तब भी बाहर से मंगाते हैं। मैं यहां किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन चर्चा यही होती है कि यहां पैदा होने के बावजूद जो import किया जाता है, वह दूसरे ulterior motive से किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरे purpose से किया जाता है।

महोदय, अब इस वक्त क्या स्थिति है, मैं बताना चाहता हूं कि इस समय स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेजेज़ में आलू भरा हुआ है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, फिरोज़ाबाद और आगरा ऐसे जिले हैं, जिनमें बहत बड़े पैमाने पर आलू पैदा होता है। कोल्ड स्टोर्स से आलू निकल नहीं रहा है, क्योंकि आलू खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है और यह आशंका है कि इसके कारण इस साल किसान आत्महत्या करने के लिए विवश होंगे। इससे कोल्ड स्टोर्स के मालिकों को और किसानों को भी नुकसान होगा। किसान कोल्ड स्टोर से अपना आलू निकालने इसलिए नहीं जा रहा है, क्योंकि जितना किराया कोल्ड स्टोर का है, उससे कम पैसा उसे आलू बेचने से मिलेगा। अगर किसान कोल्ड स्टोर से अपना आलू नहीं निकालेगा, तो कोल्ड स्टोर मालिकों को कुछ नहीं मिलेगा, यानी उसे

[प्रो. राम गोपाल यादव]

किराया भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उसका भी नुकसान हुआ और किसान का तो नुकसान हो ही गया। यह हालत है।

महोदय, अभी थोड़े दिनों पहले सब्जियों की स्थिति यह हो गई थी कि यदि किसान बाजार में टमाटर ले जाता था, तो उसे ट्रैक्टर के डीजल के पैसे के बराबर भी भाव नहीं मिल पाता था। इसलिए वह अपने टमाटर को मंडी में बेचने के बजाय टमाटर से भरी अपनी ट्रॉली को सड़क पर पलट कर आ जाता था। उस टमाटर को सड़क पर ही गायें खाती थीं। लौकी और तोरई की स्थिति यह थी कि दो रुपए में जितनी चाहे लौकी और तोरई ले लो। उसकी डलिया रखी रहती थी और दो रुपए में उसमें से जितनी चाहे लौकी ले लो। एक रुपए की तोरई ले आइए, आपकी चार दिन की सब्जी बन जाएगी।

महोदय, अब जक किसान की फसल, किसान के यहां से निकल गई, तो पता चला कि टमाटर सेब से ज्यादा महंगा हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हों या कोई ओर हों, लेकिन जब-जब किसान के पास उसकी फसल की उपज आती है, तब-तब, चाहे जो भी फसल हो, उसका बुरा हाल होता है और the moment, जैसे ही वह किसान के यहां से चली जाती है, वैसे ही बाजार में उसकी स्थिति सुधर जाती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पता कीजिए कि आजादपुर मंडी, दिल्ली में यदी actual रोजाना 100 से 200 करोड़ रुपए की बिक्री होती है, तो कागज पर वह 5000 करोड़ रुपए की वायदा बाजार के कारण ही हो जाती है। एग्रीकल्चर कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने recommend किया था कि इस पर पाबन्दी लगाइए। वायदा कारोबार में केवल कागज पर लिखा-पढ़ीहोती है। इसलिए आप महंगाई को रोक ही नहीं सकते हैं। जब महंगाई बढ़ती है, तो उसका एक कारण वायदा कारोबार भी होता है, लेकिन उस पर कभी पाबन्दी नहीं लगती। उसकी वजह से जब तक फसल किसान के पास रहती है, तब तक कुछ नहीं होता, परन्तु जैसे ही फसल किसान के पास से गई, वैसे ही उसकी कीमत बढ़ी। सर, अभी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है, वह पिछले 25-30 सालों में कभी 1 परसेंट हो जाती, कभी 2 परसेंट, कभी 2.5 परसेंट,तो कभी तीन परसेंट और कभी-कभी 4 परसेंट हो गई। जब तक sustained growth rate नहीं होगा, तब तक आप इस देश की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते, किसानों की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार सकते।

किसानों को हमने दिया क्या है? कर्ज माफी की बात कर दी और तो कुछ किया नहीं। टेक्नोलॉजी में, वह ट्रेक्टर लाता है, तो खुद अपनी तरफ से लाता है, ट्यूबवेल लगाता है, तो खुद अपनी तरफ से लगाता है, खुद खाद लाता है। कई बार तो स्थिति यह होती है कि खाद या DAP उपलब्ध नहीं होती है और जब वह लेने जाता है, तो वहाँ लाइन लगती है, उसे पुलिस की लाठी और खानी पड़ती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यहाँ systemic way में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की कि कितनी खाद पड़नी चाहिए, कितना पानी दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जल-स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। यह क्यों गिर रहा है? एक तो उसको रोकने की व्यवस्था नहीं है, फिर से जमीन को रीचार्ज करने की व्यवस्था कहीं नहीं की गई और दूसरे, उसका जो दोहन है, वह बहुत ज्यादा होता है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में, ब्राज़ील या चीन की तुलना में हिन्दुस्तान का किसान 2 से लेकर 4

गुना पानी का प्रयोग करता है, जबकि उसके से ही काम चल सकता है। अगर आपने sprinkle system या drip system की technique को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया होता, तो जो पानी की समस्या है, वह हल हो सकती थी। आज भी आज़ादी के इतने लम्बे अरसे के बाद भी इस देश में 65 परसेंट जमीन असिंचित है। अगर आप उस जमीन को सिंचित बना दें, तो आबादी की बढ़ोतरी के बाद भी कभी आपको किसी भी अन्न का, किसी भी चीज़ का एक दाना तक इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए यह आशंका निर्मूल हो जायेगी कि हमारे लोगों के सामने कभी खाने की समस्या, food scarcity की समस्या हो सकती है। ...**(व्यवधान)**... अभी रुकिये, साहब।

किसान ट्रैक्टर लेता है। पानी की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो वह पम्पिंग सेट लगाता है। GST ट्रैक्टर पर 28 परसेंट और पम्पिंग सेट पर भी 28 परसेंट कर दिया गया। बड़ी-बड़ी लग्ज़री कारों पर GST कर कर दिया, लेकिन पम्पिंग सेट पर 28 परसेंट कर दिया। चौधरी बीरेन्द्र सिंह साहब, आप तो बहुत प्रतिष्ठित किसान हैं। पम्पिंग सेट पर 28 परसेंट GST और ट्रैक्टर पर 28 परसेंट GST है, तो यह कैसी किसान समर्थक सरकार है? जिस पर कोई GST नहीं होना चाहिए, उस पर GST! आपके आगे जो मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनको आप बताइएगा, क्योंकि ये हम लोगों की बात तो अभी मान नहीं सकते हैं।

आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम किसान को उसकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य देंगे। लागत के लिए जो आपने कमीशन बनाया है कि कितनी लागत आयी और उसके बाद वह MSP तय करता है। मैंने तो एक बार सब मँगवाकर देख लिया था। ये लोग देते नहीं थे, लेकिन एक बार पूरी कमेटी ज्यादा एक तरफ हुई और कहा कि आप दीजिए, वरना हम लोग इसमें नहीं रहेंगे, न कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और न ही कमेटी काम करेगी और कहा कि आप यह बताइए कि MSP की कीमत कैसे निकालते हैं? तो एक-एक चीज़ को उन्होंने बताया। उन्होंने एक-एक चीज़ को बताया कि जमीन का इतना रेंट, किसान का बच्चा काम करता है, बीवी काम करती है, वह काम करता है, बैल है, बैल का, ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर का और सीड का, pesticide का... सर, pesticide ने किसान को बरबाद कर दिया। मैं एक चीज़ भूला जा रहा था। इतना ज्यादा pesticides का यूज़ हुआ कि अभी पिछले कुछ वर्षों में एक सैम्पल सर्वे हुआ था, तो उसमें पंजाब के पुरुषों के ब्लड में जो नॉर्मल pesticide का अंश होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा था। शिमला के पास कुफरी एक जगह है, जहां पर Central Potato Research Institute है, वह नई सीड तैयार नहीं कर पा रहा है। जहां असंचित जमीन है, ऐसी जमीन, जिसमें पानी कम मिल पाता है, वहां के लिए आईसीएआर अभी तक कोई सीड तैयार नहीं कर पाई है। हम लोगों ने आईसीएआर से बार-बार कहा कि आप ऐसी रिसर्चेज़ कीजिए, आपके पास साइंटिस्ट्स हैं, आप ऐसे सीड्स तैयार कीजिए, जिनमें पानी की कम जरूरत हो और पैदावार पूरी हो। इस तरह के गेहूं और धान के सीड्स होने चाहिए। आप जो अभी विभिन्न राज्यों में कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, उसकी वजह से एक बहुत भारी दिक्कत सामने आई है। ...**(समय की घंटी)**... आप सब लोग जानते होंगे और अगर न जानते हों, तो जान लें कि इस देश में जितना रेवेन्यू गेहूं और धान से मिलता है, लगभग उतना ही रेवेन्यू मिलता है दूध और मांस से। यह जो पशुधन है, जिससे इतने बड़े पैमाने पर रेवेन्यू मिलता है, जितना पूरे देश में गेहूं और धान से मिलता है, वह इतना neglected है, जबकि यह सब किसान से जुड़ा हुआ है। अगर इसको neglect करेंगे, तो किसान कहां

[प्रो. राम गोपाल यादव]

से संपन्न हो जाएगा, गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी? देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी रीढ़ है किसान। हमारी ऐसी नीतियां हैं, कल मैंने थोड़ी-सी बात कह दी थी, मैं फिर उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दूध और मांस, इन दोनों में आप एक-दो साल के अंदर देखिएगा कि कितनी बड़ी गिरावट आ रही है। हमारे इस देश की एक मंत्री हैं, उन्होंने एक आदेश करवा दिया कि कोई जानवर को बांध नहीं सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। लोगों को यह अंदाज ही नहीं है, वे जानते नहीं हैं कि अगर गाय और भैंस को घर पर बांधेंगे नहीं, तो उसका दूध कहां से आएगा? अगर ये खुली रहेंगी, तो उसका बछड़ा, उसका पड्डा जो है, वही सारा दूध पी जाएगा। आप उसको बांध ही नहीं सकते हैं।

सर, लोगों को अपने खेत की रखवाली करने के लिए रात-रात भर खेतों पर बैठना पड़ता है। मेरे एक मित्र हैं, वे बहुत अच्छी खेती करते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Ram Gopalji, please conclude.

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। वे हमारे पास आए और बोले कि मैंने पिछली साल मूंग की खेती की थी, तो 235 क्विंटल हुई थी, उतनी ही जमीन में इस साल केवल 35 क्विंटल मूंग हुई। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? उसने खेत में तार लगा दीजिए, तो पुलिस आएगी और किसान को गिरफ्तार करके ले जाएगी क्योंकि मेनका गांधी का आदेश है। आदमी मर जाए, लेकिन कुत्ते को चोट न लग जाए, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। खान मार्केट में रोजाना कुत्ते लोगों को काट लेते हैं, वे चारों तरफ लेटे रहते हैं। हमने एक बार वहां के दुकानदारों से पूछा कि आप लोग इन कुत्तों को हटाते क्यों नहीं हैं? उन्होंने बताया कि साहब, आपके यहां एक मंत्री हैं मेनका संजय गांधी, वे हटने ही नहीं देती हैं, मुकदमा कर देती हैं। न जाने कैसे लोग हैं अनुभवहीन! मैं सब को नहीं कहता हूँ, आप सभी तो अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको आदमी से कोई मतलब नहीं, आदमी मर जाए, किसान की फसल खत्म हो जाए, लेकिन आप अपनी गाय-भैंस को भी बांध नहीं सकते, सांकल नहीं लगा सकते, रस्सी नहीं लगा सकते। यह आदेश है! तुगलकी फरमान! उसके बाद आप चाहते हैं कि देश का किसान तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। याद रखिए कि चाहे आप किसी भी सैक्टर में कितनी भी तरक्की कर लें, ...**(समय की घंटी)**... जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा, इस देश में तरक्की नहीं हो सकती। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Members, we have to complete the discussion today, and then one Bill also is to be taken. Therefore, please have some restraint. Shri K.R. Arjunan. ...*(Interruptions)*... Shri K.R. Arjunan. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवालः महोदय, no Bill today. आज सुबह यह तय हुआ था कि जब तक किसानों के विषय पर discussion पूरा नहीं हो जाता, कोई बिल नहीं लिया जाएगा। उस समय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री जी भी उपस्थित थे। ...**(व्यवधान)**...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, we would like to have one full day's discussion on kisan. *...(Interruptions)...* किसानों का विषय ऐसा है, जिस पर चर्चा के लिए पूरा दिन मिलना चाहिए। सब लोग यहां किसानों के लिए ही आए हैं। ...(व्यवधान)...

† کسانوں کا وشئے ایسا ہے، جس پر چرچہ کے لئے پورا دن ملنا چاہئے۔ سب لوگ یہاں کسانوں کے لئے آئے ہیں۔(مداخلت)۔

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): क्या वजह है कि बिल का नाम सुनते ही नरेश भाई खड़े हो जाते हैं? ...(व्यवधान)...

प्रो. राम गोपाल यादव: बिलबिला उठते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, इसके बाद बिल तो होना ही है। देर तक करेंगे। ...(व्यवधान)...

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair]*

SHRI K.R. ARJUNAN (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, with heartfelt tributes to our hon. late leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma and sincere respect to our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, I request the attention of the Chairman to allow me to highlight some issues regarding the pathetic conditions of farmers. I would like to continue my speech in Tamil.

*Hon'ble Deputy Chairman Sir,

A Great Saint Ramalinga Adigalar has said,

'I suffered whenever I saw withered crops'.

But, in today's Tamil nadu, farmers lose their lives on seeing withered crops. The number of farmers who are committing suicide is increasing day by day. Tamil Nadu is facing unprecedented drought. The Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has met Hon. Prime Minister and has requested ₹ 39,560 crore as drought relief. Similarly, financial assistance of ₹ 2500 crore was demanded by the State Government from National Calamity Contingency Fund to provide compensation to those who were affected by Vardha Cyclone last year. But the Central Government has given only ₹ 1712 crore. Drought relief has to be provided to distressed farmers of Tamil Nadu as requested by the State Government of Tamil Nadu.

†Transliteration in Urdu script.
*English version of the original speech made in Tamil.

[Shri K.R. Arjunan]

During the elections to our Legislative Assembly of Tamil Nadu in the year 2016, it was mentioned in our Party's Election Manifesto that loans given to small, marginal and medium farmers from cooperative banks will be waived off. Our Puratchithalaivi Amma had waived loans worth ₹ 5,780 crore. Tamil nadu farmers have received crop loans from Nationalised banks also. They are struggling in Delhi to get these loans waived off. Hon. Prime Minister has to immediately intervene in this matter. The loans obtained from Nationalised banks not only by Tamil Nadu farmers, but also by all farmers of the country have to be waived off.

What is the actual situation of Tamil Nadu farmers? What are the reasons of their crisis? What are the short term solutions to their problems? What are the long term measures for their welfare? I would like to point out these in detail.

In Tamil Nadu, 70 per cent of the population is engaged in agriculture in one capacity or the other. But now, farming activities have virtually come to a standstill in the State as a result of drought. The State normally receives an average annual rainfall of 921 millimetres and has a gross irrigated area of 33.94 lakh hectares, 79 percent of which is under food crops.

The average rainfall that the State receives from the north-east monsoon from October to December is around 44 centimeters. But it received only 16.83 cm in the year 2016. Of the 32 districts, 21 recorded only 40 per cent of the rainfall from the north-east monsoon. There is an ancient axiom that Chola Empire is filled with rice. The land of Thanjavur was such a land where fertile crops were dancing like children. Such a district is filled with parched fields and dried crops today.

In the three Cauvery delta districts of Thanjavur, Tiruvarur and Nagapattinam, and the Cauvery belt which includes Erode, Karur, Namakkal, Pudukottai and Tiruchi districts, all crops have dried completely. Usually, farmers cultivate the kuruvai (short terms crop) paddy crop between June and September. During this season, Karnataka has to release Cauvery water to the Mettur dam.

Tamil Nadu farmers raise another paddy crop called samba (long term crop) between September and January with the help of rains from the north-east monsoon. This is the usual situation. But this year the North East Monsoon also had failed Tamil Nadu. The Karnataka Government did not release 192 thousand million cubic feet (tmcft) of Cauvery water as per the final award of the Cauvery Water Disputes Tribunal, given on

5th February, 2007. Instead, Karnataka provided only 66.10 tmcft in 2016. This included 31.10 tmcft released after a series of Supreme Court rulings. Failure of Northwest Monsoon and lack of Cauvery water caused crop losses and acute distress. The South West monsoon which brings rains to Southern Tamil nadu, also has failed this year. The repeated failure of the monsoons resulted in crop loss and a fall in farm incomes and a bulging debt burden led the farmers to take his own life.

The Cauvery delta has missed the kuruvai paddy crop for the second consecutive year owing to low storage levels in the Mettur reservoir. Not only the paddy crop, but the yield of other crops such as black gram, sorghum, maize, onion, tomato, citrus fruits (lemon), ladies finger, chilli, cotton, turmeric and grapes has been very poor. Snake gourd, bottle gourd, ash gourd, and pumpkin creepers have wilted. Medicinal plants grown in Vedaranyam taluk in Nagapattinam district have withered. Jasmine and Marigold have failed to bloom. Farmers engaged in Green house cultivation at Coimbatore and Krishnagiri districts also have been affected. The prices of tea leaves also have fallen. Cultivation of floriculture is deeply affected in Nilgiris district. All these districts are in the grip of a drinking water famine. There is scarcity of fodder for the cattle.

Rivers, irrigation canals, channels, lakes, ponds, and tanks all over the state are bone dry. There is no water in the Cauvery, in the Coleroon and in the Cauvery's tributaries such as the Vadavaaru, Vennaru, Vetaaru, and Kudamuruti. Irrigation canals such as the Periya Vaikkal, the Kalyani Canal, the Kannanur Canal, the Kallanai Canal and the Adappar drainage canal are running dry. Every dam and reservoir, including the Mettur dam, the Vaigai dam in Madurai district, the Manimuthar, Papanasam and other dams in Tirunelvel district, the Pechiparai and Perunchani dams in Kanyakumari district and the Tirumurthi dam in Coimbatore district has reached dead storage level. What has further devastated the farmers was that even the groundwater that was available in the borewells, too, has let them down. They are either drying up or they have to be drilled to a depth of a few hundred feet.

Sir,

On seeing the parched fields and the withered paddy crops, many farmers had collapsed in their fields. The severe all-round distress resulted in hundreds of farmers committing suicide. Those who took their lives did so by hanging themselves or by consuming pesticides. The Tamil Nadu Government declared the State as "drought-hit" and dispatched its Minsiters to the districts to assess the situation. After assessing the situation It released over ₹ 2,000 crore as relief. All cooperative farm loans worth ₹ 5,000 crore were waived off. The State Government of Tamil Nadu had announced the

[Shri K.R. Arjunan]

following measures. Farmers' land tax would be waived. Farmers who lost 33 per cent of their crops would receive compensation. Families of farmers who committed suicide in the past two months would be given a solatium of ₹ 3 lakhs each. These are the steps the taken by the State Government. What are the steps taken by the Central Government?

Agitating farmers from Tamil Nadu demand ₹ 40,000 crore drought relief package. Cauvery Management Board has to be set up immediately. With the Cauvery being the deficit river, the implementation of the Cauvery Management Board would solve the problems of Tamil Nadu farmers to a great extent. All the crop loans and agricultural loans taken by farmers have to be waived off by Nationalised banks. Farmers have to be given alternative source of employment. During non-cultivation seasons, alternative source of livelihood has to be provided to them. These are the short term solutions.

It is time for us to evolve a holistic approach to the entire issue. Farmers demand good price for their produce. The Government must come forward to implement the recommendations of the M.S.Swaminathan Commission report. The report suggests that the cost of cultivation plus 50 per cent as profit should be fixed as the basic price for a produce.

The present Government promised that it would usher in "ache dhin" for farmers and put an end to farm suicides. Increased public investments in agriculture and rural developments, a minimum of 50 per cent profit over the cost of production, providing agricultural inputs at cheaper rates, introducing latest technologies for farming, a national land use policy to protect farmers' interests, providing irrigation facilities, are the measures that were promised in your Election Manifesto. Three years have passed. How many of these promises have been implemented? When are you going to implement them? Our founder leader Dr. Puratchithalaivar M.G.R. has said,

"Farmers are the employees appointed by an employer called God'.

Yes. Farmers are God's employees. Please protect their interests.

Saint Tiruvalluvar has said, the entire world is revolving around the farmer. But, now the farmer is running from pillar to post for his survival. Drastic relief measures have to be taken by the Government, as expeditiously as possible to save them. With these words, I conclude my speech. Thank you.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, firstly, we would like to thank the Chair. Last week also, we took up some issues of national importance and had a nice good solid debate and discussion on an issue of national importance. Today also, Sir, we have taken up an issue of farmers in this Short Duration Discussion. As we heard this morning, there is also a Calling Attention Motion which has been admitted on the flood-like situation in many States. Also, it is raining very heavily in West Bengal. So, the sluice gates of DVC are being opened. Because of that opening also, there is a lot of damage being caused. Thank you, Sir, for allowing us to take this issue up. Sir, I was trying to find out where I should begin from and what benchmark I should make here. So, I thought the best benchmark here to make and to quote is the BJP's manifesto of 2014. Let's not think what happened before that and what happened ten years ago. There were two quotes. I am starting reading BJP's manifesto now. It is good to read because then you get to know what were the promises made and where we are today. So, see page No.25. "Within three years, increase the profit of farmers up to 50 per cent over the input cost." This is from BJP's manifesto on page No.25. Next one is also on page No.25. It says, "Strengthen and expand the rural credit facilities." Today, I am trying to tell you where the BJP Government has reached in the last three years. Since I was reading the BJP's manifesto, you pardon me for I have also read the Trinamool's manifesto of 2011 and where we have reached in six years in Bengal. Sir, some speaker from the BJP said that we never appreciate; the Opposition is forever opposing and we don't appreciate the Government. We appreciate the Government because for the last five years the Krishi Karman Award given by the Central Government for foodgrain production and coarse grain production has come to my State, West Bengal. So, thank you very much for that Award. Sir, the income of the farmers — these are the hard numbers — from 2010, when the promise was made, to 2016 now, in my State, West Bengal, an annual income of ₹ 91,000 has now moved up to a little over ₹ 2 lakhs. These are hard numbers. And, interestingly, the opening speaker, my colleague, Shri Digvijaya Singh from Madhya Pradesh and the speaker from Madhya Pradesh of BJP Shri Prabhat Jha both spent some time on the Pradhan Mantri Fasal Yojana. They both spent some time and tried to explain that. I would request both Madhya Pradesh and everywhere else one thing. You look at the West Bengal model which nobody has tried. It is working very well in West Bengal. Here is the model! Sir, the Minister for Agriculture is here; we have discussed it informally with him. The farmer gives 50 per cent. The Government gives 50 per cent. That is the share of the Central Government and the State Government. But what is unique in West Bengal is that the farmer does

[Shri Derek O'Brien]

not give a single rupee. एक रुपया भी farmer नहीं देता है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट देती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। I am happy and appreciate that the Agriculture Minister is nodding. That is why, this residual money is also picked up by the farmer. So, rather than doing a *tu-tu-main-main* on Madhya Pradesh, we should see that this is a good model and I would urge many more States to follow this model.

Sir, there has been a lot of talk and it is good that we should also have something on the Table. Sir, I certify that the contents are correct, and they are based on authentic information because it doesn't matter which State it is, or, it doesn't matter which party is ruling the State. That is not important. This is what we believe and this is an authentic list of 90 farmers who committed suicide. So, we have got the State, we have got the name, we have got the age and we have got the reasons for the suicide. So, these farmers' families should be taken care of. Sir, I would like to place this on the Table. In the morning, before I came here, I had these documents authenticated. Sir, they do this for many reasons. We don't have the time to go into whether it is a psychological reason because they can't pay back their debt, or because they don't have enough counselling. In fact, it has been a reasonably good monsoon as compared to the last two-three years. We are very well aware that India is so dependent on the monsoon because when it comes to water capacity also, America has 2,000 cubic capacity, China has about 2,000 cubic capacity, Russia has about 6,000 cubic capacity, whereas we are at 200 cubic capacity. This has not happened in the last four years. This has been happening for a period of time. So, we need to address this issue.

Now, let us come to the issue of the great announcement of demonetization. In fact, I was quite intrigued by what the speaker from the BJP, Mr. Prabhat Jha, said. He said, "नाम बदल गया।" जी, नाम बदल गया लेकिन क्या काम भी बदला? That is the question we have to ask. Otherwise, when this country thought that it voted for a 'game-changer', I am sure this country does not only want a 'name-changer'. On the cashless economy, we have to see the hard facts. What did the farmers do? Whether it was in Western UP, whether it was in Gujarat or Rajasthan, what did they do? They went back to the old system. As there was no cash available, they went back to the barter system, and the Chief Minister of Madhya Pradesh had to appeal to traders to pay, at least, a half in cash. Sir, if you look at what the RBI called the 'fire sale' of crops and you compare the sale of last year to that of this year, whether you do it in Kolar in Karnataka, whether you do it in Farrukhabad in UP, whether you do it in Lasalgaon in Maharashtra, whether it is potato, tomato or onion, all prices have shown a considerable drop.

Sir, everyone talked about the MSP. Let me make a specific recommendation to the Minister on MSP. I go back to a colleague of ours who used to sit here and he was an inspirational colleague, M.S. Swaminathanji, who was a nominated Member. There is too much of talk happening on MSP. Here is a hard suggestion coming from the Trinamool Congress. What did Swaminathanji say? He says that if you look at the Minimum Support Price, how do you calculate this Minimum Support Price? Sir, let us say, you call this 'C' For want of a better term, you call it 'C'. So, you take the seed cost and all the input costs. You take the seed cost, the costs of labour wages, all the agro practices, the insecticides and the pesticides. You put in all these together and you call it 'C'. Let us say that the cost is ₹ 1,000. Then, he suggests, which we have agreed, that the MSP must be 'C2'. So, if 'C cost is ₹ 1,000, you need to arrive at 'C2' plus all expenses. If it is 50 per cent, then it becomes ₹ 1,500. Sir, this is a hard number which we are suggesting. We have done it in a different way in West Bengal because we have done this through actually paying tor the farmer' e of the premium. I don't want to re-elaborate the point, which Mr. Digvijaya Singh and Prof. Ram Gopal Yadav brought up, on the insurance and the claims of farmers. Sir, in the Fasal Bima Yojana, and I am saying that this is not a problem in West Bengal because the State Government is covering for the farmer, but in the rest of the country, claims paid to farmers are less than ₹ 2,000 crores out of ₹ 6,000 crores, and the Agriculture Minister must look at these. Sir, there is no discussion on farmers' rights. Today, I heard a lot of rhetoric from the speaker from the BJP - we will do this, we will do this, we will do this. Fine; we wish you luck. But I want to tell you what was done for farmers, and, I will be failing in my duty if I do not recall, at least, in one minute, the historical 2006 Singur agitation for farmers. That was truly fighting for farmers' rights when a big corporate company like Tata, in association with all the media houses, wanted to snatch away 1,000 acres of land from the farmers. Sir, 600 acres of land was owned by farmers, who were willing to give their land without being forced by this company but Mamata di and the Trinomool Congress said that the 400 acres of land, which was belonging to the unwilling farmers, must not be snatched away. So, we all know what happened in 2006 and we all must remember what happened after that. In December, 2006, we saw, "One lady - 26 days - Hunger Strike - One objective; Save the Indian Farmer", and, that is why, Sir, and, we are glad, since then, a lot of the land movement and the way we look at land has also changed. What happened after that, Sir? When we said this, everyone said that we were making political points. Sir, we said it in 2006 and no less a body than the Supreme Court of India, in its historic judgement, on the 31st of August last year passed the judgement saying that 400 acres of land, which was usurped from the farmers, had to be given back

[Shri Derek O'Brien]

to the farmers, and, now, farming is happening there. This is not rhetoric but I thought, this is an appropriate moment to make some constructive suggestions to the Government, to see how one or two States are using models which are different, and, to acknowledge the history and the contribution made by people who have been part of this movement, and, they are not either launching television channels or changing names.

Sir, sixty years ago, almost to the day, 'Mother India' film was launched. It was launched in 1957 and now, we are in 2017. Sir, we talk about bullet trains, smart cities, kisan channels but the life of the farmer is still the same. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri M.P. Veerendra Kumar. You have 15 minutes.

SHRI MP. VEERENDRA KUMAR (Kerala): Sir, I would like to start with a newspaper report. Children and widows of farmers from Maharashtra gathered at *Jantar Mantar* to demand loan waivers and fixing of standard prices. A 13 year-old girl, Pallavi Pawar, with an unmoved expression on her face said, "I wish no parent does what my father did to me. At least, think about your children before you decide to end your life." It was around a decade ago that Pallavi's father, a farmer in Maharashtra's Jalgaon, decided to commit suicide, leaving behind his wife and four children. She said, "I don't remember his face clearly, but there are moments that flash before my eyes".

Pallavi was one of the over 40 children and widows of farmers from drought-hit Maharashtra who had gathered at *Jantar Mantar*. They had joined the on-going *'Kisan Mukti Yatra',* as part of which, farmers have demanded loan waivers and fixing of standard prices for their produce. Children dressed in white narrated tales of personal grief, with placards reading 'Suicide is not the answer', and 'Save our farmers'.

The stories of these families were grim reminder of how farmers' suicides in India might just be numbers for city dwellers, but are harsh reality for children and women living in the rural belt. That is something they see almost every day because of Government apathy. Agrarian suicides are a shameful feature on India's social scene. The Central Government itself submitted before the Supreme Court that there were 12,000 farmer suicides per year. There are statistics to show that 3.18 lakh farmers had committed suicide during the last 21 years.

Demonetisation also contributed to farm crisis. Farm incomes crashed and farmers' distress mounted, compounding already high suicide rates because of mass indebtedness.

Though some States have decided to waive off farm loans, the Central Government has not supported any of the States. There is an argument that there will be a big crisis in financial sector if you waive off loans.

According to the Public Accounts Committee of the Parliament, the Non-Performing Assets of the country are ₹ 6,00,000 crore. Seventy per cent of this is in corporate sector. Only one percent is in the agrarian sector. Big corporates are given crores and crores of rupees as loans by public sector banks. Big names in Indian corporates are given loans to the tune of ₹ 2,00,000 crore by public sector banks. But the loan waivers for farmers amount to less than these massive *loot*. And these loans to corporates had been at minimal interest. How many crores of rupees did we lose in scams? I do not want to give the numbers here as there is no time.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

You will get loans on a low interest to buy a luxury car. Bank staff will come to your house to complete the formalities. But, to buy a tractor, which is for his livelihood, a farmer has to give ten to twelve per cent interest on loan. And for that he will have to spend weeks and months with the bank people. And a poor woman, who wants to buy a goat, will have to bear huge interest burden in micro finance.

I should say that the Central Government is ignoring the agricultural sector. Centrally-sponsored schemes have been reduced. During the Twelfth Five Year Plan, the allocation for agricultural sector was ₹ 1.8 lakh crore. The same amount was spent for the development of Terminal-3 of the Delhi International Airport.

The Central Government is destroying the cooperative sector, which has been helpful to poor farmers to an extent. Demonetisation was extremely harmful to the cooperative sector.

Mr. Arvind Subramanian, the Chief Economic Advisor to the Government, has already advised to waive off arrears of corporate loans. At the same time, our so-called experts refuse to support farm loan waive-off.

The Central Budget of 2017-18 has allocated to agricultural sector ₹ 10 lakh crore only. But certain studies indicate that the small farmer is getting only eight per cent of

[Shri MP. Veerendra Kumar]

this allocation. Seventy-five per cent is availed by the big farmers, that too at the rate of three per cent interest.

Free Trade Agreements with ASEAN countries affect the agrarian sector of India dangerously. Many of the cash crops in Kerala as well as dairy sector are vulnerable to import surges triggered by the lowering of trade tariffs.

India's global-centered policy has brought loss to this country than gains. Import of rice, palm oil, tea, coffee, pepper, fish and rubber from ASEAN countries has become a challenge to our farm economy.

There is an allegation that the US, Japan and certain other countries are squeezing their produces into India through ASEAN countries exploiting the Free Trade Agreements.

Import of milk products from Australia and New Zealand has increased enormously. After the withdrawal of import barriers, private companies and multinationals have imported milk powder and converted it into milk. This has brought crisis into cooperative milk societies and to small cattle farmers. More concession to import duty will cause more suicides among them. Sir, 92 per cent of our rural farmers' income depends on cattle farming.

Free Trade Agreements cause low production in labour intensive sectors. It will cause massive unemployment in those sectors, which will naturally lead to suicides among farm labour.

During free trade agreements, Government should seek the opinion of State Governments on products to be put in negative lists. With the introduction of GST, some 13 cesses including *Krishi Kalyan* are withdrawn. It is assumed that there will be a revenue loss of ₹ 65,000 crores to the Central exchequer. Central exchequer had gained ₹ 9,000 crores through *Krishi Kalyan* cess last year. By the withdrawal of *Krishi Kalyan* cess, the Centre will find it difficult to find fund for the farmers welfare activities.

Losses to the farmers due to GST have to be evaluated and necessary steps must be taken to compensate it. I go back to Pallavi's tears and pray the Government to take steps to wipe off tears from farmers' eyes. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Veerendra Kumarji. It was your maiden speech; yet you, have completed within the allotted time. Thank you very much. Shri K.K. Ragesh.

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One second. I wanted to tell the hon. Members that some Members are coming and asking whether they can speak tomorrow. No. This discussion would be concluded today. There is no question of tomorrow. Yes, please.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, we are discussing this issue of farmers' suicide and agrarian distress at a time when farmers are organizing a lot of agitations, be it in Tamil Nadu, be it in Madhya Pradesh, in Maharashtra and elsewhere. At the very outset, I am requesting the hon. Members sitting there to go through their own election manifesto. The NDA's election manifesto clearly states: "Agriculture is the engine of India's economic growth and the largest employer and BJP commits highest priority to agriculture growth, increase in farmers' income and rural development." Unfortunately, today, the engine, which has been depicted here, has broken. That is what has happened. A lot of promises were being made in their election manifesto, as already explained here, 50 per cent profit over and above the cost of production, cheaper import and higher technologies for agriculture farming, high-yielding seeds, linking MNREGA with agriculture, price stabilization funds and many more. If, at least, 20 per cent of these promises were being met, we should have certainly avoided the present devastating situation so far as the agriculture sector is concerned. Yes, you had promised acche din, good days, for farmers. What are their 'good days'? The National Crime Records Bureau states that in 2015-16, there have been 12,602 farmers suicides. Compared to 2014-15, it is an increase of 42 per cent. In Maharashtra alone, 4,291 farmers have committed suicide. This is the highest figure ever in our country's history. Are these the good days that you had offered? When somebody raises the question about the suicide of farmers, what is your response? You say that farmers are committing suicide because of failure in love affair and due to impotency. ...*(Interruptions)*... That is what you are saying. We have got a State Minister saying that those farmers committing suicide are cowards and criminals. How are you going to address the question of farmers' suicide? Do not put the blame on farmers. ...*(Interruptions)*... Unfortunately, you are doing that. It has already been said in the House itself. It has already been said. You can go through the records. ...*(Interruptions)*... And, you have promised 50 per cent profit over and above the cost of production. But what is the situation? I had asked a question, in this House, whether the Government is going to implement the promise that they made in their election manifesto so far as ensuring 50 per cent profit is concerned. What is the answer? It was an emphatic 'No'. ...*(Interruptions)*... Yes, that is what I am saying. And, explain that if it is being implemented, the private players will

[Shri K.K. Ragesh]

be compelled to run away from the market. Sir, whom are you concerned about? Are you concerned about the farmers who are committing suicides or are you concerned about the private players, the Adanis and the Ambanis, Tesco, Walmart and Wilmar, etc? Are you concerned about that? You must explain that. Sir, why is this happening? We all are saying that. On the one side, we are talking about the price rise when we go to market and purchase something when we know that there is a huge price rise. At the same time, on the other side, farmers are saying, 'We are not getting any prices'. What does it mean? It means that prices are there for the commodities but, at the same time, those prices are not going to the farmers who are producing those products. These prices are being looted by the middlemen and the corporates. How? It is through your speculative business and futures trading. Your futures trading and speculative trading pave way for price rise in a speculative manner which ultimately denies the right of the farmers, and also your import policy that leads to the farmers not getting even the remunerative prices. I can give you the example. That has already been explained here. There is an import duty on wheat. At a time when there is a bumper production of wheat, you have slashed the import duty on it from 25 per cent to zero per cent. Why? Why did you do that? Why did you allow the foreign players, and those who import commodities from foreign countries, to import and dump wheat in our country? That, ultimately, led to farmers not getting even the Minimum Support Price (MSP). What arrangements have you made to ensure MSP or to procure wheat? Did you make any arrangement to procure wheat at that time when farmers were compelled to sell wheat at a distress price? No, Sir. So, whom are you serving? Are you serving the interest of the farmers or are you serving the corporates? Unfortunately, Sir, their policies are serving the corporates only and not the farmers. That is one of the important reasons for suicides.

And, Sir, again, you have said that you are going to link MNREGS with agricultural sector but, unfortunately, you have slashed budgetary allocation for MNREGS. As per the Act, you have to pay back the wages within a fortnight period. I want to know whether the workers are getting the wages on time? No, Sir. The Central Government is yet to transfer 20,000 crores of rupees to the States under the head 'MNREGS'. So, they are destroying the very concept of providing jobs to the people and that also affect the agrarian sector. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana which has already been explained here... ...*(Time bell rings)*... Sir, the premium, in 2016-17...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is time. ...*(Time-Bell rings)*...

4.00 P.M.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I will take three more minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You take two more minutes, okay.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, in 2016-17, the total premium that has been collected is about ₹ 21,500 crores. What is the disbursed amount during the same period? It is only ₹ 714.14 crores. What does it mean? You have allowed the insurance companies to loot the Government, to loot the farmers to the tune of ₹ 20,000 crores and you are saying that we have made such a *yojana.* Yes, you have got lot many *yojanas* which are prefixed with Pradhan Mantri. There are lot many *yojanas.* There are about 11-12 *yojanas.* But irrespective of all these *yojanas,* why are the farmers committing suicides? You have to think of that. It is because you are allowing the corporates to loot the farmers.

Sir, so far as Kerala is concerned, nowadays, the rubber farmers are getting only ₹ 100. Earlier, in 2011, they were getting ₹ 243; but, now it is around ₹ 100. Why? It is because of the import duty and the import policy. The tyre manufacturers were allowed to import rubber from international market, Bangkok market, with a cheaper import duty and this amounted to a devastated situation so far as the rubber farmers are concerned. What is the result? The farmers are on the verge of suicide and, at the same time, the tyre manufacturers' profit is getting increased day-by-day. You can go through the records. They are making huge profits. You are allowing the tyre manufacturers to loot the farmers and that is what your policy is.

Sir, you are so concerned about the non-performing assets caused by corporates and are ready to write-off. Our Finance Minister, time and again, used to say that it is not waived but it is only book adjustment. Whatever may be the case, you are ready to write-off the NPAs made by the corporates. It is to the tune of lakhs and crores of rupees. What about the loans taken by the poor farmers who are committing suicides? Why don't you go in for a loan waiver so far as farmers' loans are concerned? You are more concerned about corporate loans. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: You are ready to adjust and write-off the corporate loans. ...*(Interruptions)*... I am requesting, through you, Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Interruptions)*... All right.. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, this is a very important issue. ...*(Interruptions)*... Sir, this is a very important issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree that it is very important. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: The Government is not concerned about that. ...*(Interruptions)*... When farmers are committing suicide, the cry of farmers is falling on deaf ears and they are not ready to listen to it. They are not ready to see the agony of the farmers. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; the Minister should listen. ...*(Interruptions)*... Okay. ...*(Interruptions)*... All right. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: I am requesting them to see the agony of the farmers and come with a loan waiver and a change in their policies. Whatever policies you are putting forward for the corporates, change those policies. That is the only way to address this question. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Prasanna Acharya.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, it seems that the whole country, today, is engulfed with an agrarian crisis. Sir, the Government is claiming that there has been a growth of 4.9 per cent. I do agree and I congratulate the Government also because, in earlier years, the growth was one per cent, two per cent or hardly three per cent. Last year, the growth was 4.9 per cent.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): आप किसानों को बधाई दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRASANNA ACHARYA: I am coming to that, Sir. आप बात तो सुनिए, अभी तो मैंने शुरू किया है। आप तो बाहर जा रहे हैं, बैठिए, सुनिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You address the Chair.

SHRI PRASANNA ACHARYA: But, as the hon. Member was pointing out, the maximum credit for this growth goes to the farmers of this country. On the one hand, there is growth in the agricultural sector but, on the other hand, farmers are coming out to streets everyday in most parts of the country. They are *laathi*-charged. They are put inside the prison and they are fired at. They are killed by the police and, moreover, they are committing suicides in hundreds and thousands of numbers. That is the state of affairs in the country today, Sir. What is the reason? If there is a growth in agriculture, why

are the farmers dying? Why are the farmers agitating? Why are the farmers committing suicide? That is because the benefit of growth is not reaching the farmers. That is the main reason. That is why farmers are getting frustrated and committing suicide or resorting to agitations. Sir, in this situation, growth cannot be sustained if farmers' interests are repeatedly overlooked by the Government, and I mean both Central Government and the State Governments. Every Government has got a responsibility.

Sir, our farmers are agitating in different parts of our country. Farmers' agitation is not new to this country. If we go back into history, farmers' agitation was a part of our freedom struggle. We remember the agitation of the *Neel* farmers' in Bihar, led by Gandhiji. We remember the farmers' agitation of Bordoloi, led by Sardar Vallabhbhai Patel, the reason for which was that Britishers strangulated the interests of the farmers of the country during the colonial days. Sir, in the post-Independence India, even after the success of the Green Revolution, there were farmers' agitations. I remember, Mahendra Singh Tikait, the great farmers' leader, who led many huge farmers' agitations. We must not forget Shri Sharad Joshi. Then, I remember another Samajwadi leader, Late Kishan Patnayak, who led several fiery agitations in Odisha and in some parts of Bihar. Late Kishan Patnayak was a Member of this House from 1962 to 1967, and he came to this House at the young age of 27. He is no more there.

Sir, there was a time when people in India were starving and we had a severe food crisis. We were dependent on PL-480, if you remember, the American foodgrain assistance programme. We had to import rejected foodgrains from America under PL-480. We now have surplus of foodgrains. When there is shortage of foodgrains, there is farmers' agitation. But when there is growth in agricultural productivity, and we claim to have surplus of foodgrains, then also there is farmers' agitation. The basic reason is that the farmer, who is actually responsible for the growth in agriculture, does not get the benefit.

As many hon. Members have already stated, this Government had made certain promises to farmers during elections. You promised them doubling of their farm income in five years. Then, you promised them 50 per cent more income over and above the cost of cultivation (2C) as recommended by Swaminathan Committee. That has not yet been fulfilled.

Where are your promises, Sir? Farmers are feeling cheated. I feel that is the prime reason why they are agitating today. It is because they feel cheated by this Government.

[Shri Prasanna Acharya]

The monsoons have not betrayed them. The nature hasn't betrayed the farmer. It is this Government which has betrayed the farmer. That is why they are committing suicides. That is why there is widespread agitation all over the country. Farmers are feeling cheated by this Government. You brought in demon-tisation, which turned into demon-tisation; राक्षसीकरण हो गया। सर, विमुद्रीकरण राक्षसीकरण में परिवर्तित हो गया। And that demon's first victim was the poor farmer of this country. How? The much-hyped demonetisation drive resulted in the collapse of farm produce prices. At the time of demonetisation, many farmers were ready with their produce, but they found no buyers as every one's cash had been drained out. There was no cash in the market for a pretty long time, for months' together. In that situation, who would purchase his produce?

What are farmers demanding today? They are not demanding five-star hotels in villages. They are not demanding swimming pools in their villages. They are not demanding food malls in their villages, like the ones we have in our metros.

What do they expect from you? They expect a good, remunerative price for their produce. They want a good market for their produce. They want timely loans from financial institutions. Finally, they want a good insurance policy.

Sir, the Government announces the M.S.P. every year. But what is the mechanism for that? Many hon. Members mentioned about the Swaminathan Committee's report in this regard. Why don't you implement the recommendations of the Swaminathan Committee, at least, in respect of the fixation of the M.S.P.? Sir, if you go into the report of the Agriculture Costs and Prices Commission of last six years, it narrates the bitter truth that MSP minus cost have already declined during the last three years in most agriculture commodities, such as paddy, maize, cotton, grams, pulses, sugarcane etc.

If we just look at 2016-17 data, last year's data, there were negative margins on several commodities, *e.g.,* jowar grain, it was minus by 18 per cent; ragi, it was minus by 20 per cent; sunflower, it was minus by 13 per cent, groundnut; it was minus by four percent; moong dal, it was minus by seven per cent; and arhar dal, it was minus by four per cent, to mention a few.

I do agree that prices are determined by the forces of demand and supply. Then, how do we set the market right? We must allow export when there is a bumper crop. But,

strangely, the Government is strangulating the market by banning export even when the market is in surplus. As a result, the farmer is getting price even below the MSP.

On the other hand, the Government is allowing import, and that too, free of import duty, *e.g.,* there is duty-free import of arhar from Myanmar. There is maximum import of arhar from that country. And what is the result? If I am mistaken, the hon. Members from Maharashtra may correct me. In the mandis of Maharashtra, and even in the mandis of Madhya Pradesh, what price are the farmers getting? The farmers are getting selling price which is much below MSP. *(Time bell rings).* Sir, give me three minutes more, and I will complete. The MSP is ₹ 5,050/-, but, they are selling at ₹ 4,000/-. In such cases, the Government has to intervene in the market.

Sir, the present Insurance Policy, the new Insurance Policy, I do admit, is a better Insurance Policy than the old Policy. Now, the village has been made a unit. I congratulate the Government for this decision. This has been the demand of the farmers; this is a pretty long pending demand of the farmers. Earlier, the tehsil was a unit, and now, the village is a unit. It is a good development, Sir. But, one problem is, the insurance companies are not accountable to the district administration where they will have to function, and every year, we will be changing the insurance companies, and there will be no stability. We are not interested for the non-loanee farmers. Insurance companies are not interested for the non-loanee farmers. They are only interested for the loanee farmers.

Sir, indebtedness, as many of the Members have stated, among the farmers, is a big challenge in the present agricultural scenario in our country. According to the NSSO Report of 2014, about 52 per cent of the total agricultural households are in debt. Accumulating loan burden is one of the major reasons of farmers suicide, as all of us know. Again, according to the NSSO Report of 2014, about 60 per cent of the outstanding loans were taken from the institutional sources. Among the non-institutional sources, 25.8 per cent loans are from the professional money lenders. The professional money lenders pose a major problem in this country. Most of the small and marginal farmers are indebted to professional money lenders. Once they fall into the *chakravyuh* of the money lenders, they can't escape, and the final result is suicide.

I would like to mention one more point. As if the hoard of problems we have thrusted upon the farmers of the country is not enough, the Government is now planning to bring GM mustard to the country in a large scale. I think, it is under the active consideration of the Government, and the Government is on the verge of allowing the GM Mustard to this

[Shri Prasanna Acharya]

country. This will be another blow to the agriculture of this country. This is a warning to this Government.

Sir, Mr. Jairam Ramesh is sitting here. The farmers' community is thankful to him. I think, he was the Minister in charge at that time. He prevented BT Brinjal, and the farmers of this country are very grateful to you, Mr. Jairam Ramesh.

Sir, my last point is, what the farmers are demanding are three things, three Ps. They demand remunerative price for their product. All Members who are sitting here, get pension after retirement, Sir. Farmer is demanding pension. After serving the country for whole life, when he gets older and cannot work, how will he survive? He wants a little pension. We all enjoy pension but he is deprived of pension. Third thing is three 'Ps'. Give prestige, price, and pension to the farmer in this country. These are the three basic demands of the farmers. I think both the Central Government and the State Governments are equally responsible for the crisis of the farmers. They should ponder over the matter. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cogently presented your point. Good thing. Now, Shri Parshottam Rupala. You are a Minister. Do you want to speak?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रुपाला): जी, सर।

श्री उपसभापतिः कितने मिनट बोलेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री परषोत्तम रुपालाः सर, मैं गुजराती में बोलूँ? ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Sir, our turn has not come. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister wants to speak. *...(Interruptions)...* Do you agree? *...(Interruptions)...* Okay, आप बाद में बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRAFUL PATEL: Let him speak later. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He can speak later. The only thing is that you should remember that he is a Minister when he speaks. You should not think that he is sitting on that side. That is all. Shri Munquad Ali.

श्री मुनक़ाद अली (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं

कि आपने मुझे किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया है और मैं अपनी पार्टी की नेता, आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया है।

महोदय, हमारे देश के किसान को "अन्नदाता" के नाम से इसलिए जाना जाता है, क्योंकि वह हमारे देश के सवा सौ करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न, तिलहन, दलहन तथा गुड़, चीनी, सब्जी आदि का उत्पादन करता है, जिस कारण किसानों की मेहनत के बिना हम एक दिन भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना है कि आज किसानों के कर्ज में डूबने के कारण, उनको फसल के उचित दाम न मिलने के कारण, बाढ़, बारिश एवं सूखे के प्रकोप के कारण, हमारे देश में प्रति वर्ष लगभग 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 10,000 किसान खेती का कार्य छोड़ रहे हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा)** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि देश की केन्द्र व राज्य सरकारें किसानों के बारे में काफी बड़ी-बड़ी बातें, काफी बड़े-बड़े काम करने के लुभावने वायदे तथा बजट में उनके लिए अनेकों प्रावधान करने का डंका पीटती रहती हैं, परन्तु देश में खेती और किसानों से सम्बन्धित जो भी वास्तविकता है,वह अत्यन्त दुखद और दर्दनाक है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की हजारों घोषणाओं तथा आश्वासनों के बावजूद खेती किसानों की पसन्द का पेशा नहीं रहा, बल्कि एक मजबूरी का पेशा बन गया है। वास्तव में खेती और किसानी के घाटे का कारोबार हो जाने के कारण देश के करोड़ों किसान बैंकों व साहूकारों के कर्ज़दार होने के कारण कष्टमयी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उनमें से हजारों गरीब मंझोले किसान कर्ज के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं।

माननीय मोदी जी की सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को उनकी फसल का डेढ़ गुना मूल्य दिया जायेगा, लेकिन डेढ़ गुना तो छोड़ो, किसानों को उनकी लागत का भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि भारत का किसान "अन्नदाता" होता है। उसको हम आत्महत्या नहीं करने देंगे। उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हम अपनी सरकार में उन्हें किसी भी हालत में आत्महत्या नहीं करने देंगे, लेकिन आज लगभग तीन सालों में भारी तादाद में किसानों ने आत्महत्या की है। जितनी आत्महत्याएं तीन सालों में हुई हैं, उतनी आज़ादी से आज तक किसी सरकार में नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश के विधान सभा के चुनाव के दौरान मोदी सरकार के नुमाइंदों ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद किसानों के सभी कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद कर्ज माफ करने का ऐलान तो किया गया, लेकिन अभी एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया और जिस तरीके का ऐलान किया गया है, उससे तो ऐसा लगता है कि मुश्किल से 5 प्रतिशत किसानों को इससे छोटा-मोटा फायदा होगा, बाकी किसानों के साथ धोखेबाजी की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है? केन्द्र और राज्य की सरकारें किसानों की समस्या का हल निकालने में क्यों विफल साबित हो रही हैं, जब कि अब किसानों को उनकी उपज का वाजिब व

[श्री मुनक़ाद अली]

लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसानों की समस्याएं और भी ज्यादा भयानक रूप धारण कर रही हैं? किसानों के द्वारा सरकारी नीति व उदासीनता का विरोध करने पर देश भर में उन्हें लाठियां व गोलियां खानी पड़ रही हैं। इस प्रकार से किसानों की समस्याओं को टाला तो जा सकता है, परंतु उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। सरकारी दमन के कारण किसान अपने आपको लाचार व मजबूर समझने लगे हैं और खेती से मुंह मोड़ कर आपना जीवनयापन करने के लिए एक मजदूर बनते जा रहे हैं। कुल मिला कर नतीजा यह है कि खेती लाभ का पेशा नहीं रह गया, केवल धरती माँ से लगाव रखने के कारण अपने आपको किसान कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

महोदय, मैं किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे भी मालूम है कि पूरा देश जानता है कि 2011 में धान का मूल्य लगभग 4,000 रुपए प्रति क्विंटल था और जब मोदी जी की सरकार बनी, तो 1,100 और 1,000 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य रहा। इतना ही नहीं, चाहे दलहन हो या तिलहन हो या सब्जी हो या गन्ना हो, जो भी किसान से संबंधित है, उन सबके मूल्यों में गिरावट आई है, जिसके कारण किसान यूपीए सरकार से ज्यादा एनडीए सरकार में आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को कहना चाहूंगा कि वह बयानबाजी के बजाय किसानों के पक्ष में ठोस नीति बनाए। उनको मिलने वाले बीज, खाद, पानी, बिजली आदि को सस्ता करना होगा। किसानों की फसल को सीधे मंडियों में विक्रय करने का प्रबंध करना होगा, बिचौलियों की व्यवस्था समाप्त करनी होगी। एक बार किसानों के हर प्रकार के कर्जे को माफ करने की व्यवस्था करनी होगी। ...**(समय की घंटी)**...

गरीबी, भुखमरी व किसानों की समस्या का एक समाधान यह भी है कि खाली पड़ी हुई सरकारी जमीनों को भूमिहीनों को ज्यादा-से-ज्यादा बांटने की राष्ट्रीय नीति बना कर उस पर मुस्तैदी से, ईमानदारी से अमल करना होगा।

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर हमारी पार्टी की तरफ से हमारी एक और साथी बोल लें, तो बेहतर होगा। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसान आज कितना बदकिस्मत है, वह भूख की मार खाता है, बारिश की मार खाता है, ठंड की मार खाता है, घर में भूख की मार खाता है और जब बाहर निकलता है, तो लाठी-गोली की मार खाता है, इसलिए मेरी सरकार से गुज़ारिश है कि असत्य वादे, राजनीतिक खोखले बहाने छोड़ दे और किसानों के हक में ठोस नीति और कदम उठाए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you very much. Shri Praful Patel.

श्री प्रफुल्ल पटेलः उपसभाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में किसानों की विकट परिस्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं और शायद यह चर्चा हर साल हमारे सदन में होती है क्योंकि आज भी इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है, सबसे बड़ा जो समाज है, वह कृषक समाज है। आज भी 60 प्रतिशत लोग अपना जीवनयापन किसानी के भरोसे करते हैं। आज हमारे आधुनिक भारत में इतनी प्रगति हो रही है,

जिसको हम देख रहे हैं, फिर भी इस प्रगति से हमारा किसान वंचित रहा है और 60 प्रतिशत कृषक इस देश की कुल जीडीपी का केवल 15 प्रतिशत का हिस्सेदार है, शायद यह उससे भी कम है। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद, हमारा किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, आत्महत्या कर रहा है और फिर भी इस देश को सक्षम बनाने के लिए अपना खून-पसीना एक कर रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसी परिस्थितियों के बावजूद, इस देश में पिछले कुछ वर्षों में record उत्पादन, खासकर foodgrains के क्षेत्र में हुआ है। यहां मुझे शरद पवार जी के दस साल के कार्यकाल की याद आती है, जब उनके समय में, इस देश में गेहूं, चावल और सीरियल्स का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। आज हमारा देश, विषम परिस्थितियों के बावजूद, विश्व में चावल का सबसे बड़ा exporter बना है, गेहूं का second largest exporter बना है और यही स्थिति cotton and even sugar की भी है। इसके अलावा horticulture क्षेत्र में खासकर, जैसे फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनमें भी विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा देश है। जब हम दूध का जिक्र करते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश भी भारत है। यह सब कैसे संभव हुआ, इस स्थिति तक देश को लाने में कई चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस स्थिति को लाने में जितने हमारे प्रयास रहे हैं, आज उन्हें और गति देना जरूरी है। जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो टीका-टिप्पणी करने के स्थान पर अगर हम कुछ constructive बातें करें, जिससे चर्चा के बाद कुछ ठोस सुझाव सामने आएं, इस अवसर पर मैं कृषि मत्री जी से कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके बयान मैंने कई बार पढ़े और सुने हैं। उन्होंने हमेशा जोर देकर कहा कि यहां सब कुछ indigenous होना चाहिए। अच्छी बात है कि indigenous होना चाहिए। लेकिन साथ-साथ research हो या कुछ और हो, उस पर भी हमें जोर देना चाहिए। नई उपलब्ध technology और नए साधनों का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। आज हमारा 125 करोड़ आबादी वाला देश है। उसमें अगर हम किसानों की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो हमें Science and Technology में हुई नई research का उपयोग करना ही होगा। ऐसा कहना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई वक्ताओं ने यहां स्वामीनाथन जी का उल्लेख किया, ICAR का उल्लेख किया, I am sorry to say कृषि मत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में Science and Technology क्षेत्र में हुई research को लेकर थोड़ा हमारा दुर्लक्ष्य रहा है। इस परिस्थिति को आपको कहीं-न-कहीं सुधारना होगा। BT कॉटन को लेकर हमारे भिन्न विचार हो सकते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ समर्थन करते हैं, लेकिन हमने जब-जब नए सीड्ज़ या नई technology का उपयोग किया है, उससे किसानों को कितना फायदा हुआ है, इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए हमें नई technology and research का सदुपयोग करना चाहिए।

जहां तक दूध और मवेशियों का सवाल है, अगर हमने नए breed का इस्तेमाल नहीं किया, उसका लाभ नहीं लिया, तो किसान को आज इससे जो लाभ होता है, किसान को हम दो पैसे ज्यादा देना चाहते हैं, उसमें भी हमें वांछित सफलता नहीं मिल पायेगी। इसलिए चाहे indigenous seeds हों, देश में Science and Technology के जितने Research Institutes हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ताकत देने की जरूरत है।

आज हमें देश में सिंचाई पर जोर देना भी आवश्यक हो गया है। अभी बारिश का मौसम है। हम TV में देखते हैं कि गुजरात में अतिवृष्टि हो रही है। मैं यहां विदर्भ की बात करूं, तो पश्चिम विदर्भ में

[श्री प्रफुल्ल पटेल]

तथा महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी बारिश की बहुत कमी है। देश में आज सभी जगह परिस्थितियां एक समान हैं, ऐसा नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए, long run में irrigation के लिए, हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि drift irrigation हो या पानी बचाने के हमारे पास जो भी साधन हैं, आज कम पानी से ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करना निहायत जरूरीहो गया है। हम लोग इरिगेशन में दुर्भाग्य से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर देते हैं। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल हो जाते हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है और उसका परिणाम यह होता है कि पैसा खर्च होता है, लेकिन उसका productive use होने के लिए, उसका फायदा पहुँचाने के लिए 25-30 साल का लम्बा अरसा निकल जाता है। इसलिए हमको उसके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

आज पूरे देश में किसान बहुत बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरा है। यह क्यों हो रहा है, इस पर भी हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। मध्य प्रदेश में किसानों का जो agitation हुआ, उसमें पाँच किसानों को गोली लगी। महाराष्ट्र में किसानों ने कई हफ्तों और महीनों तक अपनी पैदावार को कृषि मंडी या बाजार तक पहुँचाने का काम नहीं किया। उन्होंने सड़कों पर दूध बहा दिया, सड़कों पर सब्जी-भाजी फेंक दी। जब आज इस तरह से बड़े पैमाने पर किसान सड़कों पर उतरता है, तो उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर बैठकर एक बड़ा comprehensive view लेने की जरूरत है। इसमें एक विषय यह आता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ और उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए। यह अच्छी बात है, खुशी की बात है। उनके कहने से और आपकी सरकार वहाँ आने के बाद आपने वहाँ कर्ज माफी की घोषणा भी की है। खैर, अभी वह मिला या नहीं मिला, वह समय की बात है। लेकिन, प्रधान मंत्री जी केवल उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि प्रधान मंत्री जी इस पूरे देश के संरक्षक हैं, पूरे देश की सरकार के कर्ता-धर्ता हैं। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए किसानों को हर जगह पर केवल – हमारे महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा हुई है, लेकिन – हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं – इस घोषणा के पश्चात् भी वहाँ पर लोगों के मन में उत्तेजना है, लोगों के मन में नाराजगी है, क्योंकि घोषणा केवल कागज़ पर नहीं होनी चाहिए, उसको अमल में लाना भी जरूरी है। उसको किस तरह से अमल में लाया जाता है और उसमें इतनी शर्तों को रखना, यह किसी भी तरह से किसान के हित में नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी और शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, तब इस देश में पूरे देश के किसानों को एक समान कर्ज माफी देने का काम किया गया था। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब 2004 में शरद पवार जी कृषि मंत्री बने थे, तब किसानों को बैंकों से 12 प्रतिशत ब्याज लगता था, आज किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज लगता है, क्योंकि उस वक्त की नीति से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने interest का subvention करके – उस वजह से आज किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज लगता है। महाराष्ट्र में एक लाख रुपये तक ज़ीरो प्रतिशत ब्याज लगता है। यही नीति कर्नाटक में भी है और कुछ राज्य सरकारों ने भी इसे लागू किया होगा, लेकिन आज जब हम पूरे देश के किसानों की बात करते हैं, तो आप राज्य सरकारों को मदद करके और एक लाख रुपए तक ब्याज की दर को ज़ीरो प्रतिशत तक करने की एक यूनिवर्सल योजना पूरे देश के लिए क्यों नहीं बना सकते? इसके लिए आपको सोचना होगा। किसानों के लिए जब तक हम ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे, तब तक हम कितनी ही बातें करें, ये फिजूल ही रहेंगी। आज इस देश का जो सबसे बड़ा संरक्षक है, वह किसान है। ...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

श्री प्रफुल्ल पटेलः आपकी इंश्योरेंस की जो योजना है, जो किसान के लिए कृषि-बीमा है, उसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं, इसके बारे में भी आप सोचिए। इसमें अब तो यह हो गया है कि private companies को यह बीमा दे दिया गया है। पहले जब सरकारी कंपनियाँ कृषि बीमा उतारती थीं, तो जनप्रतिनिधि उनको कम से कम कुछ कहने की स्थिति में भी होते थे, लेकिन आज जब यह पूरी योजना निजी कंपनियों के पास चली गई है, तो उसमें जनप्रतिनिधि का रोल इतना कम हो गया है कि वे सुनने को तैयार नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Okay.

श्री प्रफुल्ल पटेलः उसका परिणाम यह है कि आज crop insurance के बारे में बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। In fact, लोग क्लेम भी नहीं करते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें निजी कंपनियों के प्रति आपको कोई न कोई निगरानी रखने की बहुत बड़ी जरूरत है। यही मैं आज के दिन कहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

श्री प्रफुल्ल पटेलः अंत में, मैं इतना ही कहूँगा कि कृषि मंत्री जी, विशेषकर जो टेक्नोलॉजी के साधन हैं, जो भी नये संसाधन available हैं, उनके बारे में आप कृपा करके एक open mind रखिए, क्योंकि आपके बयानों में कई बार मैंने जो पाया है, यह मैं कोई टीका के लिए नहीं कहँगा, may be आपकी भावना अच्छी रही है, लेकिन उसमें अमल करना बहुत जरूरी है। आज हम सब लोगों को बिना कोई राजनीति किए किसानों का साथ देना चाहिए, धन्यवाद।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for the opportunity given to me to speak on this important issue.

Sir, I was carefully going through the past records because I am a new Member. Every year, the House discusses on agrarian crisis and the hon. Members make so many suggestions. But I find that successive Governments for the last decade are doing very little so far as addressing the farmers' issue and agrarian crisis is concerned.

Sir, I have six issues. I would like to bring to the notice of the hon. Minister for Agriculture, through you, six important issues. For all the six important issues, I would like to make the suggestions also. It is up to the Government to follow the suggestions or not.

Sir, I have no hesitation to say that this Government is sensitive and compassionate insofar as five aspects are concerned. One is, this Government has created a separate Department called 'Farmers' Welfare Department'; the second is, wide acceptance

[Shri V. Vijayasai Reddy]

for PM's *Fasal Bima Yojana,* the third is, Kisan Credit Cards; the fourth is, record agricultural credit; and the fifth is the recent decision of the Cabinet on 14th June to give an interest subsidy. On these five important aspects, of course, we need to appreciate the Government. But even then, even after taking these initiatives, still there are farmers' suicides. About 12,000 suicides of farmers have been reported every year in this country, and the Government needs to have an introspection as to why the suicide of farmers is increasing ever year and not getting abated.

Sir, as I have told you, I would like to bring to your notice six important issues. The first is, lack of bank credit. Why are farmers' suicides still persisting in the country? The first is, lack of access to bank credit. Sir, 90 per cent of the farmers in this country are either small farmers or marginal farmers or tenant farmers. They don't have access to the bank facility. Way back, between 2004 and 2009, when the Congress Government was headed by YSR, who was the Chief Minister of Andhra Pradesh, he had introduced a Scheme by name of *'Pavala Vaddi',* that is, four per cent interest; and the difference between the Prime Lending Rate for the agriculture and four per cent, that used to be subsidized by the State Government. So, that was an excellent Scheme and every farmer during that period was happy and none of the farmers' accounts had got NPAs at that point of time. Therefore, such a Scheme has to be introduced in all the States, not only in that State but in all the States.

Sir, so far as non-availability of bank credit is concerned, I have one suggestion to make. Whatever is the investment that is needed by the farmer, so far as crop loan is concerned, the Government of India should innovate and find the ways and means of making the fund available to the farmer so that when the harvest comes to the hand of the farmer, whatever the Government has invested with a small interest, either two per cent or four per cent, it can be recovered from the farmer instead of leaving everything to the bankers because, all bankers, again, have the objective of making profit also apart from the social obligation. Sir, the second important issue which I would like to bring to the notice of the hon. Minister is e-NAM, that is, Electronic National Agricultural Market. This is a very good programme by the Government of India. It aims to connect 585 wholesale *mandis* in the country with the objective that farmers get better prices for their produce. As per data available, 400 *mandis* have been linked to the Electronic

National Agricultural Market, and 185 would be linked in the next few months, probably by March. This is a very good programme. Karnataka is the best example; Karnataka is a success story so far as e-NAM is concerned. In Karnataka, 157 mandals are using e-trading, e-payments, e-permits, scientific trading, etc. Sir, while perusing records and going through various websites, I found that the average realization of prices had gone up by 40 per cent for every farmer because of the Electronic National Agricultural Market, which the Karnataka Government has successfully implemented. I wish other States in the country also implement this excellent scheme which the Government of Karnataka has implemented.

Sir, the third important issue that I wish to talk about is the Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana. It is a very good programme, a very good insurance scheme, but it is not as penetrative as it was expected. That is my observation. Private insurance companies are the real culprits behind this. Here I would like to say that there is a great imbalance in claims paid and premiums collected. Let me give you an example. For the Kharif crop, an amount of ₹ 9,100 crores was collected as premium by private insurance companies. Now, the claims that are supposed to have been paid are ₹ 3,500 crores whereas actually they have paid just ₹ 2,700 crores. That leaves a difference of ₹ 800 crores, as there are umpteen numbers of disputes that have been raised by the insurance companies. My suggestion to the Government in this regard is to ensure that whenever there is a claim made by the farmer from insurance companies, it is settled within 15 days' time.

I would take just one more minute, Sir. Denial of loan waiver is another reason for farmers' suicides. Many State Governments in the country have promised farmers that they would be waiving their loans, but, in reality, these promises have not been fulfilled in letter and spirit. Instead of making these promises that remain unfulfilled, there must be a concrete plan for waiver and budgetary allocation made for the same. Appropriate steps need to be taken as far as loan waiver is concerned.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, let me make one last point.

Sir, we must focus on making the farmers strong and stand on their own legs and not allow them to become parasites. Lastly, I would like to suggest to the hon. Minister that we could have special agricultural zones just like we have Special Economic Zones. Special agricultural zones could be created for farmers for them to have better realization of prices for their crops.

[Shri V. Vijayasai Reddy]

Sir, last but not the least, is water availability. In one part of the country there are floods while in another part there are drought conditions. There is a wide variation in the average per capita availability of water in the various river basins. It is as high as 14,000 cubic meters in Brahmaputra and as low as 300 cubic metres in Sabarmati. The only solution for this is inter-linking of river waters. Government of India could think about it. That would be the solution for the problem of droughts and floods prevailing in different parts of the country.

SHRI R.S. BHARATHI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on this very important issue that the country is facing today. Many of my colleagues have made various points. So, I don't want to repeat the same. Today, Sir, I rise to bring to the attention of this House and the Government of India the plight of the Indian farmer. Across the States, farmers and farm workers are constantly praying, pleading and petitioning the Governments for some relief. I hope, no Member will contradict me when I say that this is the worst draught in our history since Independence. These are extraordinary circumstances and, therefore, I appeal to this House that we should take some extraordinary measures as well. A group of farmers from Tamil Nadu have been protesting earlier in the month of April and now again they have gathered at Jantar Mantar. They have sought a meeting with the hon. Prime Minister. Everybody knows, Sir, that these farmers were agitating during the winter season; in the chilly weather, they were on the streets. Then, in the hot summer, they were on the streets fighting for the same cause and today they are drenched in rain. Many leaders of this House visited them. We have consoled them and our leader, Working President, Mr. M.K. Stalin, also visited them. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu also gave them some assurance. In spite of all that, I do not know why the hon. Prime Minister is reluctant to meet them. Sir, I, on behalf of my Party, would request the hon. Prime Minister, through you, to meet them at least now and do the needful because it is their *bona fide* and genuine demand. I can assure you, Sir, that their demand is not disproportionate to the situation that they have faced over the past years. Rains have failed in Tamil Nadu. Banks have turned them away. Sir, here, I would like to mention that banks in Tamil Nadu are threatening the farmers. The reason for suicide by farmers in Tamil Nadu is that they are treated like criminals. Bank officials with the help of *goondas* are knocking the doors of farmers even at midnight. The prestige of farmers is involved here. A person who has refused to pay crores and crores of rupees to banks and fled to a foreign country is leading a pleasant life, whereas these poor farmers who have borrowed only some thousands or some lakhs are

being harassed in Tamil Nadu. This is the reason for their suicide. They have approached the State Government. The State Government said that the Centre should take care. In Tamil Nadu, Sir, in 2006, when our leader, Dr. Kalaignar took over as the Chief Minister, the very first day the first drop of ink was to sign the waiver of loan of ₹ 7,000 crore for farmers irrespective of the fact whether they were big farmers or small farmers. Sir, today, lakhs of farmers of Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra have been given loan waiver. The BJP Government speaks that it believes in one nation, one tax and one education. In spite of the fact that, this Government believes in one nation, one NEET, one tax and one entrance exam, then why not go in for one waiver of loan for farmers? Sir, when DMK Government was in power in Tamil Nadu, our leader, Dr. Kalaignar, enacted so many laws for the benefit of farmers of Tamil Nadu. The Tamil Nadu Agricultural Labourer Fair Wages Act, 1969, was enacted whereby the Government adopted a uniform rate of fair wages for all kinds of works during cultivating season. Here, I would like to mention that during 2006 to 2011, there was one project known as *uzhavar santhai,* that is, weavers' market. The farmers' produce was procured and straightway came there. There were no middlemen. Many hon. Members have pointed out that the profit does not go to the farmers, but the middlemen are grabbing the profits. To curb all these practices, we had enacted a law in Tamil Nadu to open centres for the farmers and the farmers were benefited from 2006 to 2011. Likewise, we enacted the Tamil Nadu Agricultural Labourers-Farmers (Social Security and Welfare) Act to provide comprehensive social security and for ensuring well-being of landless labourers and farmers engaged in direct cultivation.

Now, I will mention some of the primary challenges faced by the farmers across the country today. I would like to mention only three of them. The first challenge is the deteriorating soil health due to continued farming and indiscriminate use of chemicals and fertilizers. The second challenge is over-dependence on monsoons and depleting water resources. The third challenge is the acute farm labour scarcity. Sir, I urge the Government of India to call a special Session of Parliament to discuss the farmers' issues and enact a special legislation to address these challenges. Many of my friends have said that Government after Government has been only discussing the issues relating to agriculture, but nothing goes to the farmer. Therefore, at least, now, let us take a serious note of the farmers' situation and let us have a special discussion and enact a special legislation to address the challenges faced by the farmers. There is a famous kural:*

* The Hon'ble Member spoke in Tamil.

[Shri R.S. Bharathi]

Its meaning in English is, "Agriculture, though cumbersome, is the most excellent form of labour, for even though people go about in search of various employments, they all have to come back to the farmer. There is no form of labour nobler than the agriculture." The noblest profession in this country would be agriculture according to Thiruvalluvar. Therefore, Sir, the Government should take a serious note of this.

Sir, I would also mention that in Tamil Nadu today, there are two big problems which the agriculturists are facing. One is in Neduvasal village because of the hydrocarbon project. Because of this project, the entire Pudukkottai District will be spoiled. Farmers there cannot cultivate anything. They are agitating. Even experts have given opinion that this project should be stopped by the Central Government, but there is no reaction from the Centre. Likewise, for the last two weeks, Kadiramangalam farmers are fighting against ONGC. In Tamil Nadu, once again they say, at Karaikkal, we are going to stop the project. Once upon a time, Thanjavur was the source of rice produced for the entire State. *'Solai nadu sor azhitha nadu',* as they used to say, entire Tamil Nadu was dependent on the product of Thanjavur District, but I am afraid, Thanjavur District is going to be ruined. The Government has to take a serious note of this issue. I will also request the Agriculture Minister that our leader has written a letter regarding the BT mustard and that issue may be considered. Thank you.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): महोदय, हम आज तक बहुत गर्व से कहते थे कि हम किसान परिवार से हैं, हम किसान हैं, लेकिन आज पूरे देश में जिस तरह से किसान प्रताड़ित हो रहा है, गोलियां खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, यह देखकर मुझे बहुत दर्द के साथ कहना पड़ता है कि हम किसान हैं और इंसान भी हैं। महोदय, हिंदुस्तान में 60 से 70 प्रतिशत लोग खेती और खेती पर आधारित व्यवसाय करते हैं, लेकिन सरकार के रवैये को देखकर, मुझे तो लगता है कि हम सभी किसानों के लिए "त्राहि भगवान" कहने का काम सरकार ने कर दिया है। महोदय, मैं हर बार इसी विषय पर बोलती हूं और यही मंत्री जी हमारे सामने रहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि किसानों की मुश्किलों में कमी नहीं आयी है। आत्महत्या के आंकड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आत्महत्या के वर्ष 2014 के आंकड़े देखें, तो आंध्र प्रदेश में 632 हुई हैं, प्रधान मंत्री जी के गुजरात में 600 हुई हैं, कर्णाटक में 768 हुई हैं और मध्य प्रदेश में 1,198 हुई हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं मेरे राज्य महाराष्ट्र में 2014 में, 4004 हुई हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यही आंकड़े 2015 में बढ़ गए और कर्णाटक में 1559 तथा गुजरात में 301 हो गए और आत्महत्या के ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इन आंकड़ों में कमी होने वाली है, जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती।

सर, 41 per cent की बढ़ोत्तरी इन दो सालों में हुई है। मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि पहले ऐसा माना जाता था, मेरी स्टेट सहकारिता के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी स्टेट है, लेकिन यह

सरकार सहकारिता को खत्म करना चाह रही है। जिस महाराष्ट्र ने सहकारिता के माध्यम से पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया था और वही राज्य हिन्दुस्तान को नक्शे पर लाया था, आज उसी महाराष्ट्र में ग्रामीण सहकारिता जो अर्थ-वाहिनी का काम करती थी, वह खत्म होती जा रही है। चाहे सरकारी गन्ना कारखाना हो, चाहे सरकारी दूध संघ हो, चाहे और कोई हो, ये सब महाराष्ट्र से कम होते जा रहे हैं। इसका सीधा असर हमारे राज्य के किसानों पर हो रहा है, महिलाओं के ऊपर हो रहा है और खेत मजदूरों के ऊपर हो रहा है।

सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि जब प्रधान मंत्री मोदी जी ने नोट बंदी का निर्णय डिक्लेयर कर दिया, तो हमारा जो किसान धक्के खा रहा था, उसी किसान को न बीज मिला, न खाद मिली और वह चार-चार, पांच-पांच दिनों तक बैंकों की लाइन में खड़ा रहा। उसको उस समय हजार, दो हजार रुपए मिलने भी मुश्किल हो गए थे, यह किसानों का हाल था।

अभी हमारे भाई शिव सेना से बोले थे कि महाराष्ट्र में ऋण मुक्ति हुई है और 34,000 करोड़ रुपए वहां के मुख्य मंत्री ने ऋण मुक्ति के लिए डिक्लेयर कर दिए हैं। मैं इस सभागृह को और सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी जैसा कि संजय जी ने कहा है कि उनकी सरकार ने किस तरह से ऋण मुक्ति कर दी है, क्योंकि हम किसान हैं, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि उन्होंने बहुत selective ऋण मुक्ति की है। पहले उन्होंने बोला कि जो भी किसान कर्ज लेना चाहते हैं, हम उसको बैंक से ऐसे ही 10,000 रुपए दे देंगे। आज ताकि एक भी किसान को 10,000 रुपए की राहत नहीं मिली है, यह बात मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं। अभी संजय जी ने बोला कि डेढ़ लाख रुपए तक का हम ऋण मुक्त करेंगे। अगर उससे ज्यादा किसी के ऊपर कर्जा होगा, तो उस कर्जे के लिए पहले किसानों को वह पैसा वापस करना चाहिए और वह पैसा करने के बाद ही हम उनको डेढ़ लाख रुपया दे देंगे। किसानों के साथ यह कैसा मज़ाक है? अगर ड़ेढ़ लाख से ऊपर पैसा किसान के पास होता, तो उसको आपके दरवाजे पर भीख मांगने की उसको आवश्यकता नहीं होती।

सर, उन्होंने किसान को 30 जून, 2016 की डेडलाइन दी और कहा कि अगर कर्ज़ माफी चाहते हो, हम 30 जून, 2016 के बाद उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आप से कहना चाहती हूं कि आपके यहां भी होगा और हमारे राज्य में भी होता है। अगर कोऑपरेटिव बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यदि हम उनके पास कर्ज़ा लेने जाते हैं, तो जो पुराना कर्ज़ा मार्च में देना होता है, पहले उसको नया किया जाता है। अगर वह नया हो गया, तो इस सरकार ने कहा कि इस तरह से जो कर्ज़ा नया किया है, हम उसको डेढ़ लाख रुपया नहीं देंगे, हम उसको सिर्फ 25,000 रुपए ही देंगे। इस प्रकार से उन्होंने हमारी अवहेलना की है। यदि किसी के परिवार में दूर-दूर का आदमी भी नौकरी करता है, तो उसको कर्ज़ा माफी नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में यह एक नया कानून लागू कर दिया गया है। हमारे परिवारों में तो कोई न कोई नौकरी करता ही है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे परिवार को कर्ज़ से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर इस तरह से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो दिन पहले ही ऑनलाइन घोषणा पत्र की घोषणा कर दी कि अगर आपको कर्ज़ मुक्ति चाहिए, तो आपको ऑनलाइन घोषणा-पत्र देना चाहिए। अगर हमारे किसान इतने पढ़े-लिखे होते कि वे ऑनलाइन घोषणा-पत्र दें, तो आपके पास आने की नौबत ही नहीं आती।

[श्रीमती रजनी पाटिल]

5.00 P.M .

सर, मैं आपके माध्यम से कृषिं मत्री जी को बताना चाहूंगी कि आप सिर्फ कृषि के लिए ऋण मुक्ति क्यों देते हैं, बल्कि जो जानवर पालते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, जो हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, उनको भी राहत देने की बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने लिस्ट ट्विटर पर 15 दिन पहले डिक्लेयर कर दी। हमने ट्विटर पर देखा कि कितने लोगों को कर्ज़ मुक्ति मिली, तो 36,10,000 लोगों की सूची दी थी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी और सभी को सुनकर आश्चर्य होगा कि उसमें से 813 लोग मुम्बई शहर में खेती करने वाले थे।

क्या वे मलबार हिस्से में खेती करते हैं? उनमें से मुम्बई शहर के 813 लोग खेती करने वाले निकले। Press की कटिंग मेरे पास है। इन्होंने इस तरह से ऋण मुक्ति की है। इन्होंने किसान के हाथ बाँध दिए हैं, उनके पैर बाँध दिए हैं, उनके मुँह पर पट्टी भी बाँध दी है और उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उनसे बोला है कि जाओ मरो, कहीं पर भी जाकर मरना है। इन्होंने इस तरह से किसानों के साथ छेड़खानी की हुई है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूं कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब हमारी सरकार ने किसानों के 72 हजार करोड़ रुपये की ऋण मुक्ति की थी। मैं यहां पर खास तौर से बताना चाहती हूं कि हमारे उस समय के प्रधान मंत्री, माननीय मनमोहन सिंह जी विदर्भ और मराठवाड़ा में दो बार गए थे। वे वहाँ पर किसानों का दो बार हाल पूछने के लिए गए थे। हम इतनी बार मोदी जी से बोल चुके हैं कि आप पूरे विश्व में घूमते हैं, देश-विदेश की यात्रा करते हैं, कम से कम हमारे किसानों का हाल पूछने के लिए एकाध बार तो आइए। हम कहते हैं कि आप कर्णाटक में जाइए, विदर्भ में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, लेकिन वे वहाँ पर जाने वाले नहीं हैं। जब उनकी विदेश यात्राएँ खत्म होंगी और 2019 में जब उनकी नैया डूबने लगेगी, तब उन्हें किसान याद आएंगे, क्योंकि यही किसान उन्हें उनकी असली जगह दिखाने वाले हैं। ...**(समय की घंटी)**... उपसभाध्यक्ष जी, मैं बस दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी।

उपसभाध्यक्ष जी, सरकार ने यह भरोसा दिया था कि स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार एमएसपी देंगे, 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का अनुकरण करेंगे। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जब अपने "मन की बात" कार्यक्रम को आह्वान किया, तब उन्होंने कहा कि अरहर की दाल लगाओ, अरहर की दाल लगाओ। महाराष्ट्र के हमारे सभी किसानों ने प्रधान मंत्री के शब्द मानकर अरहर की दाल लगाई और उस अरहर की दाल की इतनी बम्पर क्रॉप आई कि अरहर की उस क्रॉप को रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं रही। उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो करके, म्यांमार जैसे देशों से अरहर की दाल इम्पोर्ट कर ली। जब वह दाल उनसे इम्पोर्ट कर ली गई, तब हमारे किसानों को अपनी वह दाल घर में ही फेंकनी पड़ी। ये हमारे किसानों के आज के हाल हैं। उन्होंने जो हमारा भरोसा तोड़ा है, मैं उसको यहाँ पर बताना चाहती हूं। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष जी, किसानों की हालत बहुत गंभीर है। अगर किसान जीवित रहेगा, तभी देश रहेगा। किसान जिंदा रहेगा, तभी देश जिंदा रहेगा। इसके लिए मैं यह बोलना चाहती हूं कि जब मंत्री जी भाषण देंगे, तो अलग-अलग नाम देकर, अलग-अलग योजनाएँ बताएंगे। वे उनके अलग-अलग

नाम बताएंगे, जैसे यह योजना, वह योजना इत्यादि, जो हमारी समझ में भी नहीं आएंगी। आप हमें ये योजनाएँ मत बताइए, आप हमें सीधा यह बताइए कि आप हमें क्या राहत देने वाले हैं? राहत देने वाले भी हैं या नहीं? हमें संपूर्ण ऋण मुक्ति चाहिए। आप संपूर्ण ऋण मुक्ति करने के लिए तैयार हैं या नहीं? लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार बोला था, "जय जवान-जय किसान", लेकिन इस सरकार के हाल में जवानों के हाल भी गंभीर हैं, क्योंकि वे हर रोज बॉर्डर्स पर मरते जा रहे हैं। किसान के हाल उससे भी गंभीर हैं, इसलिए उन दोनों को बचाने के लिए मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगी कि सरकार को बहुत बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम देती हूं, धन्यवाद।

श्री परषोत्तम रूपालाः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया है कि मैं किसानों की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा ले सकूँ। मैं अभी अपने सभी साथियों को सुन रहा था। यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया जा रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो या किसानों के दमन का मुद्दा हो, उनको बड़ी संवेदना से सुनना चाहिए और बड़ी संवेदना से प्रस्तुत करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ता था, उस समय सुना करता था कि इस देश में यदि कोई सबसे अच्छा व्यवसाय माना जाता है, तो वह खेती माना जाता है, उत्तम खेती कहा जाता है। पहले उत्तम खेती कहा जाता था, बार में मध्यम व्यापार कहा जाता था और नौकरी को कनिष्ठ माना जाता था। हम ऐसी बातें पुरखों से सुनते था, शायद कहानियों में सुनते होंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रजनी पाटिलः बहुत साल हो गए।

श्री परषोत्तम रूपालाः यह बहुत सालों पहले की बात है। आप हमें जो 2014 से बता रहे हैं, क्या यह उत्तम खेती 2014 में कनिष्ठ हो गई है? यह मेरी समझ से परे हो रहा है। 2014 के बाद यह खेती निकृष्ट हो गई। हमारी बहिन बहुत ही ऊँची आवाज में हमें सुना रही थी कि हमारी सरकार ने इतना कर्ज माफ कर दिया। उस कर्जा माफी के बाद कितनी आत्महत्याएं हुई थीं, उनकी फिगर्स भी आपको थोड़ी बता देनी चाहिए थी? किसानों के मन में क्या पैदा हुआ था? जिन्होंने जिंदगी भर पैसा लिया ही लिया और कभी जमा करने की कोशिश नहीं की, उन्हीं का कर्जा ज्यादा माफ हुआ था, न कि ऐसे किसानों का, जो मजदूरी कर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा लाभ किसे मिला था? ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): आप किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप किसानों का अपमान कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please don't interrupt. *...(Interruptions)...*

श्रीमती रजनी पाटिलः किसानों का अपमान मत करो। ...**(व्यवधान)**... आप किस तरह की बात करते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री परषोत्तम रूपालाः अच्छा, जब आप बोल रहे थे, मैं इधर ही बैठा था। मैं इससे भी ऊँची आवाज में बोल सकता हूँ। ...**(व्यवधान)**... आवाज ऊँची करने से सच्चाई को छुपाया नहीं जाता। ...**(व्यवधान)**... आवाज ऊँची करने से सच्चाई को छुपाया नहीं जाता। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Rupalaji, you please resume. *...(Interruptions)...*

श्री परषोत्तम रूपालाः आपका हक है चिल्लाओ, **...(व्यवधान)...** और जोर से चिल्लाओ। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती रजनी पाटिलः हम दबने वाले नहीं हैं। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Smt. Rajani, please *...(Interruptions)...*

श्री हुसैन दलवइः सर, मंत्री जी किसानों का अपमान कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री परषोत्तम रूपालाः आपने कौन सा किसानों का ठेका ले रखा है? जो आप बोल रहे हैं, ठीक और मैं बोलूं तो किसानों का अपमान हो जाता है? **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): When your turn comes, you can reply. *...(Interruptions)...* Your turn will come. Then you can reply. *...(Interruptions)...* Please, you need not immediately retaliate. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* You need not immediately retaliate. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...*

श्री परषोत्तम रूपालाः हम बोलें, तो किसानों का अपमान और आप गालियां भी देते रहें तो आप किसानों की बात बता रहे हैं? **...(व्यवधान)...** लोग सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं। **...(व्यवधान)...**

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, we are debating an issue of great importance. I think, let all the views come. They will have other speakers who can contradict him. But, he should not be stopped from speaking. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): I am telling them the same thing. *...(Interruptions)...* They need not immediately retaliate. *...(Interruptions)...* Their next speaker could, of course, respond to what he is saying. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, if a Member is passionately speaking in a loud voice, she should not be reprimanded. जोर की आवाज से **...(व्यवधान)...** You should not be saying that. *...(Interruptions)...*

श्री परषोत्तम रूपालाः मैं उनकी तारीफ कर रहा था। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती रजनी पाटिलः आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। ...**(व्यवधान)**...

श्री परषोत्तम रूपालाः हम आपकी तारीफ कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**... जो आप इतनी ऊँची आवाज में बातें कर रहे थे, उसके बाद की बात आपने नहीं बताई। सर, मैं आपके माध्यम से इस सभागृह के सामने सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि किसानों की हालत के बारे में जो यह चर्चा कर रहे हैं कि इसको ऋण नहीं मिल रहा है, इसको मंडी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए अभी तक की सरकारों ने क्या किया? उसके बारे में तो जिक्र होना चाहिए कि हमने इतनी मंडियां की थीं, जो नई सरकार ने आकर बंद कर दीं। यह तो बताना चाहिए था। मंडियों में क्या चल रहा है, आपको, साहब, मालूम है? सर, आप जरा इधर मेरी ओर देखिए। शिवा जी सर, आप इधर देखिए, मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि मंडियों में क्या हो रहा है? इस तरह से रूमाल निकाला जाता है, किसानों की चीज़ के लिए अंदर हाथ रखते हैं। खरीदने वाला इधर रखता है और अंदर से अंगुली पकड़ कर उस चीज़ के दाम तय होते हैं। ...**(व्यवधान)**... उनका काम इस तरह से होता है, सर। इन मंडियों में इस तरह से हाथ डाल कर अंगुली पकड़ कर दाम तय होते हैं। ...**(व्यवधान)**... हम किसान हैं। हमने भोगा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आपने किया क्या, जो अभी तक यह हालत है किसानों की? ...**(व्यवधान)**... यह हो रहा है? ...**(व्यवधान)**... आपने भी देखा होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Rupalaji, please address the Chair.

श्री परषोत्तम रूपालाः मैंने इसीलिए आपको बोला। ...**(व्यवधान)**... आपको ही बोला, सर। इस देश में यह हो रहा था। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have a point of order. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि इस डिबेट में माननीय केन्द्रीय मंत्री जी का उत्तर आने वाला है और वे जिस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, क्या यह उनको शोभा देता है? ...**(व्यवधान)**... बात यह है कि ...**(व्यवधान)**... जो व्यक्ति ...**(व्यवधान)**... जिस व्यक्ति के पास अधिकार है ...**(व्यवधान)**...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, he is a Member of our Party. ...*(Interruptions)*... He is not replying. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: This is not the way. ...*(Interruptions)*... It is my point of order. ...*(Interruptions)*... They should have listened to my point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No, no. He is speaking on behalf of his Party. ...*(Interruptions)*... He is not replying. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is my point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Digvijayaji, please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप बीच में कैसे interrupt कर सकते हैं? **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Please allow him. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Rupala is speaking on behalf of ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No point of order. ...*(Interruptions)*... There is no point of order, please. ...*(Interruptions)*... Do not interrupt him. ...*(Interruptions)*... If at all you do not agree with him, then, when your turn comes, you can speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is a debate. ...*(Interruptions)*... But when there is a Cabinet Minister, who is going to reply to the questions, what is the reason for him to respond? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No; he is speaking on behalf of his Party. ...*(Interruptions)*... The Minister will reply later. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: There are so many Members. ...*(Interruptions)*... There are more Members who want to speak. ...*(Interruptions)*... You should allow your Members to speak. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): No, no. He is speaking on behalf of his Party. ...*(Interruptions)*... The Minister can speak. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः वे इस हाउस के सदस्य हैं और उनको यह अधिकार है कि वे बोलें। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes, as a Member. ...*(Interruptions)*... Mr. Digvijaya, I will tell you. ...*(Interruptions)*... Though he is a Minister, he is entitled to speak as a Member of this House. ...*(Interruptions)*... No, please. ...*(Interruptions)*... Their turn has come. ...*(Interruptions)*... Their Party's turn has

come and he is speaking on behalf of his Party. *...(Interruptions)...* He is not speaking in the capacity of a Minister but as a Member of this House. *...(Interruptions)...*

श्री परषोत्तम रूपालाः सर, मैंने सभा गृह के सामने तथ्या क्या रखा, क्या मेरी शोभा भी मिट गई? मैंने सभा गृह के सामने एक तथ्य रखा, अभी मैंने कोई नई बात तो कही नहीं। मैंने जो देखा था, वह मैंने कहा, एक किसान के नाते कहा। क्या मैं इससे शोभा के लायक भी नहीं रहा? क्या मुझे अपनी शोभा के लिए जो fact है, वह यहाँ नहीं रखना है?

सर, इस देश में यह बहुत सालों तक चलता रहा। कहीं हम न्यूजपेपर्स में पढ़ते थे कि किसी ने लट्ठा पी लिया और मर गया, तो सरकार की ओर से उसको मुआवजा मिलता है। ऐसा मैंने देखा भी है और सुना भी है। किसान खेती करने के लिए देश की जनता का पेट भरने के लिए जाता है। वहाँ उसको बिच्छू काटता है, साँप काटता है, thrasher में उसका हाथ चला जाता है और वह मर भी जाता है, तो क्या उसके लिए कोई व्यवस्था है? ...**(व्यवधान)**...

श्री शादी लाल बत्रा (हरियाणा): हरियाणा में 5 लाख रुपए मिलते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री परषोत्तम रूपालाः इनका क्या सम्बन्ध है, अभी मुझे इनका सम्बन्ध भी बताना है। ...**(व्यवधान)**... मैं बताऊंगा। ...**(व्यवधान)**... मैं बताऊँगा ...**(व्यवधान)**... मैं बताऊँगा। ...**(व्यवधान)**... मैंने इसीलिए तो इसे शुरू किया था कि जो लट्ठा पीकर मर जाता है, उसके लिए प्रावधान है, लेकिन किसानों के लिए यह प्रावधान नहीं था, जो हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में, अगर वहाँ इसके चलते अकस्मात किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने उसके लिए एक लाख रुपए देने का प्रावधान किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): अखिलेश जी के समय में 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ...**(व्यवधान)**...

† **جناب جاوید علی خان** : اکھلیش جی کے وقت میں پانچ لاکھ روپے کا پراودھان کیا گیا ...(مداخلت)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please. *...(Interruptions)...*

श्री परषोत्तम रूपालाः अभी तो इसका प्रावधान सभी जगहों पर हो गया है। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें किसानों के साथ होती रहीं और इसके बारे में इस सभा गृह के माध्यम से हमें जानने को मिला। मैं उन सभी सांसदों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में जो अच्छी practice हो रही है, उसे सदन के सामने रखने की कोशिश की। जैसे कर्णाटक में मंडी में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, e-NAM मंडी में। देश के सभी प्रांतों में इसकी शुरुआत कैसे हो, हमें इस दिशा में सोचना चाहिए। पश्चिमी बंगाल की ओर से यह जानने को मिला है कि किसानों की फसल बीमा योजना का प्रीमियम वहाँ की सरकार bear कर रही है। यह अच्छी बात है। लोक सभा में तेलंगाना के किसी

†Transliteration in Urdu script.

[श्री परषोत्तम रूपाला]

सदस्य ने बताया था कि उनकी सरकार वहाँ खाद, बीज वगैरह के लिए किसानों की मदद कर रही है। यह अच्छी बात है। कुल मिला कर मेरे कहने का इतना ही मतलब था कि राज्यों ने जो भी अच्छी practice शुरू की हैं, चाहे वह कर्ज माफी की हो, किसानों की मदद की हो, वे सारी practices सभी राज्यों में हम संकलित रूप से कैसे शुरू कर सकें, इस प्रकार की राय इस सदन की बने, उस दिशा में इस चर्चा को हमें ले जाना चाहिए, यह मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। सर, हमारे जो भी सांसद किसानों की समस्याओं के बारे में बता रहे थे, वे ज्यादातर pesticides के उपयोग, कृषि के स्वास्थ्य और किसानों को ऋण दिए जाने के बारे में बता रहे थे। ये सब चिन्ताएं माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने प्रान्तों के बारे में बताई गईं। वे सदन से अपने अनुभव शेयर कर रहे थे।

महोदय, शायद श्री दिग्विजय सिंह जी ने अपने प्रवचन में भी बताया था कि पानी का समुचित उपयोग करना चाहिए। मुझे यह बताते हुए फख्र हो रहा है ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः मैं प्रवचन ही कर रहा था। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसादः अब श्री दिग्विजय सिंह जी नर्मदा नदी की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहां उन्हें साल भर प्रवचन ही करने हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आप यह देखिए कि दिग्विजय सिंह जी का प्रवचन कितना लोकप्रिय हुआ। ...**(व्यवधान)**...

श्री परषोत्तम रूपालाः महोदय, एक अच्छी प्रैक्टिस के नाते, मैं बताना चाहूंगा कि हमने गुजरात में लोक भागीदारी से पानी को रोकने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। चेक डैम बनाने में लोक भागीदारी और सरकार, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, जिसके कारण भूगर्भ स्तर का लैवल बढ़ाने में बहुत सहायता मिली। अब इसे किस प्रकार से राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, इस बारे में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो घोषणाएं हमारे किसानों के हित में की थीं, उनमें सबसे अच्छी घोषणा यदि मैं किसान होने के नाते कहूं, तो वह मुझे "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" लगी। देश में जो बांध किसी न किसी कारण 5 साल से 25 साल तक आधे-अधूरे पड़े थे, जिसके कारण जो पानी समुद्र में जा रहा था, उसे किसानों के खेत में जाना चाहिए था, वह वहां नहीं पहुंच रहा था। इसलिए उस पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाने के लिए 5 साल से 25 साल तक के अधूरे बांधों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक इस योजना के तहत 22 योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आप चाहेंगे, तो मैं उन कंप्लीट योजनाओं के नाम भी आपको बता सकता हूं।

महोदय, मैं एक और बात माननीय सदन के सदस्यों के लिए कहना चाहता हूं कि "प्रधान मंत्री सिंचाई योजना" के माध्यम से हर जिले का irrigation plan बन रहा है। इसलिए हम सभी सांसदों के ध्यान में यह बात होनी चाहिए और अपने-अपने क्षेत्र का अच्छे से अच्छा इरिगेशन प्लान बने, इस बारे में हम सभी को अपनी-अपनी सहभागिता करनी चाहिए। अतः हमें जिले को अपना नेतृत्व देना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि किस जिले में क्या potential है, क्या करना चाहिए और कैसे करना

चाहिए। इस प्रकार से जब प्लान बनेगा, तो केन्द्र सरकार की ओर से भी ऐसी योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है।

महोदय, drip irrigation का जो मुद्दा है, वह प्रधान मंत्री जी के प्रवचनों का एक अहम मुद्दा है, जिसमें उन्होंने 'Per Drop, More Crop" पर जोर दिया है। इसके कारण, पूरे राष्ट्र में ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Rupalaji, please conclude.

श्री परषोत्तम रूपालाः सर, मैं एक बात कह कर अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा।

महोदय, इस योजना के माध्यम से किसान पानी का सही उपयोग करें और इस काम के लिए जो सहायता केन्द्र और राज्यों की ओर से मिल रही है, उसका लाभ उठाएं। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इस बारे में उन्हें aware करें, क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में वे लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन तक हमारी ये योजनाएं पहुंचें। मुझे आशा है कि आप सब इसमें सहभागी बनेंगे।

महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी के प्रवचनों में दो-तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके कारण मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यदि किसी के प्रवचन बहुत ज्यादा गौर से सुने गए हैं, तो वे प्रधान मंत्री जी के प्रवचन हैं, जो उन्होंने प्रधान मंत्री बनने से पहले, यानी चुनाव के दौरान दिए थे। उन्हें देश की जनता ने भी बहुत गौर से सुना है और सुना ही नहीं, बल्कि देश की जनता ने इसके लिए बहुत दाद भी दी है, धन्यवाद।

श्री संजय राउत : सर, किसानों की हालत, खेती की हालत, इस बारे में एक अच्छी डिबेट यहाँ चल रही है। प्रभात झा साहब और रुपाला साहब के भाषण के बाद, मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलने के लिए हमारे पास बचा है। आपने दोनों तरफ से थोबड़ा फोड़ दिया है। पहले प्रभात झा साहब ने फोड़ दिया था और एक आपने फोड़ा है। ...**(व्यवधान)**... जिसका फोड़ना था, उसका फोड़ दिया, सबको मालूम है। ...**(व्यवधान)**...

सर, मैं रजनी ताई पाटिल का भाषण सुन रहा था। वे हमारे महाराष्ट्र की एक तेज-तर्रार नेता हैं। रजनी ताई, मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने - महाराष्ट्र में हमारी सरकार, जो तीन साल से चल रही है, उसमें गरीब किसान कैसे आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की हालत क्या है, इस पर मैं आपकी संवेदना समझ सकता हूँ। लेकिन आपको यह हिसाब देना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में, 10 सालों में, सिर्फ विदर्भ में 30,000 किसानों ने आत्महत्याएँ कीं। ...**(व्यवधान)**... वहाँ 30,000 से भी ज्यादा और आपके मराठवाड़ा में 8,000 किसान। यह जो 30,000 का और 8,000 का आंकड़ा है, यह एक चिन्ता का विषय तब भी था और आज भी है। आत्महत्या अब तक रुकी नहीं है, चल रही है, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज की सरकार एक कोशिश कर रही है कि किसान जिन्दा रहे, किसानों के परिवार जिन्दा रहें।

आज सुबह सेंट्रल हॉल में हमारे नये राष्ट्रपति महामहिम जी का भाषण मैं सुन रहा था। राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। अगर किसान राष्ट्र निर्माण का कार्य

[श्री संजय राउत]

करता है, तो राष्ट्र निर्माण का कार्य करने वाला किसान 60 सालों में ऐसी हालत में पहुँच गया है कि अब उसको खेती करना एक संकट लगता है। वह खेती छोड़ रहा है। दूसरी बात, महाराष्ट्र जैसे राज्य में किसान – इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, कि किसान कभी हड़ताल पर गया है, लेकिन आप हँसो मत, रजनी ताई, इस बात की 60 सालों से उनके मन में जो चिढ़ थी, वह अब निकल गई। किसान जो 60 सालों से अंदर ही अंदर मर रहा था, उसका एक विस्फोट हुआ और किसान हड़ताल पर चले गये। 20-25 दिनों तक किसानों ने कोई काम नहीं किया, चाहे वह अनाज हो या दूध, फल हो या सब्जी हो। किसान को क्या हुआ? क्या किसान पागल हो गया है कि अपना उगाया हुआ अनाज वह रास्ते पर लाकर फेंक देता है? न वह अपने लिए कमायेगा और न ही हमारे लिए कमायेगा! इस परिस्थिति में किसान को कौन लाया? यह कोई आज की बात नहीं है। हमें, सबको इस बारे में, इस सदन में चर्चा करनी चाहिए। योजनाएँ बनती हैं। पहले भी प्रधान मंत्री जी ने कुछ अच्छी योजनाएँ घोषित कीं, हमारे प्रधान मंत्री जी भी करेंगे, लेकिन जीने के लिए जो पैसे चाहिए और कृषि उपज को बाजार में बेचने के बाद किसान को कितना पैसा मिलता है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। क्या किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल पाता है, या नहीं, सिर्फ उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। किसान हर महीने कितने रुपये कमा पाता है, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। बाकी तो रुपाला साहब, आपने बताया है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करने जा रही है और सरकार काम भी करेगी। आज हमारे देश में हमारी चर्चा गोरक्षा के मामले में होती है। हम मानते हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए। यह हमारा धर्म है, कर्त्तव्य है, लेकिन हमारा किसान जो मर रहा है, वह भी हत्या है, किसानों का परिवार मर रहा है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, इसलिए गौर-रक्षा के साथ-साथ किसानों की भी रक्षा होनी चाहिए। हमें उनके परिवार को संभालना चाहिए। उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री जी इज़राइल जाकर आए, इज़राइल की डिफेंस हो या कृषि हो, किसानी हो, वह एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र है, एक क्रांतिकारी राष्ट्र है, वहां कम पानी होने के बावजूद उन्होंने किसानी में, खेती में, कृषि में जो प्रगति की है, हमें उनसे कुछ सीखना भी चाहिए, लेकिन हमने इज़राइल से क्या सीखा? हमारे बड़े-बड़े डेलिगेशन वहां जाते हैं, राज्य के जाते हैं, देश के जाते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए कि वहां का किसान लाचार नहीं है। ...**(समय की घंटी)**... वहां 'किसान' शब्द का प्रयोग हमारी तरह नहीं होता है। हमारे यहां का किसान चेरिटेबल ट्रस्ट है, वह दया के ऊपर जीता है, लेकिन इज़राइल का किसान चेरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां का किसान कभी आत्महत्या नहीं करता है। वह क्यों नहीं करता है, इस बारे में हमें बहस करनी चाहिए। हमारे यहां की खेती घाटे का सौदा क्यों बनी है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह देखना पड़ेगा।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, योगी आदित्यनाथ जी का अभिनन्दन करता हूँ, उन्होंने मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद, दूसरे ही दिन ऋण मुक्ति की घोषणा की। चूंकि योगी जी ने इसकी घोषणा की, इसलिए महाराष्ट्र को भी ऋण मुक्ति करनी पड़ी। यह मैं आपको बता दूं कि हमने उनसे प्रेरणा ली है। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवईः उससे पहले पंजाब में हुआ था। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउतः हमने 15 साल तक संघर्ष किया था, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। ...**(व्यवधान)**... 15 साल के बाद योगी जी ने घोषणा की, ...**(समय की घंटी)**... वहां पर मुख्य मंत्री हमारे हैं, तब हमने कहा कि जब यह काम योगी जी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please.

श्री हुसैन दलवईः सर, ये गलत बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... पहले पंजाब में हुआ था। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउतः हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। ...**(व्यवधान)**... यह जो ऋण मुक्ति का आंदोलन शुरू किया गया था, उसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ रही है। ...**(व्यवधान)**... शिवसेना पार्टी के श्री उद्धव ठाकरे जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है और आज भी ऋण मुक्ति की घोषणा होने के बाद ...**(समय की घंटी)**... जैसा आपने कहा कि कुछ मिला नहीं है, हम यह मानते हैं, लेकिन अभी इसका प्रोसेस शुरू है। कितने किसानों को इसका लाभ मिला है, कितने किसान ऋण मुक्त हुए हैं, हमने सरकार से इसकी लिस्ट भी मांगी है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Mr. Sanjay, address the Chair and please conclude.

श्री संजय राउतः सर, हमने महाराष्ट्र सरकार और बैंकों से यह भी मांग की है कि आपने जिन 36 लाख किसानों की ऋण मुक्ति की घोषणा की है, इन 36 लाख किसानों की लिस्ट आप declare कीजिए ताकि यह पता चल सके कि इससे किसको-किसको लाभ मिला है। हम यह भी एक बड़ा काम कर रहे हैं। जिस किसी भी किसान को ऋण मुक्ति का लाभ मिलना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलेगा।

रजनी ताई, आपने कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात की। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव मूवमेंट का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट की हालत क्या है? शुगर फैक्ट्रीज़ हों या और कुछ हो, यह हालत तीन साल की नहीं है, जो आप बोल रही थीं। ...**(समय की घंटी)**... हमारे पास या यहां महाराष्ट्र के जो लोग बैठे हैं, उनके पास कितनी शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब आपके पास हैं, कांग्रेस के पास है, एनसीपी के पास है, हमारे पास क्या है? ...**(व्यवधान)**...

श्री रजनी पाटिल : आपके पास नहीं है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

श्री संजय राउतः अभी हम बनाना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... बेच कर खाने वाले शुगर फैक्ट्रीज़ में ये कौन लोग हैं? कोऑपरेटिव बैंक है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please conclude.

श्री संजय राउतः सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। चाहे यहां के लोग हों या वहां के लोग हों, किसान, उनकी आत्महत्या, किसानी, खेती, हमें इस पर राजनीति से ऊपर उठ कर बात करनी चाहिए। मैं रुपाला साहब के भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। आपको बीच-बीच में यहां आकर सदन को संबोधित करना चाहिए।

सर, मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत-से विषय हैं, किसानों की खुदकुशी रातों-रात खत्म नहीं हो सकती है और दूसरी बात यह है कि अगर किसान जिएगा, तो देश बचेगा, यह ध्यान रखना चाहिए, धन्यवाद।

THE VICE-CHIRMAN (SHRI TIRUCHISIVA) : Thank you, Mr. Sanjay Rout. Shri D. Raja.

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश) **:** किसानों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, इस पर भी बता दीजिए। उनके बच्चों का क्या भविष्य है? खेती तो लोग करना चाहते नहीं है।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. Today, we had the opportunity to listen to the Address given by the newly-elected President after he took oath in the Central Hall of the Parliament. In fact, the newly- elected President referred to those people empowering the new India, building the nation. I would like to remind the House of one thing. I would like to refer to one former President at this point of time. The former President is none other than Mr. K.R. Narayanan. He made a speech. He addressed the nation, in fact, on the eve of the Republic Day on 25th January, 2000. I quote what Mr. K.R. Narayanan had said. "On three way fast lane of liberalization, privatization, and globalization, we must provide safe pedestrian crossings for the unempowered India so that it too can move forward, equality of status and opportunity. Beware of the fury of the passioned man, says the old adage. One could say, beware of the fury of the passioned and long suffering people. They are the Indian farmers; they are the Indian kisans, and the whole country is witnessing the fury of those passioned, long suffering kisans of this country." That is why, my party also, along with other parties, has been organizing countrywide protests. Thousands of people have been picketing, and courting arrest; yesterday, today, and it will happen tomorrow also. But, Sir, agrarian crisis is real, let us admit it, and it is acute also. While even one farmer committing suicide out of increased indebtedness or from lack of remunerative prices, it should sadden us, it should be unacceptable to every one, unacceptable to you, unacceptable to me, and every one, it should sadden us, and the high number of suicides officially admitted, speak for themselves. So, how are we going to address these issues? It is a fact that agriculture output has been volatile. Eighty-six per cent of holdings are less than two acres; informal sources of credit consitute forty per cent of loans; these are all data available in public domain. What are the key issues? We must have long term approach, we should have the short term approach. The short term approach, because the farmers are passing through unprecedented distress, and they must be saved, they must be rescued, for which I think,

the Government should seriously think of loan waiver, interest waiver. Several States have done it, and why can't the Centre take initiative? That is what I am asking. What is the role of the Central Government, Union Government? And there is a demand to consitute a Debt Relief Commission. Can you think of constituing a Debt Relief Commission? It is there in States like Kerala. We will have to address certain key issues, Sir. What are the key issues which we confront today? One, increasingly, there is a decline in cultivable agricultural land for various reasons. There is continuous dependence on monsoon whether monsoon will be all right or monsoon will fail. There is inadequate access to irrigation, imbalanced use of soil nutrients, uneven access to modern technology, lack of access to formal agricultural credit, limited procurement of foodgrains by Government agencies and failure to provide remunerative price to the farmers. These are the key issues which we should address. As a nation, as a Government, as a Parliament, how can we address these key issues? This is where the Government will have to apply its mind. How can you ensure remunerative price? Dr. Swaminathan was our esteemed colleague. We all know him. Everybody refers to Swaminathan Commission Report. What about Ramesh Chand Committee Report which has been constituted for MSP fixing methodology? They have given certain equations how it should be C2 plus 50 per cent. It is there. Why are you not implementing that? This is what I am asking. If we are concerned about farmers, why can't we think of implementing the very Committees which you constitute, the Government constitutes? I am not asking for anything else, anything beyond that. You constituted a Commission, why did you constitute that Commission? What is the purpose of constituting such Commissions? They give Reports and these Reports are kept in cold storage. Farmers are dying and committing suicide and we are crying here on the floor of the Parliament. If you think Parliament is supreme, I am asking you in the name of Parliament, why can't you implement those recommendations and ensure remunerative price for the farmers? On the one side you allow the cost of inputs to go up because they are all agri-business corporations. So, you support the agri-business corporations, let them increase the prices of fertilizer, let them increase the price of seeds, let them increase the price of everything. But farmers cannot get remunerative price. The farmers go to private money lenders, farmers go to other lending agencies. Finally, what happens? My good friend, Prof. Ram Gopal Yadav, was referring to Pt. Nehru that anything can wait but not agriculture. But I refer to other economist who said that Indian farmers are born in debt, Indians farmers live in debt, and Indian farmers die in debt. Is it what we want? They are the people who produce food for the whole nation. Why did you pass this Food Security Act, 2013? I am asking you. We passed it because we want food security for our citizens and this food security is given by farmers. For instance, the Food and Agricultural

[Shri D. Raja]

Organization, FAO, defines food security as a situation where all people have at all times physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets the dietary needs and food preferences for a healthy and active life. This is the FAO of the United Nations. Sir, as Members of Parliament, we may belong to different parties, but we should think of our people. Our people should have decent living, our people should have food and our people should not starve. Here in this case the very food producers are dying. How can we tolerate this, Sir? That is why I am pleading with you. There are certain other issues. We are talking of doubling the income. Is there any Farmers' Income Commission in this country? How can you ensure doubling the income of the farmers? How can you ensure providing pension to the farmers? There are many problems, Sir. Another serious issue is that we are having water problem. It has become a precious one. I know there are several river water disputes and there are several tribunals. Whatever Awards Tribunals gave in the past are not being implemented! The Cauvery Management Board has not been constituted! The problem is this. The inter-State river disputes must be settled and the time has come we should think of interlinking of rivers. It will help us to improve our agriculture. ...*(Time-bell rings)*... I am concluding, Sir. I take the example of Tamil Nadu and it is also applicable to other States. The size of cultivable land is declining! For instance, in Tamil Nadu, GAIL's pipeline goes through the entire Western part of Tamil Nadu. Farmers are asking it to have along the national highways and not to lay it through cultivable lands as it affects agriculture. But, GAIL and the Government of India are not listening!

Tamil Nadu farmers are fighting against hydrocarbon project at Neduvasal. Nobody knows how it was conceived. People have serious doubts. It will suck away the entire groundwater. It will destroy agriculture. So, there is a demand that Thanjavur, Tiruchirapalli, Thiruvarur, Nagapattinam should be declared as an exclusive agricultural zone.

SHRI DEREK O'BRIEN: You are speaking for Tamil Nadu. What about other States?

SHRI D. RAJA: Sir, I am speaking for the entire country. I speak for Punjab. I speak for Haryana. I speak for Maharashtra. When farmers commit suicide in Marathwada, my heart bleeds. I shed tears as to why my Marathi farmers should commit suicide.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Yes, Mr. Raja. Please, look at the clock.

SHRI D. RAJA: Sir, one Karnataka farmer committed suicide. I felt sad. Why our people should die like that? And, if farmers pass through such distress in Odisha, I feel sad. Why? We have perennial rivers and ordinary rivers. What are we not having in this country? We have everything. We are blessed with such a beautiful nature. We have such a fertile land. We have hard working, toiling and energetic people who are building the nation.

Finally, when it comes to life, what life does a farmer have? What life does an agricultural worker have? What is their living condition, Sir? Go to any village. Look at the living condition of agricultural worker. How can we sleep peacefully? So, Sir, my humble request is that the Government should address these issues with a sense of urgency, with all seriousness and the Government should take short and long-term measures to save agriculture, farmers, agriculture workers and India. Thank you.

डा. संजय सिंह (असम): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 2014 के बाद एक बड़ी कैटेगरी आई भक्तों की। उन्होंने हर जगह कहना शुरू किया कि यह सरकार बड़ा जबर्दस्त काम कर रही है। लोगों ने पूछा कि ऐसा जबर्दस्त क्या किया? उन्होंने कहा कि दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन जबर्दस्त काम हो रहा है और समय बताएगा और इसी में तीन साल निकल गए। भक्तों ने कहा कि हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि ने समुद्र का पानी पी लिया था, यह तो 2014 में हिन्द महासागर में पानी आया है। 70 साल पहले देश आजाद हो गया, 60 साल तक जनता कांग्रेस को वोट देती रही, लेकिन कांग्रेस के जमाने में कुछ हुआ नहीं। पहले तो रेगिस्तान प्रधान देश था, अब 2014 के बाद कृषि प्रधान देश बना है। मान्यवर, आज तो हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के दुख, तकलीफ और उनकी आत्महत्या पर... मैं कोई data नहीं बता रहा हूं। अभी दो-तीन दिन पहले मैं जंतर-मंतर पर गया था। वहां तमिलनाडु के किसान जिस तरह से कपड़े उतारकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं - वहां सैंकड़ों किसानों के नरकंकाल, आत्महत्या किए हुए किसानों के अवशेष जंतर-मंतर पर सड़कों पर पड़े हैं। आज वे भले ही सत्ता पक्ष से कह दें कि कांग्रेस के समय में क्या आत्महत्याएं नहीं हुईं - इसलिए आत्महत्या जायज़ हैं, ठीक है, हो रही है! मैं तो मान लूंगा कि आपने तीन साल में बहुत अच्छा काम किया, खेती बहुत अधिक सुधर गयी है, किसान की हालत सुधर गयी है अगर एक भी आत्महत्या न हो, तो मैं मान लूंगा कि आपका काम बहुत अच्छा है। अगर आप data देखें तो पहले से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। आप कोई भी data उठा लीजिए, आप देखेंगे कि वह हर तरह से नीचे जा रहा है, किसान की हालत खराब है। चाहे ऋण माफी का मामला हो, ऋण माफी का बहुत गाना गाया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऋण माफी की चर्चा हुई, मध्य प्रदेश में हुई। आप देखें कि केवल उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कितने परसेंट किसानों का, जो किसान कर्ज़दार थे, उनका कितने परसेंट ऋण माफ हुआ। आप देखिए, जहां-जहां घोषणाएं हो रही हैं, वास्तव में कितने किसानों को उससे लाभ हो रहा है - इसको भी देखने की आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश में किसानों के द्वारा ऋण माफी की डिमांड हुई, आपने तब ऋण माफ किया, जब मध्य प्रदेश में कई लोग मर गए, गोली चली, लाठी चली,

[डा. संजय सिंह]

उत्तर प्रदेश में लोगों ने डिमांड की। आज हिन्दुस्तान का किसान सबसे बड़ा unorganized sector है। किसानों का कोई संगठन नहीं है, भले ही उनकी कोई यूनियन हो, कुछ हो, लेकिन उनकी एक आवाज़ कहीं से नहीं निकल पाती। मैं आज यह भी बता दूं, सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि जिस कृषक वर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, वह सिंचाई के पानी के लिए भगवान के भरोसे है। आज अगर सरकारी कांटे में खरीद लिया गया तो उसका अनाज का दाम मिल जाता है और वह category, जो अनाज को बेचकर अपनी बेटी की शादी का इंतज़ाम करती है, अपने बच्चे की फीस का इंतजाम करती है, जिसकी land holding कम है और जो अपनी पैदावार को हफ्ते भर से ज्यादा hold नहीं कर सकता है, आज सबसे ज्यादा उसी वर्ग के बारे में हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, मैं दो-तीन बातें कह रहा हूं, अगर आप कर दें तो इस देश के किसान की हालत ठीक हो जायेगी, इस देश का जो अन्नदाता है, जिसने आज हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखा है, जिसकी वजह से हम अपने पैरों पर खड़े हैं - जो वह पैदा करता है, अगर आप एक हफ्ते के अंदर उसे खरीदकर उसका उचित दाम उसको दे दें तो मैं आपको बता रहा हूं कि उससे देश की स्थिति सुधर जाएगी। खेती करने वाला किसान जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, हर odd स्थिति में काम करता है - उसे सही टाइम पर बिजली नहीं मिलती है, सही टाइम पर पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, इस सबके बावजूद वह खेती करता है। उसके लिए आप यह कर दें क्योंकि आज खेती वह किसान करता है, लेकिन उससे ज्यादा लाभ आढ़ती कमाता है, middle man कमाता है। आप जितने भी नारे लगा दें कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, जबर्दस्त काम हो रहा है, कृषि में इतना काम हो गया है, आप data बता दें, slogans सुना दें, लेकिन हर जगह आप देखिए - फर्रुखाबाद में आलू का हाल क्या है? आपने मंडियों में eNAM चला दिया कि पूरे देश में किसान कहीं भी अपनी पैदावार को बेच सकता है। आज आप देखिंए, मडियों में जितनी खरीद-फरोख्त होती है, उसका एक परसेंट भी eNAM से नहीं हुआ। यहां data की बात करना, announce करना, नारे लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं। आज महाराष्ट्र में प्याज़ की हालत क्या है, कर्णाटक में टमाटर की क्या हालत है, मध्य प्रदेश में लहसुन और मेथी का क्या हाल है - इस सबको आप देखिए। आपने नोटबंदी कर दी और कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, cashless society हो गयी - ठीक है, पूरा देश cashless हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज मंडियों में कैसे क्या होता है - क्या card से होता है या क्या cash से होता है? आज जितना नुकसान नोटबंदी से हुआ है, अगर इसकी आप ठीक से बैठकर जांच करें और इस पर विचार करें तो आपको समझ में आ जाएगा।

माननीय महोदय, इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में कहा गया। जब देश में पैदावार बढ़ती है तो आप इम्पोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि कम्पनीज़ का फायदा हो या वाकई किसान का फायदा हो? अगर आपके यहां पैदावार हो रही है तो उसका सही दाम उसे तभी मिल सकता है, जब उसका बाहर से इम्पोर्ट बंद हो। मान्यवर, इसके बारे में आप गंभीरता से सोचें। फसल बीमा योजना में आप जांच कर लें कि किसानों को फायदा हुआ या प्राइवेट कम्पनीज़ को ज्यादा फायदा हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारा मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो या हम चाहते हैं कि technology के नाम पर तमाम बातें हों? ...**(समय की घंटी)**... उपसभाध्यक्ष

महोदय, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में कुछ नहीं हुआ है। मैं दो-तीन चीज़ें बताना चाहता हूं, इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा सा पढ़ने का वक्त दे दीजिए। कांग्रेस के regime में एक्सपोर्ट सात गुणा ज्यादा बढ़ा था। India became world's number one exporter of rice ahead of Thailand and Vietnam. India became number two exporter of cotton after the US. Cotton exports contracted by 62 per cent from what it was in 2011-12, that is, during the Congress regime. It was 4.3 billion dollars in 2011-12, and it came down to 1.6 billion dollars in 2016-17. Soyabean-meal exports plunged from ₹ 14,000 crore in 2012-13 to a mere ₹ 1,500 crore in 2015-16. Tractors' sale rose from 1.90 lakh units in 2003-04 to 6.34 lakh units in 2013-14, indicating prosperity of the farmers. Tractors sale came down to 4.94 lakh units in 2015-16, which shows the cold shoulder treatment meted out to agriculture by the Modi Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you.

डा. संजय सिंहः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक अंतिम निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

अंत में, मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बढ़िया नारा है, मैं आज भी कहता हूं कि "सबका साथ, सबका विकास", लेकिन देश इसको सही तब मानेगा, इसका मजाक नहीं उड़ायेगा, जब आप वास्तव में इस पर खुद चलना शुरू करें। आप यह दिखाइए कि हम "सबका साथ, सबका विकास" करना चाहते हैं। आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस देश के माहौल को ठीक करना है, इसके बिना खेत तो रहेगा, लेकिन खेती नहीं रहेगी, ऐसे ही किसान मरते रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय रहेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी और जो वातावरण विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में हो रहा है, उस पर आप स्वयं ध्यान दे सकते हैं। उद्योग होंगे, लेकिन लाभकारी व्यापार नहीं होगा। पुलिस, पैरा-मिलिट्री फोर्सेज़ और आर्मी रहेगी, लेकिन न रक्षा होगी, न सुरक्षा होगी और न शांति होगी। यह संसद थी, है और रहेगी। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि सार्थक और सकारात्मक चर्चा का माहौल जारी रहे, तो आपको माहौल ठीक करना होगा और यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

श्री राम नारायण डूडी (राजस्थान)**:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्याओं पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा में अपने विचार रखे और कांग्रेस के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद 60 साल तक इस देश पर कांग्रेस की सरकार की नीतियां चली, तो उनकी जो नीतियां थीं, उन्हीं के चलते किसानों के सामने आज समस्याएं खड़ी हुई हैं और आज वे कह रहे हैं कि आपकी नीतियों की बदौलत किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं उन महानुभावों से यह कहना चाहूंगा कि हमें जुम्मा-जुम्मा तीन साल हुए हैं और इन तीन सालों के अंदर हमारी जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज हमारी नीतियां जिस प्रकार से काम में ली जा रही हैं, उनके संबंध

[श्री राम नारायण डूडी]

में मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपकी जो 60 साल की नीतियां रही हैं, उनके कारण किसान कमजोर हुए हैं। यदि किसी ने किसान को कमजोर किया है, तो उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल और केवल कांग्रेस की नीतियों ने किया है। जब देश के अंदर अनाज की कमी थी, उस वक्त हम बाहर से अनाज मंगाते थे, बाहर से अनाज मंगाने पर हमें जिस प्रकार के संकटों या मनमानी शर्तों का सामना करना पड़ता था, उस वक्त इस देश के किसानों ने इसको एक चैलेंज समझ कर, इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किया। अगर इस देश को किसी ने आत्मनिर्भर किया है, तो इस देश के किसानों ने किया है। आज 60 परसेंट काश्तकार लोग खेती पर निर्भर हैं। और उस challenge को स्वीकार करते हुए देश के किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाया, इस के लिए मैं उन किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज वही किसान आत्महत्या कर रहा है।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

महोदय, ये आत्महत्याएं किसान को फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण हो रही हैं क्योंकि उसकी उपज पर लागत ज्यादा आती है और उचित मूल्य न मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर होती जाती है। इस कारण उसके सामने कई तरह के खर्चे आ जाते हैं और जब उन खर्चों की वह भरपाई नहीं कर पाता है और साहूकार पैसे मांगने आ जाता है, तो मजबूरी में वह आत्महत्या करता है। आज देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हालात हैं, जिन के कारण अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग फसलें पैदा होती हैं, लेकिन उन फसलों का सही दाम निर्धारित न होने से किसान की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गयी है। इसे सुधारने के लिए कई बार सोचा गया। ...**(व्यवधान)**... महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार थी, उस वक्त भी किसानों का कर्ज़ा माफ किया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय में भी किसानों का कर्ज़ा माफ किया गया, लेकिन इस से समस्या का हल नहीं हुआ। महोदय, जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होता, जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, जब तक उसे अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। महोदय, कर्ज़ा माफ होना अलग बात है। यह तो एक सुविधा है। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। उन योजनाओं के अंदर कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि मृदा जांच करना। जहां काश्तकार को यह पता ही नहीं है कि उसे अपने खेत में किस प्रकार का बीज बोना चाहिए, किस प्रकार की खाद देनी चाहिए, किस प्रकार से खेती करनी चाहिए, यदि वह इन सब चीज़ों का सही आधार बनाकर खेती करेगा तो उसकी आय दोगुनी होगी। यह असली वजह है क्योंकि आज तक आपने किसी प्रकार का नवाचार नहीं किया और उस के अभाव में हमारा किसान पिछड़ता चला गया। आप सिर्फ उनके वोट लेने तक ही सीमित रहे।

उपसभापति महोदय, मैं एक उदाहरण यहां रखना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में मुख्य मंत्री जी ने "जल स्वावलंबन" योजना प्रारंभ की है। उसे first phase में 350 पंचायतों में शुरू किया गया है और second phase में और 4200 पंचायतों में करना तय हुआ है। इस तरह से हम पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री "जल स्वावलंबन" योजना के आधार पर पूरे प्रदेश में सिंचाई सुविधा develop करना चाहते हैं।

श्री उपसभापतिः डूडी जी, अब conclude करिए।

श्री राम नारायण डूडीः उपसभापति महोदय, जब तक काश्तकार के प्रति हमारे मन में संवेदना नहीं होगी, तब तक उनका हित नहीं होगा। मैं उस वक्त का थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस वक्त वसुंधरा जी की सरकार में मैं राजस्व मंत्री था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay Dudiji, please.

श्री राम नारायण डूडीः महोदय, कांग्रेस गवर्नमेंट के शासन में काश्तकारों से 18 परसेंट ब्याज और late payment पर 6 परसेंट की penalty ली जाती थी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Shri Ram Kumar Kashyap. ...*(Interruptions)*...

श्री राम नारायण डूडीः और किसानों के खेत नीलाम होते थे। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, हम लोगों ने 6 परसेंट penalty को खत्म किया।

श्री उपसभापतिः अब समाप्त कीजिए, 6 मिनट हो गए हैं।

श्री राम नारायण डूडीः और ब्याज को 18 परसेंट से 12 परसेंट पर लाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Kumar Kashyap, you have got only five minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री राम नारायण डूडीः महोदय, इस तरह यह संवेदनशीलता हमारी सरकार के अंदर है। यह पहले भी थी, आज भी है...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Kumar Kashyap, take only five minutes. ...*(Interruptions)*...

श्री राम नारायण डूडीः और हम उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Kashyap. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, now it is six o'clock. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the time should be extended and it should be disposed of today. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: No, Sir; tomorrow. Tomorrow. ...*(Interruptions)*...

6.00 P.M.

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): सर, आपने मुझे किसानों की समस्याओं के संबंध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। **...(व्यवधान)...**

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the Minister will give a good reply tomorrow. *...(Interruptions)...* Take the sense of the House. Since we all have had a good debate, the Minister can be requested to reply tomorrow at 2.00 p.m. *...(Interruptions)...*

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, it is already 6 o'clock. The Minister can make a reply tomorrow. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What does the Parliamentary Affairs Minister have to say?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, better तो यही होता कि आज ही reply हो जाता, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछ लें कि वे कितनी देर तक reply करेंगे। इस पर बोलने वाले कितने मेम्बर्स रह गए हैं?

श्री उपसभापति: इस पर बोलने वाले 3 मेम्बर्स हैं। इसका मतलब यदि एक मेम्बर पांच मिनट लेगा, तो कुल 15 मिनट लगेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): सर, माननीय सदस्यों द्वारा यहां जितने विषय उठाए गए हैं, निश्चित रूप से उसका उत्तर नहीं, लेकिन जो सही जानकारी है, इस सदन के माध्यम से सभी लोगों को मिलनी चाहिए। पिछली बार यह स्थिति थी कि पूरा विषय नहीं आ पाया था। जैसे "फसल बीमा योजना" है, इस पर जो बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो तथ्य है, वह सदन के सामने आना चाहिए, जैसे "कृषि बाजार योजना" है, हमें इसके लिए अधिक समय चाहिए। हम पिछली बार भी पूरा नहीं बोल पाए थे।

श्री उपसभापति: इसका मतलब यह है कि आप बोल रहे हैं कि यह reply कल होगा। इसका मतलब क्या है?

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, इसका मतलब यह नहीं है, मतलब यह है कि Sir, he is ready to reply, but he wants more time, may be one-and-a-half to two hours. *...(Interruptions)...*

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, यह किसानों का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, इसलिए इसमें सरकार और विपक्ष की बात नहीं है। हम सब कृषि मंत्री का जवाब सुनना चाहते हैं। पिछली दफा भी इनका जवाब ऐसे ही रह गया था। अब पहले ही 6.00 बज चुके हैं। सर, आधे से ज्यादा सदस्य 2/3 तो बाहर हैं और अभी यहां 1/5 हैं। यह reply जितना ज्यादा लम्बा होता

जाएगा, उतने ही लोग और बाहर जाएंगे। मैं चाहूंगा इस दफा और पिछली दफा के भी जवाब को पूरा सदन भी सुने और पूरा देश भी सुने। बीच में सवाल-जवाब होते रहें, तो उस वक्त सदन के पूरे सदस्य मौजूद होने चाहिए। ऐसा तो सिर्फ कल दो बजे ही हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज बोलने का काम खत्म कर लिया जाए। तीन मिनट के बजाय पांच-पांच मिनट भी बोलें या छः मिनट भी बोलें, क्योंकि साल में एक-आधे दफा किसानों के बारे में चर्चा होती है, तो उस पर कोई अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है, न इस तरफ अंकुश लगाने की जरूरत है और न उस तरफ अंकुश लगाने की जरूरत है तथा कल दो बजे जवाब हो जाए, यही मेरा आप से अनुरोध है।

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** آنریبل ڈپٹی چیئرمین سر، یہ کسانوں کا مدعہ پورے دیش کا مدعہ ہے، اس لیے اس میں سرکار اور وپکش کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کرشی منتری کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ان کا جواب ایسے ہی رہ گیا تھا۔ اب پہلے ہی چھ بج چکے ہیں۔ سر، آدھے سے زیادہ ممبران 2/3 تو باہر ہیں ابھی یہاں 1/5 ہیں۔ یہ ریپلائی جتنا زیادہ لمبا ہوتا جائے گا، اتنےہی لوگ اور باہر جائیں گے۔میں چاہوں گا اس دفعہ اور پچھلی دفعہ کے بھی جواب کو پورا سدن بھی سنے اور پورا دیش بھی سنے۔ بیچ میں سوال جواب ہوتے رہیں، تو اس وقت سدن کے پورے سدسنیے موجود ہونے چاہیئں۔ ایسا تو صرف کل دو بجے ہی ہوسکتا ہے۔ اس لیے میرا نوینن ہے کہ آج بولنے کا کام ختم کرلیا جائے تین منٹ کےبجائے پانچ پانچ منٹ بھی بولیں یا چھ منٹ بھی بولیں، کیوں کہ سال میں ایک آدھ دفعہ کسانوں کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے، تو اس پر کوئی انکش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس طرف انکش لگانے کی ضرورت ہے اور نہ اس طرف انکش لگانے کی ضرورت ہے تتھا کل دو بجے جواب ہوجائے، یہی میری آپ سے گزارش ہے۔

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): सर, मैं भी यही चाहता हूं कि सभी लोगों को टाइम मिले। अब जो बोलने वाले रहते हैं, आप उनको दो-तीन मिनट का समय देंगे। हर एक सदस्य ने जो बात कहनी है, वह अपने हिसाब से कहनी है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 6.00 बज गए हैं, मिनिस्टर साहब भी और हम सब भी यही चाहते हैं, इसको कल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हाउस में संख्या बहुत कम है। हम कल फिर सात बजे तक बैठ जाएंगे। हम सब बैठकर बिल पास करेंगे, इसलिए यह ठीक होना चाहिए। इसको ऐसे न करें। यह तो सबसे बड़ा मसला है। इस देश में किसान और जवान ही तो सबसे बड़े हैं। एक दूसरे को गलत कहने से कुछ नहीं होगा। यह तो फिक्र की बात है, यह गलत कहने की बात नहीं है। देश में बहुत कुछ होने वाला है।

श्री उपसभापतिः इसका मतलब यह है कि कल होना है?

†Transliteration in Urdu script.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, आज यह भी हुआ था कि डिस्कशन होगा, reply होगा और उसके बाद हम बिल भी लेंगे। अगर चेयर और ऑनरेबल मेम्बर्स का यह मानना है कि कल reply करना चाहिए, तो I think three or four Members are left to speak. मुझे लगता है कि इसको नए मेम्बर्स से न जोड़ा जाए।

दूसरी चीज़ यह है कि हमारे दो बिल हैं, एक तो OBC बहुत important है, जो Select Committee को भेजा गया था और दूसरे बिल भी हैं, तो कल हमें उनको भी साथ में ही लेना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the remaining speakers are Shri Kashyap, Shri Balwinder Singh Bhunder. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः सर, मैं एक मीटिंग में भाग लेकर यहां 3.00 बजे आ जाऊंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You say, reply tomorrow at 3.00 p.m.?

SHRI RADHA MOHAN SINGH: Yes, Sir.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Also, Sir, we have already allotted one hour for the Collection of Statistics (Amendment) Bill. It is a very small Bill. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are only three more speakers. We will finish the discussion today and the reply will be tomorrow. ...*(Interruptions)*... Let us finish the discussion today. ...*(Interruptions)*...

SHRI K.K. RAGESH: Sir, if the Minister comes at 3 o'clock, we will have one hour from 2 o'clock to 3 o'clock. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, my suggestion is that from 2 o'clock to 3 o'clock, let the remaining speakers speak and from 3 o'clock to 4 o'clock, let the hon. Minister speak and 4 o'clock onwards, we will do the Bill Business. ...*(Interruptions)*... I don't understand why we are complicating a simple issue. From 2 o'clock to 3 o'clock, let all the Members complete and from 3 o'clock to 4 o'clock, let the Minister reply because the Minister requires an end point also. You are giving him the starting point. You have to indicate when he will have to stop. ...*(Interruptions)*... So, he stops at 4 o'clock and then you may take up the Bill after 4 o'clock. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Jairamji, the Chair has to consider all aspects. Firstly, the time for Short Duration Discussion is two-and-a-half hours but we have already taken four hours. That is one. Secondly, there is other Business also to be taken up. If you take the whole time for this Business tomorrow, then that is not fair because there is other Business also. That is my concern. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the challenge tomorrow will be for the Parliamentary Affairs Minister to restrict the Minister's reply. We are prepared to listen to him for three hours. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, we have three more speakers. We finish the discussion today and then the Minister replies tomorrow. I think that is okay.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः कल पर छोड़िए। आज तीन स्पीकर्स बचे हैं। दो-दो तीन-तीन मिनट का क्या मतलब है? हम भी उतना ही बोलना चाहते हैं, जितना बाकी लोग बोले हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take more time.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः इसको कल पर छोडिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आपको कितना टाइम चाहिए?

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः मिनिमम दस मिनट चाहिए।

श्री उपसभापतिः ठीक है, दस मिनट। Naqviji, tomorrow?

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, it is better कि रिमेनिंग स्पीकर्स बोल लें, कल रिप्लाई हो जाएगा। रिप्लाई तीन बजे और, Sir, reply at 3 o'clock and between 2 o'clock and 3 o'clock, we can take up the Collection of Statistics (Amendment) Bill. One hour is already allotted for it. ...**(व्यवधान)**...

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः जब रिप्लाई ही नहीं होगा तो who will sit here? Everybody will go. तीन स्पीकर्स अभी हो जाएंगे।

श्री उपसभापतिः रिप्लाई कल होने वाला है, रिप्लाई कल होगा। There are three speakers. We should finish them today. Mr. Kashyap; you have five minutes. ...*(Interruptions)*...

एक माननीय सदस्यः उपसभापति जी, यह बहुत बड़ा इश्यू है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खानः किसान भी बोलना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot add more speakers. That is against the rule. ...*(Interruptions)*... More names cannot be added. ...*(Interruptions)*...

कश्यप जी, आप बोलिए।

श्री राम कुमार कश्यपः उपसभापति जी, आपने अंत में मुझे आज ही बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज किसानों के लिए खेती करना एक घाटे का सौदा हो गया है। एक तरफ तो किसान को खाद, डीज़ल, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि दिन-प्रतिदिन महंगी मिल रही हैं, जिसके कारण किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं और किसानों के खर्चे किस कदर बढ़ गए हैं, मैं इसका एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पहले, जब किसान पशुओं के लिए चारा पैदा करता था, चाहे वह चरी हो, बरसीम हो या ज्वार हो, उस चारे को पैदा करने के लिए उसे कभी भी कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती थीं, परंतु आज समस्या इस कदर बढ़ गई है कि किसान को अपने पशुओं को चारा पैदा करने के लिए तीन बार कीटनाशक दवाइयां स्प्रे करना पड़ता है, जिसके कारण उसका खर्च बढ़ गया है, दूसरी तरफ, उसकी आमदनी घट गई है, क्योंकि उसे अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके कारण इस घाटे को, इस भरपाई को पूरा करने के लिए उसे साहूकार, आढ़ती व सरकारी बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसान का बेमौसम बारिश व सूखे की मार भी पड़ती है। जिसके कारण किसान कर्ज को वापिस नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी में किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। यह चिंता का विषय है कि देश में हर साल लगभग 12 हजार किसान आत्महत्या करते हैं। वर्ष 2013 में 11,772 किसानों ने आत्महत्या की, वर्ष 2014 में 12,360 किसानों ने आत्महत्या की, वर्ष 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की। किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, परन्तु इसका जो प्रमुख कारण मैं मानता हूं, वह किसानों के सिर पर कर्ज का बोझ होना है। यह हमारे लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए एक चिंता का विषय है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समस्या के निपटारे के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। दूसरा जो चिंता का विषय है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि आज किसानों के बच्चे, यानी युवा पीढ़ी का खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वे खेती नहीं करना चाहते हैं। किसानों के बच्चों को आज यह भी नहीं पता कि उनके पास कितनी जमीन है और खेतों में क्या पैदावार हुई है? इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना होगा। तीसरा जो चिंता का विषय है, वह यह है कि आज किसान जागरूक हो चुका है, उसको पता है कि कौन सा काम करने से उसका फायदा है और कौन सा काम करने में उसको घाटा है। आज के जागरूक किसान को यह पता लग चुका है कि उसको खेती करने में घाटा हो रहा है, इसलिए कुछ किसान खेती छोड़ कर शहरों में चले गए हैं। उन्होंने खेती करना छोड़ दिया है और उनकी जगह जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, वे जमीन को लीज़ पर लेकर, पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए, चालीस-चालीस हजार रुपए प्रति एकड़ जमीन को लीज़ पर लेकर खेती करते हैं। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा, तो किसान खेती करना छोड़ देंगे, तो फिर हमारे देश की हालत वही हो जाएगी जो 1960 में थी। फिर देश में अन्न की समस्या पैदा हो जाएगी और हमें अन्न दूसरे देशों से मंगवाना पड़ेगा।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)** *पीठासीन हुए*]

महोदय, इससे हमारी बहुत विदेशी मुद्रा भी खर्च होगी। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विषय को बहुत ही गंभीरता से ले जो कृषि की समस्या के सुधार के लिए मैं तीन-चार सुझाव देना चाहूंगा। एक तो जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां पर जितनी भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट्स की

पोस्टें हैं, वे सारी खाली पड़ी हैं, जिससे हमारा रिसर्च का काम प्रभावित हो रहा है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जितनी भी पोस्टें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में खाली पड़ी हैं, उनको भरने का काम करें, ताकि वे लोग रिसर्च करके किसानों के विकास के लिए काम करें और इसमें अपना अहम योगदान करें। दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं। इस समय हरियाणा में किसानों की एक बड़ी भारी समस्या है कि हरियाणा में आज किसानों के हजारों नए ट्यूबवेल के कनेक्शन की एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं। हरियाणा के कई जिलों को ड्राइ ज़ोन घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को नए बिजली के ट्यूबवैल कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मैं सरकार की इस बात से सहमत हूँ कि हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, परन्तु वाटर लेवल नीचे चला गया तो किसान को नए ट्यूबवेल कनेक्शन न देना, यह समस्या का हल नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितने भी ऐसे केस पेंडिंग पड़े हैं, उनको जल्दी से जल्दी ट्यूबवैल कनेक्शन मिले, ताकि किसान को सिंचाई की सुविधा मिले और खेती में काम करके किसान आत्मनिर्भर हों और देश के लिए भी योगदान कर सकें। तीसरा, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, चाहे वह टमाटर की फसल हो, चाहे मटर की फसल हो, चाहे प्याज की फसल हो, चाहे अन्य फसल हो। देखने में क्या आता है कि किसान की जिस फसल के ज्यादा भाव मिल जाते हैं, किसान अगले साल उसी को ज्यादा मात्रा में पैदा कर लेते हैं और फिर होता यह है कि उस साल उसकी मांग उतनी न होने से उसे उचित रेट नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सरकार ऐसी कोई व्यवस्था बनाए कि जब किसान कोई फसल पैदा करे तो किसान को पता हो कि उसका कितना रेट उसे मिलेगा और उतना रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा बताना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसका ज्ञान न होने के कारण उसे टमाटर, प्याज, मटर को सस्ते भाव में बेचना पड़ता है। तो इसको रोका जाए। मेरे यही तीन-चार सुझाव थे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री आनन्द भास्कर रापोलू (तेलंगाना): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, महानुभाव, आपकी इतनी कृपा हुई कि आपने मुझे थोड़ा बोलने का मौका दिया। यह मुद्दा देश में कृषि क्षेत्र में पैदा हुए संकट के बारे में है। अभी हमारे प्रधान मंत्री बहुत उदार होकर गुजरात पुत्र होने के नाते गुजरात गए हैं और वहाँ बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए उड़ान भर रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर पूरे गुजरात में जहाँ-जहाँ बाढ़ का प्रभाव है, वे उन सबका अंदाज़ा ले रहे हैं। इस मौके पर मुझे प्रधान मंत्री की दो-तीन घटनाएँ याद आ रही हैं। उनमें से एक यह है कि साउथ इंडिया के कुछ कृषकों ने पूरे भारतवर्ष का ध्यान आकृष्ट किया है, जो तमिलनाडु से आए हैं। वे कृषक हरे रंग के कपड़े पहन कर जंतर-मंतर पर अर्धनग्न अवस्था में बैठे हैं। अगर आजकल के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाए कि खेतीबाड़ी करने वाले किसान कैसे होते हैं, तो उनको जंतर-मंतर पर हरे रंग के कपड़े पहन कर अर्धनग्न बैठने वाले जो किसान हैं, उनको दिखा कर बताना पड़ेगा कि वैसे होते हैं। इस प्रकार का माहौल बन गया है और इस प्रकार का उनका परिचय हो गया है, मगर अभी तक प्रधान मंत्री का उन लोगों को बुला कर एक मिनट बात करने का मन नहीं हुआ है। मगर प्रधान मंत्री बहुत दयालु हैं। जब श्रीलंका में बाढ़ आई थी, तो उन्होंने फौरन संदेश दिया। साथ ही साथ वहाँ की दिक्कत हल करने के लिए भारत की तरफ से रिलीफ भी भिजवाई। जब पाकिस्तान में बाढ़ आई, तो उस बाढ़ के संकट में घिरी पाकिस्तान की जनता की तरफ आपका ध्यान देते हुए उन लोगों को सहारा देने के लिए और मदद देने के लिए

[श्री आनन्द भास्कर रापोलू]

उन्होंने वहाँ के प्रधान मंत्री से भी अनुरोध किया और अपनी संवेदना भी व्यक्त की। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, मिजोरम और त्रिपुरा तक जहाँ भी देखिए, बाढ़ आई थी। जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में वहाँ बाढ़ आई, तब वहाँ की जनता बाट देख रही थी कि कभी हमारे पंत प्रधान उड़ान भर कर हमारी विकट स्थिति देख कर जाएँ, मगर कुछ भी नहीं हुआ और उनके ट्विटर से संवेदना का एक ट्वीट निकला। प्रधान मंत्री की तरफ से ऐसा होता रहता है। ऐसी स्थिति में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2015 में तमिलनाडु में चेन्नई में बाढ़ का बहुत बड़ा संकट आया था, तब पंत प्रधान ने वहाँ जाकर उसे देखा भी और संवेदना भी व्यक्त की। उसके बाद उनकी डिजिटल टीम, ट्विटर टीम और वेबसाइट पर काम करने वाली टीम ने उनकी फोटो को वेबसाइट पर डाला, जिसमें यह दिखाया गया कि पंत प्रधान बाढ़ के पानी को देखने के लिए चल रहे हैं और उस संकट को देख रहे हैं। वह फोटो मार्क करके, फोटो शॉपिंग करके, जिसमें पंत प्रधान सीधे-सीधे जनता को देख रहे हैं, उस तरह की एक तस्वीर वेबसाइट पर, ट्विटर पर, उनके खुद के ट्विटर पर लगाने की वजह से पूरे विश्व के मीडिया चैनल्स, न्यूज एजेंसीज़, जिनमें राइटर्स हैं, एपीआई है, इसके साथ ही साथ बाहर वाली international dailies, Independent, Guardians वगैरह ने पंत प्रधान के इस photo shopping के शौक के बारे में बताया कि बाढ़ में भी इनको photo shopping का शौक है। ऐसा कह कर गालियाँ देने की वजह से फौरन वेबसाइट और ट्विटर से उनका फोटो निकालना पड़ा। ऐसी स्थिति हो गई है। 2014 में जम्मू-कश्मीर में बाढ़ आई थी। आज के दिन भी जम्मू-कश्मीर की जनता याद करती है कि उस बाढ़ के संकट की वजह से उन लोगों को कितना दुःख हुआ। उसे देखने के लिए भी पंत प्रधान गए थे। मगर कितना इंतजाम करना है, कितनी रिलीफ देनी है, कितनी मदद करनी है, आज के दिन भी उसका अंदाज़ा नहीं है। अभी गुजरात से लेकर असम तक के क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, मगर हमारा दक्षिण का अधिकतर भाग जिसमें तमिलनाडु भी है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त है। सूखाग्रस्त होने के कारण उस क्षेत्र की जनता मर रही है। इसी बीच हमारे तेलंगाना की स्थिति भी बहुत खराब हुई। इस बारे में भी मंत्री जी को बताया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे तेलंगाना में मिर्ची और हल्दी की स्थिति बहुत खराब हो गई। आपने मिर्ची और हल्दी को सरकारी माध्यमों से खरीदने का आश्वासन देते हुए ऐलान भी किया था, किन्तु वह ऐलान केवल ऐलान ही रह गया। जहां और जिन क्षेत्रों में ये चीज़ें खरीदी जानी चाहिए थीं, वहां नहीं खरीदी गईं। आपके ऐलान और आश्वासन का कोई फायदा वहां के लोगों को नहीं मिला।

महोदय, मुझे मालूम है कि मुझे ज्यादा समय बोलने के लिए नहीं दिया जाएगा और मैं यह भी जानता हूं कि अभी उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह देंगे। मुझे मालूम है कि मुझे अभी हमारे सभाध्यक्ष महोदय टाइम करने वाले हैं, मगर मुझे चन्द बातें इस सदन में कहनी बहुत जरूरी हैं, जिन्हें आपके माध्यम से मैं इस सभा में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे थोड़ी देर बोलने का और मौका दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तो अपनी बात शुरू भी नहीं की है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): नहीं-नहीं। कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री आनंद भास्कर रापोलू: महोदय, जो मैं बोल रहा हूं, यह मेरे क्षेत्र के लोगों की वेदना है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों की संवेदना व्यक्त कर रहा हूं। मैं कोई जान बूझकर आपका समय केवल औपचारिक या परम्परा के रुप में बातें कह कर समाप्त नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं। पिछली बार जब इस बारे में चर्चा हुई थी, तो हमें कृषि मंत्री का जवाब भी नहीं मिला था। सरकार द्वारा यदि कृषि क्षेत्र की इसी प्रकार अनदेखी की जाएगी, तो देश की कृषि का भविष्य क्या होगा, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, let me speak a little more on it. When we got independence, 75 per cent of the population was dependent on agriculture.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude in one sentence.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: And their contribution to the GDP was 61 per cent. If we take the latest data into consideration, 58 per cent of the population is dependent on agriculture. But their contribution to the GDP is only 19 per cent. Why has this gap occurred? And now we are thinking that the agriculturists and farmers would become entrepreneurs. Are we really going ahead? We are not at all going ahead. You intend to double the income of the agriculturists by 2022. Is it possible within five years? Former Chairman of the Commission for Agricultural Costs and Prices said that this would be the miracle of miracles if we can double their income.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Bhaskarji, please conclude. I am calling the next speaker. Sardar Balwinder Singh Bhunder. ...*(Interruptions)*... Please conclude in one sentence.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Let me conclude. ...*(Interruptions)*... Why are you calling the next speaker when I have not concluded?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You were given three minutes. आपका समय समाप्त हो चुका है। आप डबल टाइम ले चुके हैं। कृपया अब आप बैठ जाइए।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Then I will sit down. I am making a plea. I am making an observation. ...*(Interruptions)*... I am making a pertinent point. I am supporting the initiative of the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: The Congress Vice-President has advocated in the situation of merging of the General Budget and the Railway Budget. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): I am bound by time-limit. Please conclude.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: He has advocated a separate comprehensive agricultural budget. Please think about a separate agricultural budget which will have irrigation, cooperation, food processing and agriculture into it. This would help you in envisaging certain projects, programmes and policies. Then you can expect to double the income of the farmers.

In Telangana, the Telangana Government intends to have an agricultural budget from the next year. Kindly envisage this to alleviate the suffering of the farmers. Then you can look towards "per drop, more crop" and you can at least plan to double the income of the farmers. Then alone will it be possible. Otherwise, you will only be dreaming. Let us not dream about the miracle of miracles. Let us be realistic in addressing the problems of the farming community. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापति *(पीठासीन हुए)*

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर : ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, आज किसानी पर सारा हाउस बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रहा है। मैं भी उसी पर बात कर रहा हूँ। न तो मैं इधर की बात करता हूँ और न ही मैं उधर की बात करता हूँ। मुश्किल यह है कि जब ये सीट्स उधर चली जाती हैं, तो आवाज़ कुछ और हो जाती है और जब वे सीट्स इधर आ जाती हैं, तो आवाज़ कुछ और हो जाती है। लेकिन, किसान की किस्मत बदलने के लिए हम एक आवाज़ नहीं हुए। हम एक-दूसरे को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने चंगा किया, मैंने चंगा किया। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ, तो इस देश में 80 परसेंट किसानी थी, लेकिन अब हम 60 परसेंट पर आ गये हैं, क्योंकि अब 60 परसेंट लोग खेती करते हैं। जब यहाँ अंग्रेज़ थे, तो हमारे पंजाब में जो मूवमेंट चल रही थी, जोकि देश भर में चल रही थी, तो सरदार भगत सिंह के जो ग्रैंड फादर या उनके अंकल किशन सिंह जी थे, वे कविता गाते थे। वे कहते थे- "पगड़ी सम्भाल जट्टा, पगड़ी सम्भाल ओए। लुट लया माल तेरा, लुट लया माल ओए।" पगड़ी का मतलब हमारी respect है। अब भी वही बात है। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन "पगड़ी सम्भाल' कहने के बजाय मेरे ख्याल में हमें यह कहना चाहिए कि "जिन्दगी सम्भाल जट्टा, जिन्दगी सम्भाल ओए। लुट लया माल तेरा, लुट लया माल ओए।" तब तो पगड़ी का सवाल था, respect का सवाल था, लेकिन अब दो जिन्दगी का सवाल पैदा हो गया है। प्वाइंट तो यह है कि यह सवाल क्यों पैदा हुआ? हम कहते हैं कि हमने ठीक किया, हमने ठीक किया, मैं तो किसी को

नहीं कहता कि किसी ने बुरा किया। लेकिन, बात यह है कि आज 70 साल बाद, पहली दफा यह हो रहा है कि अगर आप साउथ में जाइए, तो जहाँ माल्टा पैदा होता था, शुगर पैदा होती थी, वहाँ भी खुदकुशी हो रही है और इधार पंजाब है, जो कि किसानी में टॉप का स्टेट है, वहाँ भी खुदकुशियाँ हो रही हैं। यह जो सरकार हमारे पंजाब में आई है, इसे आये तो 120 दिन हो गये, लेकिन खुदकुशियाँ 150 हो गयी हैं। इससे आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किसान की हालत क्या है। अब बातें करने से तो बात सुधरती नहीं, यह सोचिए कि ये हालात क्यों पैदा हुए? मैं सुन रहा था, जब ऑनरेबल सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर, दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे। वे बड़ी अच्छी तरह बोल रहे थे। इन्होंने एक बात कही कि आप इम्पोर्ट तब कर रहे हैं, जब किसान को जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप हो रही है। मैं आपको, किसी को दोष नहीं देता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या इम्पोर्ट आज ही हो रहा है? इम्पोर्ट तो पहले भी हो रहा थी। जब हमारे पास अनाज होता था, तब भी हम इम्पोर्ट करते थे। हम सिर्फ इम्पोर्ट ही नहीं करते थे, जब हमारे पास सरप्लस हो जाता था, हम एक्सपोर्ट करने के लिए बैन कर देते थे। इससे भी बड़ी ज्यादती किसान के साथ और क्या हो सकती थी? तब अकेले पंजाब में किसान surplus production करता था और थोड़ा-सा हरियाणा करता था। जब देश में हमारी कनक के रेट अच्छे हो जाते थे, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, तो आपके समय में इंटर स्टेट बैन हो जाता था। किसान के साथ इससे भी बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है कि जब उसको प्राइस मिलता है, इंटरनेशनल प्राइस अप होता है, तब भी हम एक्सपोर्ट बन्द करते हैं और इंटरनल प्राइस अप होता है, तो हम इंटर स्टेट बंद कर देते हैं! अगर हमारे यहाँ कमी आ जाती है या सरप्लस हो जाती है, तो हम किसान की हेल्प नहीं करते। इसलिए अब नहीं, शुरू से ही किसान की एंटी पॉलिसी चल रही है। हमारा जो कमीशन है, वह प्राइस ...(**व्यवधान**)... वही मैंने इंटर स्टेट बोला। ...(**व्यवधान**)... शायद जिलाबंदी भी थी, लेकिन इंटर स्टेट का मुझे पता है। हमारा जो किसान है, उसके साथ इससे भी बड़ी जो ज्यादती हो रही है, वह यह है कि हमने पिछली बार ओनियन का मामला देखा, उसका रेट पिछले साल 100 रुपये प्रति किलो चला गया था, तब उसका एक्सपोर्ट बन्द कर दिया गया और कहा गया कि अब यह हो नहीं सकता है। इससे किसान को नुकसान हुआ। अब किसान का प्याज खराब हो रहा है, तो सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। यही हाल पिछली बार पोटैटो का भी हुआ और अब भी यही हाल है। टमाटर का हाल भी पिछली बार यही हुआ, अब भी यही हाल है। इसी तरह, बासमती की डिमांड आई, तो पिछली साल बासमती बरबाद हो गई, किसान फिर बरबाद हो गया। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर असम में जाओ और चाय वाले को देखो, तो चाय वाला रो रहा है। यानी, जो फार्मर टी पैदा कर रहा है, वह भी रो रहा है। कोई फार्मर देश में सुखी नहीं है, सभी फार्मर्स दुखी हैं। इसका कारण क्या है? कारण देश की नीति है। जो नीतियाँ हैं, वे किसान के पक्ष में नहीं हैं। चूंकि टाइम कम है, इसलिए अब मैं ज्यादा न बोलकर कुछ सुझाव दूंगा।

आज जो बात हो रही है कि तीन साल में हम गवर्नमेंट से हिसाब पूछते हैं, मैं नहीं कहता, अब भी प्रॉब्लम वही है, लेकिन जो 30 साल पहले करने वाले थे, क्या करने वाले थे? आज देश में कितना अनाज बरबाद होता है? इसके बारे में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए के foodgrains, vegetables and fruits बरबाद हो जाते हैं। इसके लिए आपको कोई सोच क्यों नहीं है कि देश में फूड पार्क बने, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम लगे, कोल्ड चेन बने तथा बड़े-बड़े गोदाम बने। यह 30 साल पहले होना चाहिए था। अगर 30 साल पहले बड़े-बड़े गोदाम बन जाते, तो फूड ग्रेन्स की इतनी

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

वेस्टेज क्यों होती? अगर उस समय ही कोल्ड चेन बन जाती, तो जो कहीं पोटैटो रोता है, कहीं टमाटर रोता है, कहीं ओनियन रोता है, वह जहां कमी है, वहां चला जाता। कुछ दिन पहले टमाटर रो रहा था और अभी टमाटर 80 रुपए प्रति किलो है। जो बातें सरकार अब कर रही हैं, कोशिश कर रही है... मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ सॉल्व हो गया, इतनी देर में सब कुछ हो सकता था, यहां बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि देश में प्रॉब्लम क्या है? आज देश में दो ही प्रॉब्लम्स हैं- एक किसान और दूसरा जवान, जो बेरोजगार है। बच्चे भी बेरोजगार हो गए, लैण्ड होल्डिंग कम हो गई, इनपुट्स की प्राइस बहुत बढ़ गई और जब मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाता है... जो कमिशन मिनिमम प्राइस फिक्स करता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से यह हिदायत दी जाती है कि आप जो मिनिमम प्राइस फिक्स करेंगे, वह इस तरह फिक्स करेंगे कि उसका मार्केट पर affect न पड़े। अगर ट्रैक्टर महंगा होता है, सीमेंट महंगा होता है, कपड़ा महंगा होता है, चाहे और कोई चीज़ महंगी होती है, तब कोई affect नहीं पड़ता है। किसान कंज्यूमर भी है, किसान प्रोड्यूसर भी है।

डिप्टी चेयरमैन साहब, दुनिया में प्रोड्यूसर कभी भी फायदे में नहीं रहा है, ट्रेडर फायदे में रहता है। प्रोड्यूसर को दो मार पड़ती है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के रूप में पड़ती है और प्रोड्यूसर के रूप में भी मार पड़ती है। जब टमाटर का रेट 80 रुपए प्रति किलो होगा, तब वह भी लेगा और जब किसान टमाटर को सड़क पर फेंकता है, जब भी किसान रोता है। इस तरह से दोनों तरफ से किसान रोता है। यह भी कहा जाता है कि आपने जीएसटी लगा दिया, लेकिन पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। मैं यह सुन कर हैरान हूँ। क्या किसान पर कोई टैक्स नहीं है। किसान जो भी सामान खरीदता है, उस पर टैक्स देता है। किसान को उसकी पैदावार की उचित कीमत मिलती नहीं है, लेकिन जब वह कोई चीज़ खरीदने जाता है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिस पर टैक्स नहीं है। किसान हर चीज़ पर इनडायरेक्ट टैक्स देता है और सबसे ज्यादा देता है। अब और दुख की बात यह हो गई कि जीएसटी भी लगा दिया, जिसके तहत यह 5 परसेंट से 28 परसेंट तक चला गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस जीएसटी को रोकिए।

डिप्टी चेयरमैन साहब, किसान को तो बहुत तरह का टैक्स देना पड़ता है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। एफसीआई wheat परचेज़ करती है, अगर एफसीआई एक किलो wheat का एक रुपया देती है, जब वह उसको स्टोर पर ले जाती है और फिर मार्केट में लाती है, तो वह तीन रुपए प्रति किलो पड़ता है। इस प्रकार से उस पर दो रुपए एक्स्ट्रा हो गये। वह दो रुपए किसके गए? अगर वह दो रुपए उधर न जाते, एक ही रुपया जाता, तो किसान के पास एक रुपया और आ सकता था। ये जो मिडिल मैन हैं, ट्रेडर्स हैं, ये किसान को तब भी अंग्रेज़ की तरह लूट रहे थे और अब भी लूट रहे हैं।

मैं हैरान हूं कि सरकार की पॉलिसी कौन लोग बनाते हैं। जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि किसानी क्या है, किसानी करने वाला कैसे रो रहा है, किसानों की तकलीफ का किसी को पता नहीं है। किसानों के सामने जो दो साल बाद या तीन साल बाद वैदर की प्रॉब्लम आती है, कहीं हिल स्टॉर्म आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं फ्लड आ गयी, यह जो मार पड़ती है, इसमें जो उसकी फसल खराब होती है, उसका मुआवजा कौन देता है? मेरा यह कहना है कि उसका भी मुआवजा देना चाहिए। किसान की जो किस्मत है, उसके बारे में मेरे पहले भी डी. राजा जी ने बोला है कि किसान

कर्ज में जन्मता है, कर्जे में रहता है और कर्जे में मरता है। उसका कारण है। हमारे मुल्क में किसान की ऐसी हालत है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में जो किसान खेती करता है, वहां की सरकार किसान को बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, तभी वहां के किसान जिन्दा रहते हैं। वहां की गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप सरकार से हेल्प लीजिए और खेती कीजिए। वहां लैंड भी है और गवर्नमेंट हेल्प भी करती है, लेकिन हमारे पास लैण्ड भी नहीं है, इरिगेशन सिस्टम भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी नहीं है। यहां पर किसान को कोई चीज़ पूरी मिलती नहीं है, जो वह चाहता है, लेकिन इसके बाद भी वह खेती करता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, यह उसकी मजबूरी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी को दोष देने की बजाय, मैं इधर वाले से भी कहना चाहता हूं उधर वाले से भी कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग इकट्ठे होकर इसके बारे में सोचें। अगर किसान को समझ आ गई... किसान में एकता नहीं है, यह किसान की बदकिस्मती है। ...**(समय की घंटी)**... किसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः आप और हम तो भूख हड़ताल करते हैं, मुलाजिम भी भूख हड़ताल करता है, कोई टंकी पर चढ़ता है। मैं किसानों से विनती करता हूं कि एकता कीजिए, खेती की भूख-हड़ताल कीजिए। आप रेट भले ही one-third कर दीजिए, अगर किसानों ने एकता कर ली तो सरकार को उनकी मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि आइए, खेती कीजिए, हम आपको रेट ठीक देंगे। आज बदकिस्मती है कि किसानों में एकता नहीं। वह रोता है, खुदकुशी करता है और हम उसे देखते रहते हैं। यहां बोलकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को seriously बिल्कुल नहीं लेते।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे हालात आज चल रहे हैं, उससे देश में क्रांति आने का खतरा है। आज देश में क्यों Naxalite Movement चल रही है? क्यों जगह-जगह लोग टंकियों पर चढ़ रहे हैं? क्यों देश की हर स्टेट में किसान बगावत पर उतारु हैं? यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। अगर इस देश से अंग्रेज चले गए, तो हम भी कोई बड़े लोग नहीं हैं। इसलिए खतरनाक क्रांति आ सकती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...*(Time-bell rings)*...

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः उसे रोकने के लिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, सिर्फ request करता हूं कि आप देश के किसान को बचाइए। अगर किसान ऐसे ही समस्याग्रस्त रहे, तो देश आगे बढ़ नहीं सकेगा और देश का नुकसान होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Members, I have requests from three more Members. I am allowing them three minutes each. ...*(Interruptions)*.... Now, listen. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI CHHAYA VERMA (Chhattisgarh): Sir, आप मुझे एक मिनट ही दे दीजिए। ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You don't allow me to speak! ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... Don't you know I am speaking? Allow me to say something. ...*(Interruptions)*... I said that I have three more requests. I am allowing them three minutes each. Number one is Shrimati Chhaya Verma; number two is Shri La. Ganesan and number three is Shri VP. Nishad; then, after these three, the discussion is over and then, we will take up the Special Mentions. The reply is tomorrow at 3.00 p.m.; from 3.00 p.m. to 4.00 p.m., one hour. It is limited to one hour, so the Minister has to manage within one hour. From 2.00 p.m. to 3.00 p.m., we will take up the Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017. It is a one-hour Bill. It is only a technical Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, one hour is not enough for the Minister because he has not replied the last time also. So, give him some more time as one hour is not enough.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. ...*(Interruptions)*... I only gave a suggestion. ...*(Interruptions)*... Jairamji, what I said is only a suggestion, okay.

श्री राधा मोहन सिंहः उसमें कोई समय-सीमा नहीं रहेगी। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, guidance to the Minister. ...*(Interruptions)*... Now, Shrimati Chhaya Verma.

श्रीमती छाया वर्माः समय देने के लिए, उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अंतिम वक्ता ही सही, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी पार्टी के कालिता जी और गुलाम नबी आज़ाद साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी। सदन में 2.00 बजे से इस विषय पर discussion चल रहा है। मैं यहां पुरानी बातों को न दोहराते हुए, सिर्फ अपनी बात रखना चाहूंगी।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश)**:** इसी बात पर इन्हें दो मिनट और देने चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

[उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया) *पीठासीन हुए]*

श्रीमती छाया वर्माः महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की समस्याओं पर तीन मिनट में मुझे यहां बोलना है। इस देश में कृषि ही किसानों की शक्ति है, उनकी भक्ति है, उनकी निद्रा है और उनका जागरण है, लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसानों की जो दुर्दशा आज भारत में है, वह किसी से छिपी नहीं है। आपने देश में GST लागू किया। उसमें BMW गाड़ी की कीमत कम कर दी, लेकिन tractor जो किसानों का औजार है, उसकी कीमत आपने बढ़ा दी। ऐसे ही, किर्लोस्कर पम्प, जो खेती में काम आता है, उसकी कीमत आपने GST में कम कर दी, लेकिन किर्लोस्कर कम्पनी वालों ने उसके रेट बढ़ा दिए। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। किसानों की हालत और खराब हुई। यूरिया खुले मार्केट में कम रेट पर मिलता है, लेकिन society में उसी खाद

कीकीमत,चाहेयूरियाहोयाग्रो-मोरहो,काफीअधिकरहतीहै।किसानपढ़ा-लिखानहोनेकेकारण society की दुकान में जाता है और बोलता है कि मुझे एक बोरी फलां खाद दे दो और खाद लेकर चला जाता है। जब किसान खरीदने जाता है, तो उसे खाद की कीमत पता नहीं होती और वह पूछता भी नहीं। खुले मार्केट में उसी खाद की कीमत काफी कम है।

यहां सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने स्टेट की बात की है, मैं भी अपने राज्य छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगी। विधान सभा चुनाव के ठीक पहले वहां के मुख्य मंत्री ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि मैं किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदूंगा, समर्थन मूल्य पर खरीदूंगा और 300 रुपए बोनस भी दूंगा। सारे किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और चुनाव के बाद से आज तक चार साल बीत गए, लेकिन किसानों को न तो उनके धान का समर्थन मूल्य मिला, न बोनस मिला और न उनके धान का एक-एक दाना खरीदा गया। आज वहाँ कि किसान अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। किसी जमाने में छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता था, लेकिन आज वहाँ पर धान नहीं है, किसानों के पास केवल कटोरा रह गया है। वहाँ पर एक साल में 954 किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। सर, भारत के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था, वह अब जाकर हुआ। वहाँ के कुरुद गाँव का एक किसान, जिसकी चार बेटियाँ थीं, उसने जब आत्महत्या की, तो पुलिस वहाँ पूछताछ करने गई। पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछा - क्या आपके घर में लड़ाई-झगड़ा होता था? सर, लड़ाई-झगड़ा किसके घर में नहीं होता। उसकी पत्नी ने कहा - हाँ, कभी-कभी मनमुटाव हो जाता था। जब उससे पूछा गया कि आपके पति कभी दारू पीते थे, तो उस पर उसने जवाब दिया नहीं, वे नहीं पीते थे, कभी-कभार पी लेते थे। उसके बाद, दूसरे दिन अखबार में बड़े-बड़े अक्षरों में यह छप गया कि इसके घर में आपस में मनमुटाव था, झगड़ा होता था, इसलिए दारू पीकर इसने स्यूसाइड कर लिया। इसका मतलब यह था कि सरकार को उसे मुआवजा न देना पड़े, इसलिए उसके बारे में गलत बात सामने रखी गई। उसके घर में शासन का एक भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं गया, बल्कि पुलिस उसके घर के लोगों को प्रताड़ित करती रही। सर, वहाँ पर जिन 954 किसानों ने स्यूसाइड किया है, उनमें से अधिकांश इसी तरह से प्रताड़ित होते रहे हैं। वहाँ के किसानों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। वहाँ के किसान बहुत ही विषम परिस्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं।

अभी मंत्री जी बोल रहे थे कि हम वहाँ पानी दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग लगे और नदी का पानी उन उद्योगों तथा उद्योगपतियों को जा रहा है, जबकि किसानों को दो फसल तो क्या, एक फसल के लिए भी सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ के किसानों की हालत बहुत खराब है। सर, मैं बस यह कहना चाहूँगी कि भारत में अगर हमारे भारत के किसान खुशहाल नहीं रहेंगे, तो हमारा भारत संपन्न नहीं हो सकेगा, हमारे भारत के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri La. Ganesan.

SHRI LA. GANESAN (Madhya Pradesh): Respected Vice-Chairman, Sir, when the saintly poet Vishwakavi Thiruvalluvar can express the glory of kisans in two lines, I can

[Shri La. Ganesan]

very well put forth my points in three minutes. I have to share some information. Why are the *kisans* indebted? The reason is, according to National Sample Survey Organisation, the average amount of outstanding loan per agriculture household is ₹ 47,000 while the income is ₹ 77,000 only. Practically, two-thirds of the income of the *kisans,* on an average, according to the survey, goes for the debt. This is the situation prevailing. It is a very serious thing. Actually, the people from South should get more time to talk about that because among the indebted farmers, the highest number is from Andhra Pradesh, followed by Telangana. Surprisingly Tamil Nadu comes on the third position with 82.5 per cent. The average amount of outstanding loan is highest for Kerala. Compared to other States, the Southern States are suffering more. Though there are other reasons for suicides, the suicides cannot be ignored because according to the survey, around 60 per cent of the suicides are clearly for farming-related issues, bankruptcy or indebtedness. It is very clear. That is why suicide is a very important matter. Our hon. Minister has also mentioned that simply a loan waiver cannot solve the problem and I also agree with him. For that what I want to say is, kisans are getting loans not only from official institutions like banks and other bodies, but they are getting credit from non-institutional sources also. That is more important here. Though they are getting only 25.8 per cent of the loan from non-institutional sources—it is difficult for kisans to repay them. It is easy to repay to the banks, because the interest rates are comparatively lower. But, from money lenders, they are being harassed. The interest rate is more. The kisan is not able to repay, and the sufferings are more because of the non-institutional sources like moneylenders. This is an important aspect that we need to take note of.

Then, as the hon. Minister has rightly said, we have taken steps. The Government of India, especially the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has taken steps in this regard. Firstly, agricultural credit flow has considerably increased over the years. Secondly, you have the kisan credit card system; thirdly, with a view to ensuring availability of agricultural credit at reduced interest rate of seven per cent per annum to the farmer, the Government of India has initiated an interest subvention scheme for short-term crop loans up to rupees three lakhs. Under this scheme, an additional subvention of three per cent is given to those farmers who would repay their short-term crop loan in time, thereby reducing the effective rate of interest to four per cent per annum for such farmers. This is one of the important points that I wanted to mention.

Sir, according to statistics available, in 2007, when UPA Government waived the

loan, for 30 million farmers in 18 States 16,379 committed suicide. As he rightly put it, later. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: What is this? ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: What is he talking? ...*(Interruptions)*...

SHRI LA. GANESAN: Sir, I am only quoting statistics given by the survey. You may deny it later. ...*(Interruptions)*... Allow me to speak. I have been given just three minutes. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंहः सोर्स तो बतला दें, इनको जानकारी कहां से मिलेगी। **...(व्यवधान)...**

श्री भुवनेश्वर कालिताः व्यवस्था का प्रश्न है। **...(व्यवधान)...**

SHRI LA. GANESAN: Later, in 2009, even in Maharashtra... ...*(Interruptions)*... Mr. Vice-Chairman, Sir, you have given me only three minutes. I don't wish to yield to anybody. Please allow me to speak for three minutes. If you want, you could give them a chance to speak later. I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI LA. GANESAN: Sir, in 2007, in Maharashtra alone, 4,238 persons had committed suicide. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI LA. GANESAN: The figures clearly show that. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the hon. Member has to take the House into confidence and disclose his source of information.

SHRI LA. GANESAN: I got these statistics from the Parliament Secretariat only. If you want, you could also go and get them. ...*(Interruptions)*... I am not prepared to answer to them. I wish to conclude. I would conclude it within two minutes. Later, you can ask him to speak. I have no problem with that. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): He is not yielding. ...*(Interruptions)*... You may speak now. Please go on. You have little time left.

SHRI LA. GANESAN: Sir, our respectable colleague from Tamil Nadu said that banks were harassing farmers. I agree with him. But the Government of India, through the Reserve Bank of India, has issued guidelines for relief measures by banks in areas affected by natural calamities, like Thanjavur in Tamil Nadu, from where I have come. Through a Circular dated 21st August, 2015, the State-level bankers committee, district-level committees, the banks were directed to take a view on rescheduling of loans, if the crop loss was 30 per cent or more. Banks have been advised to allow maximum period of repayment up to two years and, in some cases, if necessary, up to a maximum of five years. Already, banks have been instructed. This is an information that I wanted to share from the Government side.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude.

SHRI LA. GANESAN: Finally, indebtedness.....*(Interruptions)*... Indebtedness has somehow existed for centuries.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, banks have been harassing farmers despite instructions having been issued. ...*(Interruptions)*...

SHRI LA. GANESAN: Sir, I agree with my colleague from the DMK that banks are harassing people. But, at the same time, I have talked about instructions that my Government has given to banks. I agree with you. But as compared to banks, the harassment of farmers is more from the non-conventional, non-institutional financial institutions. To that extent, the Central Government cannot give instructions to them. That is the problem that needs to be addressed. The remedy I would suggest is the same. Indebtedness of one form or another has been in existence for centuries. That may, perhaps, not be the root cause of the present agrarian crisis. Measures like loan waivers can provide only a temporary relief, but long-term solutions are needed to solve farmers' woes. For that, the only solution is increasing the income of the farmers. For that, the Government is already making efforts. We have already declared that by 2022, income of farmers would be doubled. We are going to rule till 2022 and we are going to implement it. यह सत्य है, आप भी देख सकते हैं। I wanted to share this information with you. Finally, I would like to give one more suggestion. What is the outcome of the discussion? At least, I would like to make one prayer from my side. Forgetting about all political differences, in this Session, we will unanimously plead with the farmers; we will unanimously request the farmers, at least, hereafter, they should not indulge in suicide activity. We are here to save them; we are here to protect them. Why don't we give that promise to the farmers? Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी, आप तीन मिनट में समाप्त करिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किसानों की समस्याओं के कारण देश में हो रही आत्महत्याओं की वृद्धि पर अल्पकालिक चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जो किसान धरती को चीरकर अन्न पैदा करने का काम करता है, पूरे देश को खिलाने का काम करता है, आज उसकी ऐसी हालत है क्योंकि उनकी कोई यूनियन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, आज वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबके लिए गारंटी देते हैं - बीमा कम्पनियां, जो फसल का बीमा करती हैं, उन कम्पनियों को आपने घाटे के लिए गारंटी दे दी कि अगर उनका घाटा होगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, उसी प्रकार किसानों की जो उपज है, उसके न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करना चाहिए और उसके घाटे की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को लेनी चाहिए। महोदय, बुंदेलखंड के किसानों की समस्या के लिए मैंने 31 मार्च को एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय मंत्री जी को जवाब देना था, लेकिन समय समाप्त हो गया था। मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि बुंदेलखंड का किसान बहुत परेशान है, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां वर्षा आधारित कृषि होती है। वहां 62 लाख से ज्यादा किसान पलायन कर चुके हैं, वे प्रतिदिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, किसान क्यों परेशान हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, इस पर प्रधान मंत्री जी को और माननीय कृषि मत्री जी को चिंता करनी चाहिए और इसका समाधान ढूंढकर इस समस्या का निवारण करना चाहिए- इसीलिए हम आज खड़े हुए हैं।

मान्यवर, भारत में प्रति वर्ष लगभग 12,000 से अधिक किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। 2015 तक कुल 1,33,623 किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं - चाहे कर्णाटक हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखुड हो, छत्तीसगढ़ हो या आन्ध्र प्रदेश हो। मान्यवर, हमारे बुंदेलखंड में एक विशेष समस्या है अन्ना प्रथा। माननीय मंत्री जी फसल दुर्घटना बीमा लाए, लेकिन उसमें अन्ना प्रथा covered नहीं है। आपने agriculture में FDI को 100 प्रतिशत दे दिया है। अब जो बीज बाहर से आ रहा है, उसमें फल नहीं लग रहा है। उसकी गारंटी नहीं है, वह बीमा में covered नहीं है, अन्ना जानवर फसल को खत्म कर देते हैं, वह बीमा में covered नहीं है। मान्यवर, हमारे बुंदेलखंड में तिलहन में अलसी पैदा होती है, वह बीमा में covered नहीं है। इन सबको कवर किया जाना चाहिए।

महोदय, सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है, फिर क्या कारण है कि आज धरती चीरकर अनाज पैदा करने वाला किसान खुद मर रहा है। जब Food Security Act बन गया है और हम हर नागरिक को खाद्यान्न देने का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो जो किसान घाटे में खेती कर रहा है, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप नियम, कानून बनाइए, जिससे कि किसान आत्महत्या न कर सके।

मान्यवर, किसान के सामने दो-तीन समस्याएं हैं - एक तो मार्केटिंग है और दूसरा, उनके कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारण हो। अगर उनकी फसल को खेत से ही ले लिया जाए, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): चलिए अब आप पूरा करिए। आपके बोलने का समय पूरा हो गया है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : अगर उनकी फसल का निर्धारण हो जाए, तो इससे उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए ही मैंने माननीय उपसभापति जी से रिक्वेस्ट करके इस विषय पर बोलने के लिए समय मांगा था। मैंने 31 मार्च को एक संकल्प रखा था, उस पर माननीय मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन समय खत्म हो जाने के कारण वे बोल नहीं सके थे। मेरा निवेदन है कि जब माननीय मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर दें, तो मेरे संकल्प का भी उत्तर दे दें, धन्यवाद।

SPECIAL MENTIONS*

Demand to handover the responsibility of conducting the Common Law Admission Test (C.L.A.T.) to a professional body

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, every common entrance examination is expected to be conducted with utmost care and caution since career of students would be at stake. Entrance exams such as NEET, CAT, etc., are being conducted by professional bodies which gives little scope for any malpractice or mistake. But, when it comes to CLAT, it is the other way round. CLAT is an examination for admission into 18 National Law Universities in the country and this exam is conducted by one out of 18 NLUs every year on rotation basis since 2008. There is no doubt that National Law Universities have professionalism in teaching law, but lacks professionalism in conducting CLAT which resulted in leakage of question paper in 2009; question booklet in 2011 contained questions which had answers underlined, deviated from syllabus in 2012; erroneous ranks announced; questions plagiarized in 2015 from CLAT and website with erroneous questions, some Questions have more than one correct answer in 2017. This clearly indicates that since common test began in 2008, almost every year CLAT is mired in controversies and riddled with errors. With more than 50,000 students appearing for 2,175 seats in 18 NLUs, it indicates intensity of competition as this exam produces fearless advocates for the country.

In view of the above, it is important to conduct CLAT by a professional body. I strongly feel that Bar Council of India itself would be the best statutory body which is capable enough to conduct CLAT. Hence, I request the Government of India to entrust CLAT to Bar Council of India from next year.

---

*Laid on the Table.